16/5/96

हरियाणा विधान सभा

HVS/12

की

कार्यवाही

8 मार्च, 1995

खंड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

बुधवार, 8 मार्च, 1995

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
वाक आउट	(3) 6
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3) 6
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 26
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 29
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं/विभिन्न मामले उठाना	(3) 36
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— राज्य में यूरिया तथा डी0 ए0 पी0 खाद की कमी सम्बन्धी	(3) 38
वक्तव्य— कृषि मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(3) 41
मुख्य मन्त्री द्वारा घोषणा	(3) 59

मूल्य : 247 00

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 60
वाक आउट	(3) 61
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 63
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 86
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 87
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 94
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 94
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 97
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 97
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 100
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 100
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन	(3) 101
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 102
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)	(3) 102
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 103
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)	(3) 104
बैठक का समय बढ़ाना	(3) 105
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)	(3) 105
वाक आउट	(3) 106
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)	(3) 107

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

ERRATA

To

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 1, No. 3, dated the 8th March, 1995.

Read	For	Page	Line
निवेश	निवश	31	34
करें	कर	40	1
श्री अध्यक्ष	अधध्क्ष	53	14
प्रौटैक्ट	प्रौटैस्ट	56	9
145 रुपये	155 रुपये	58	9
रहे हैं	रहे	61	27
शब्द "रहा" से पहले "लग" न पढ़ा जाये		64	16
इनसिक्योरिटी	इन्सक्यारीटि	65	16
रावी-ब्यास का	रावी-ब्यास	65	30
भाखड़ा की	भाखड़ा	66	5
एस०वाई०एल०	एव०वाई०एल०	66	26
बढ़ेगा	बढ़गा	68	29
आपूर्ति	आपूर्ति	69	4
शब्द "भी" के बाद "है" न पढ़ा जाये		70	4
काम	नाम	73	16
सच	सचा	77	8
बताना	बनात	77	9
सैंस	सस	86	29
वाईडनिंग	वाईडगि	87	5
शूगर	शगर	91	16
शब्द "जैसी" के बाद "नहरों" में न पढ़ा जाये		98	13
रिपोर्ट	रिपोट	98	18
दर्ज	दज	98	18
इजाजत	इजाजज	104	14

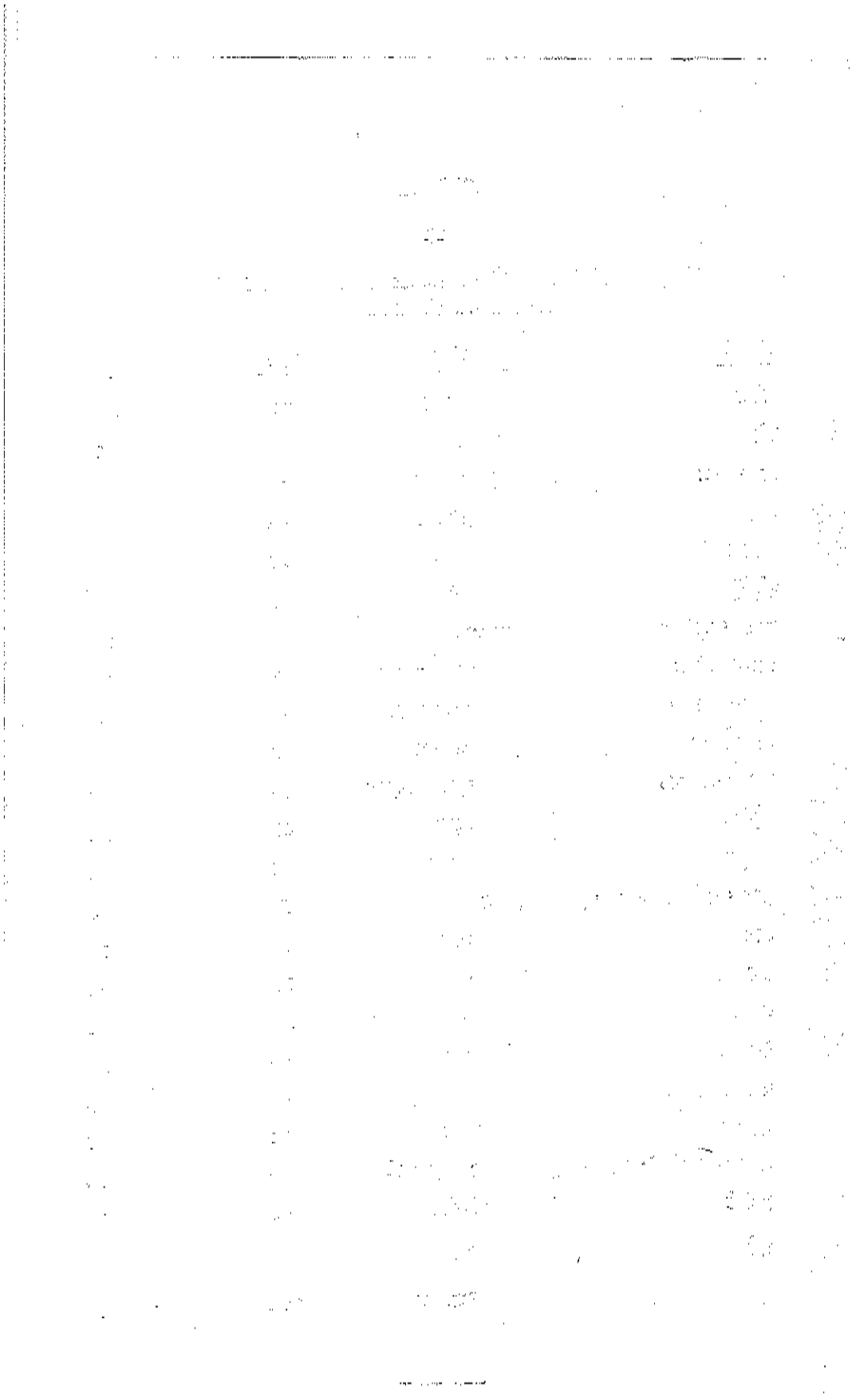

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 8 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होंगे ।

Old Age Pension

*1009. **Dr. Ram Parkash :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

(a) the districtwise number of persons getting old age pension in the State at present; and

(b) the districtwise number of persons out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes and Backward Classes respectively ?

Minister of State for Social Welfare (Capt. Ajay Singh) :

(a) & (b) : A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Statement Giving District Wise Detail of Beneficiaries Under Old Age Pension Scheme Indicating Scheduled Caste/Backward Classes Beneficiaries as on 31.12.94

Sr. No.	Name of District	Total No of beneficiaries on roll as on 31.12.94	No. of SC beneficiaries among the total No. of beneficiaries.	No. of B C beneficiaries among the total No. of beneficiaries.
1	2	3	4	5
1	Ambala	39799	10865	11939
2	Y/Nagar	30103	9299	7114

[Cap. Ajay Singh]

1	2	3	4	5
3	Kurukshetra	25011	8004	8754
4	Kaithal	32713	9963	9501
5	Karnal	36807	10077	12617
6	Panipat	22890	4415	5920
7	Sonepat	52285	8302	8730
8	Faridabad	35778	6909	3407
9	Gurgaon	46218	8807	12828
10	Rewari	25904	5699	3626
11	Narnaul	33661	6616	3258
12	Jind	38095	9804	8402
13	Rohtak	75693	25021	14011
14	Bhiwani	42544	10648	10602
15	Hisar	75628	23486	20728
16	Sirsa	25709	8948	6427
	Total	638838	166863	147864

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि पैंशन के लिए पात्र वृद्धों की संख्या 6 लाख, 38 हजार, 838 है । इसके साथ ही जिलावाईज लिस्ट भी रख दी है । जहां तक अनुसूचित जातियों के पात्र वृद्धों की संख्या का ताल्लुक है, 1,66,863 अनुसूचित जातियों तथा 1,47,864 बैकवर्ड क्लासिज के वृद्धों को यह पैंशन दी जा रही है ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पात्र व्यक्तियों को कब तक की पैंशन दी जा चुकी है । जहां तक प्रतिशतता का ताल्लुक है, बी० सीज० तथा एस० सीज० की अच्छी प्रतिशता है । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि अदायगी में अगर कोई बैकलाग है, तो वह कब तक पूरा हो जाएगा । जो नया व्यक्ति पैंशन का हकदार होता है, उसके लिए साल में कितनी बार सर्वे किया जाता है और कब-कब सर्वे किया जाता है ? क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाने बारे विचार करेगी कि प्रत्येक महीने की किसी खास तिथि जैसे 7 तारीख तक यह पैंशन पात्र व्यक्तियों को दे दी जाया करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1993-94 के दौरान पात्र व्यक्तियों की पहचान की गई थी, उस वक्त टोटल लाभ पात्र व्यक्तियों की संख्या 1,00,426 थी और इसमें सामान्यतः 2.07% की बढ़ौतरी होनी चाहिए लेकिन यह बढ़ौतरी 14% पाई गई। इसका दोबारा रिव्यू करवाया गया और दो बार रिव्यू हुआ उसमें भी 80,224 लोग लाभपात्र पाए गए जो कि कुल संख्या का 11% बनता है। सही रूप में जब तक पहचान नहीं हो जाती तब तक सही व्यक्तियों को पैंशन नहीं मिल पाएगी इसलिए इसको दोबारा किया गया था ताकि सही व्यक्तियों को लाभ दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ इन्होंने एक और बात कही कि एक नया कार्यक्रम बना कर एक निश्चित तिथि को पैंशन दे दी जाया करे। यह कार्यक्रम तो पहले बना ही हुआ है। हमारी हर सम्भव कोशिश होती है कि 15 तारीख तक हरेक व्यक्ति को पैंशन मिल जाए। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि फरवरी, 1995 तक की पैंशन हमने सभी लाभपात्र लगभग 6 लाख 39 हजार लोगों को वितरित कर दी है।

चौधरी सूरज भान काजल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 4 साल पहले कितने लोगों को पैंशन दी जा रही थी और अब जिन लोगों को पैंशन दी जा रही है, उनकी संख्या कितनी है ?

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो पैंशन पहले दी जा रही थी उसमें पात्र लोगों की संख्या 6,79,255 थी और अब जिन व्यक्तियों को पैंशन दी जा रही है, उनकी संख्या मैंने अभी बताई ही है।

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि नये व्यक्तियों को लास्ट टाईम कब पैंशन दी गई थी। जहां तक मुझे मालूम है, सितम्बर, 1992 के बाद किसी भी नये व्यक्ति को पैंशन नहीं दी गई है। मन्त्री महोदय कृपया बताने का कष्ट करें कि पैंशन के लिए क्या सालाना कोई तारीख या तारीख फिक्स किया हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं विधवाओं को दी जाने वाली पैंशन के बारे में जानना चाहूंगा। पिछले सैशन में भी मैंने सदन में इस बारे में प्रार्थना की थी। भारत की नारी और कोई भी झूठ बोल सकती है परन्तु विधवा होने के बारे में कोई भारतीय नारी झूठ नहीं बोल सकती। पिछले 3 साल से विधवाओं को पैंशन नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार ऐसा नियम बनाए कि अगर कोई नारी दुर्भाग्य से विधवा हो जाए तो 2-3 महीने के अन्दर-अन्दर उसको पैंशन मिल जानी चाहिए। लेकिन उनको पैंशन तीन साल से नहीं मिली है। इसके साथ ही सितम्बर, 1992 के बाद किसी नए व्यक्ति को पैंशन नहीं मिली और इसी तरह से क्या विकलांगों के लिए पैंशन देंगे, इस बारे में मंत्री जी बताएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि जो नए लाभ पात्र हैं उनको हमने पैंशन नहीं दी है क्योंकि उनकी सही पहचान नहीं हो पाई है । जिनकी पहचान हो पाई है उनको 2/95 तक पैंशन दे दी है । जहां तक नई विडोज की बात है, उनको भी हमने 2/95 तक पैंशन दे दी है ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, विकलांगों और विडोज के बारे में मैं पूछना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : Chauhan Sahib, please sit down. The question is of old age pension. It is neither of widows nor of handicapped.

श्री रमेश कुमार अध्यक्ष महोदय, आज जो पैंशन दी जा रही है और चौधरी देवी लाल जी के राज में 65 साल की उम्र वाले को पैंशन दी जाती थी और इस सरकार ने वायदा किया था कि 60 साल वालों को चाहे वह आदमी हो या औरत हो पैंशन दी जाएगी । इन्होंने कितनों को पैंशन दी है इनकी संख्या आप बताएं ।

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम 60 साल की उम्र वालों को पैंशन दे रहे हैं । इनके राज में तो नवम्बर, 1990 से लेकर जून, 1991 तक किसी भी वृद्ध को पैंशन नहीं दी गई थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि कितने महीने हैं जिनमें इन्होंने पैंशन नहीं दी थी ।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 8 महीने की पैंशन नहीं दी थी ।

श्री अध्यक्ष : उसकी वजह क्या थी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वह तो ये ही जानते होंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ही नहीं रही थी तो हम पैंशन कहां से देते । ये जून की तारीख कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धीर पाल जी, आप फेस टू फेस बात न करें । आपको जो भी कहना है चेयर को एड्रैस करके कहें । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं और ठंडे दिमाग से बात सुनें । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर से अप्रैल तक 6 महीने बनते हैं और इन्होंने इन महीनों में पैंशन नहीं दी । (विघ्न) चलो, आप 5 महीने ही समझ लें । आप रिकार्ड की बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी साढ़े तीन साल की पैंशन 7वें महीने को इकट्ठी दी है । इनकी पार्टी ने तो 6-6 महीने की इकट्ठी पैंशन दी है । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का टाईम मिलना चाहिए । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण देने का टाईम नहीं है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नवम्बर से लेकर जून तक आठ महीने की पैंशन नहीं दी गयी । हमने इलैक्शन के दौरान अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में फैसला किया था कि पैंशन देने के लिए 60 साल की उम्र वालों का दोबारा से सर्वे शुरु करवाएंगे और सबको पैंशन देंगे । हमने जो फैसला किया था, उसी के अनुसार हम पैंशन दे रहे हैं । लेकिन बीच में 6 या सात महीने हम पैंशन नहीं दे पाए थे । यह पैंशन हम क्यों नहीं दे पाए थे, क्योंकि इन लोगों की करतूत की वजह से प्रदेश में बिजली का मामला बिगड़ गया था । इन्होंने एक भी नई यूनिट प्रदेश के अन्दर नहीं लगायी थी और बिजली की कोई नयी यूनिट न लगने की वजह से बिजली का उत्पादन बढ़ा नहीं । प्रदेश में बिजली की मांग इतनी बढ़ गयी कि हमारे सामने बहुत दिक्कत आ गयी । भारत सरकार ने हमसे कहा कि पहले आप हमें पैसा दो तब हम आपको बिजली देंगे । इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम 6 या 7 महीने पैंशन नहीं दे पाए थे लेकिन हमने इसके लिए बुजुर्गों से माफी मांग ली कि हम आपको सात महीने की पैंशन नहीं दे पाए क्योंकि भारत सरकार को बिजली का पैसा देना पड़ गया । हमने उनसे कहा कि बिजली भी आपके घर में ही आ रही है, नये बिजली के कनैक्शंज किसानों को दिए जा रहे हैं (विघ्न) आप सुनिए तो सही । अध्यक्ष महोदय, ये कैसी भाषा बोलते हैं ? अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर हमने सात महीने की इकट्ठी पैंशन यह दो किश्तों में स्टेट में भिजवायी और हर दो महीने के बाद इकट्ठे दो-सौ रुपये उनके सम्मान के लिए बुजुर्गों को भेजते हैं । हमने फरवरी तक का टोटल पैसा भेज दिया है । जहां तक विधवा पैंशन का सवाल है, दिसम्बर तक की टोटल पैंशन विधवाओं के लिए चली गयी है । इनकी पैंशन रोकने का सवाल ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि पैंशन की इस नयी पालिसी से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के वर्गों की पैंशन पाने की तादाद बढ़ गयी है या घटी है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनके वक्त में तो इन वर्गों के लोगों की पैंशन पाने की परसैंटेज 20 थी जबकि इस वक्त हम जो टोटल लोगों को पैंशन दे रहे हैं वह 6,38,838 है जिसमें से हरिजन पैंशन पाने वाले 1,66,863 हैं यानी लगभग हरिजन 26.1 परसैंट हैं । यह तो हरिजनों को कुछ नहीं दे रहे थे ।

श्री अध्यक्ष : अब अगला सवाल होगा ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह बिल्कुल सरासर गलत बात है । इसका मतलब तो आप सरकार को जान बूझ कर बचाने की साजिश कर रहे हैं। (विघ्न) यह बात बिल्कुल नहीं चलेगी । यह सरकार को बचाने की साजिश थी । (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो लाख लोगों की पैंशन खायी गयी है । (विघ्न) पहले आठ लाख लोगों को पैंशन मिलती थी । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : आप सुनिए तो । आपके समय में सौ रुपये सरकारी खज़ाने से जाता था और उसमें से दस रुपये कमीशन लेते थे । (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

चौधरी बलवन्त सिंह मायना : स्पीकर साहब, सरकार एक कमेटी बनाकर इस बात का सर्वे करवा ले कि कितने जिलों में हरिजनों की पैंशन गलत कटी है ।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं । हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं । ..... (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सभी उपस्थित जनता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मैम्बर्ज और अन-अटैच्ड मैम्बर्ज सदन से वाकआउट कर गए ।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

तारांकित प्रश्न संख्या 1017

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री कृष्ण लाल सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

Elimination of Poverty

*1003 **Shri Jai Singh** : Will the Finance Minister be pleased to state the outline drawn for eradication of poverty during the years 1993-94 and 1994-95 in the rural areas and the target, if any, fixed therefor in the State?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सारे राज्य में विभिन्न राजकीय विभागों तथा राज्य सरकार द्वारा चालित संस्थानों द्वारा विभिन्न स्कीमज़ के अधीन कार्यान्वित किये जा रहे हैं । इनका ब्यौरा पटल पर रखी गई विवरणी में दर्शित है ।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

विवरणी

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अधीन वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 में वित्तीय परिव्यय/व्यय का विवरण।

क्रमांक	क्रियान्वयन विभाग/स्कीम	1993–94			1994–95		
		वित्तीय परिव्यय (लाख रु0)	व्यय (लाख रु0)	रोजगार सृजन (उपलब्धी)	वित्तीय परिव्यय (लाख रु0)	व्यय (लाख रु0)	रोजगार सृजन (उपलब्धी)
1	2	3	4	5	6	7	8
	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम						
	ग्रामीण विकास						
1.	समेकित ग्रामीण विभाग कार्यक्रम	1241.37	1318.31	34026 (लाभान्वित व्यक्ति)	736.00	719.81 (1/95 तक)	15197 (1/95 तक (लाभान्वित व्यक्ति)
2.	ग्रामीण युवकों को स्वः रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना	139.13	143.54	6536 (प्रशिक्षित व्यक्ति)	60.40	74.24 (1/95 तक)	3167 (1/95 तक प्रशिक्षित व्यक्ति)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों एवं बच्चों का विकास	65.36	96.87	534 (संगठित ग्रुप)	71.29	22.14 (1/95 तक)	338 (1/95 तक संगठित ग्रुप)
4.	जवाहर रोजगार योजना	2582.73	2369.53	34.63 (लाख मानव दिवस)	2389.61	1530.37 (1/95 तक)	19.03 (1/95 तक लाख मानव दिवस)
5.	रोजगार एश्योरेंस स्कीम	1650.00	993.85	15.20 (लाख मानव दिवस)	4400.00	1824.37 (1/95 तक)	19.67 (1/95 तक लाख मानव दिवस)
2.	पशुपालन						
	विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम	110.00	122.18	2711 (लाभान्वित व्यक्ति)	113.00	72.89 (12/94 तक)	1244 (12/94 तक लाभान्वित व्यक्ति)
बी–स्वः रोजगार स्कीम्स							
1.	उद्योग विभाग						
1.	ग्रामीण रोजगार स्कीम्ज	124.08	126.80	6701	145.00	145.00 (अनुमानित)	3433 (अनुमानित पूरे वर्ष के लिये)

1	2	3	4	5	6	7	8
*2.	प्रधान मन्त्री रोजगार योजना शहरी / ग्रामीण क्षेत्र (वर्ष 1994–95 से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा दी गई है)	—	—	—	—	1455.25 (12/94 तक)	2935 (12/94 तक)
3.	उद्योग कुंजों की स्थापना	225.00	200.00	—	200.00	200.00	—
2.	मछली पालन						
	मछली पालन ईकाईयों की स्थापना	53.00	52.98	258	55.00	55.25 (अनुमानित)	600
3.	डेरी विकास लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना (3 व 5 दुधारु पशु)	43.00	40.91	1376	47.00	31.75 (12/94 तक)	774 (12/94 तक)
4.	खादी तथा ग्रामीण उद्योग विकास बोर्ड						
	खादी तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास	322.45	301.11	423	283.21	70.38 (1/95 तक)	107 (1/95 तक)

* वर्ष 1993–94 तक यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में चलाई गई थी ।

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अनुसूचित/पिछड़ी जाति कल्याण विभाग						
	हरिजन विधवाओं/बेसहारा स्त्रियों को सिलाई प्रशिक्षण देना	78.00	68.44	1685	78.00	46.78 (1/95 तक)	2049
**6.	हरिजन कल्याण निगम						
	कृषि तथा समृद्ध क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार, व्यवसायिक तथा स्वः रोजगार क्षेत्रों में आय तथा रोजगार उत्पत्ति कार्यकलाप	2096.92	1101.43	11296	2276.14	707.21 (1/95 तक)	7209 (1/95 तक)
7.	हरियाणा पिछड़ी जातियां तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम						
	पिछड़ी जातियां तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मार्जन मनी सहायता देना	लागू नहीं	252.68	4323	लागू नहीं	110.94 (1/95 तक)	1906 (1/95 तक)

** हरियाणा औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक फोकल गांवों में प्लाटों का विकास/शैड का निर्माण करता है। यह प्लाट/शैड ग्रामीण युवकों को स्वः रोजगार देने के लिए अलाट किए जाते हैं। अब तक सोनीपत जिले के गांव जथेरी में 78 प्लाट/शैड तथा गुड़गांव जिले के अलीपुर गांव में 66 प्लाट/शैड तैयार किए गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	महिला विकास निगम						
	1. महिलाओं को स्वः रोजगार के लिए मार्जन मनी सबसिडी/दीर्घ कालीन ऋण	लागू नहीं	177.19	1369	लागू नहीं	115.22 (1/95 तक)	1214 (1/95 तक)
	2. महिलाओं को डेरीज के लिए रोजगार सहायता देना	लागू नहीं	8.11	1903	वर्ष 1994-95 से यह स्कीम समाप्त कर दी गई है।		
सी0	प्रशिक्षण एवं उत्पादन एवं रोजगार स्कीम्ज						
1.	महिला विकास निगम महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन, कटाई एवं सिलाई स्टेनोग्राफी, मोटर वाईडिंग व दरी बनाने के लिए प्रशिक्षण	लागू नहीं	1.50	240	लागू नहीं	15.44 (1/95 तक)	610 (1/95 तक)
2.	हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम						
	1. हथकरघा बुनाई में प्रशिक्षण	10.00	15.37	55	11.00	15.00	68
							पूरे वर्ष के लिए अनुमानित

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2. गलीचा बुनाई में प्रशिक्षण	6.60	9.18	115	7.00	9.00	56	पूरे वर्ष के लिए
	3. चीनी के बर्तन बनाने में प्रशिक्षण	3.20	2.50	13	2.40	2.50	18	अनुमादित
	4. हाथ/स्क्रीन छपाई में प्रशिक्षण	2.20	2.95	19	प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिये गये है।			
3.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम मेवात विकास एजेंसी के अधीन प्रशिक्षण केन्द्र							
	1. मुद्रा बनाने, सजावटी सामान बनाने तथा चमड़े के फुटबाल तथा वालीबाल बनाने में प्रशिक्षण	6.00	8.99	82	8.00	8.40	83	—सम—
	2. हस्तशिल्प विकास प्रशिक्षण केन्द्र मुद्रा बनाने, पंजा दरी बुनने, सजावटी सामान बनाने तथा फर्नीचर के लिए कवरज बनाने में प्रशिक्षण	0.85	2.23	160	0.90	2.40	36	—सम—

श्री जय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन विभिन्न योजनाओं के तहत कौन-कौन से ग्रामीण आते हैं और इसमें अन्न देने का क्या क्राइटेरिया है ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि [illegible] ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचा है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे कितने आदमी हमारे हरियाणा में हैं, उसका सर्वे भारत सरकार की एक एजेंसी नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन करती है । यह आर्गेनाइजेशन 4-5 या कभी 6 साल के बाद भारतीय स्तर पर सर्वे करती है और उसकी रिपोर्ट हर प्रदेश को पहुंच जाती है। जो 1987-88 का सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट के रिजल्ट हमारे पास हैं । उसके मुताबिक हमारे हरियाणा में करीब 6 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रिकार्ड किए गए हैं । उनको राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए इमदाद की जाती है । नीलोखेड़ी का जहां तक राणा साहब ने सवाल किया है, उसका अभी मेरे पास जवाब नहीं है । स्टेट लैवल पर 6 लाख के करीब परिवार हैं, जिनको हम ऊपर उठाने के लिए भिन्न-भिन्न स्कीमों से उनकी सहायता कर रहे हैं ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में पर-कैपिटा आय क्या है ? बैकवर्ड क्लास की प्रतिव्यक्ति इंकम क्या है, शिड्यूल्ड कास्ट्स की क्या है और यह नीतियां लागू करने के बाद उनकी प्रतिव्यक्ति आय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस क्वैश्चन से इसका संबंध नहीं है । सवाल यह था कि कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनको अन्न देने का क्या क्राइटेरिया है । फिर भी मैं मापदण्ड बता देता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आप बैठ जाइए ।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, जो क्राइटेरिया एडॉप्ट किया हुआ है, उस आर्गेनाइजेशन ने, वह वैसे तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन उनका है । उन्होंने कहा है कि रूरल एरिया में 2,400 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन जिस व्यक्ति को मिलती है, उसको गरीबी रेखा के नीचे शामिल करते हैं । अर्बन एरिया में 2,100 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलती है । इसका जो फार्मूला एडाप्ट किया हुआ है, उसी हिसाब से कर रहे हैं लेकिन इसको पर-कैपिटा इंकम 11 हजार रुपये पर-एनम, पर फैमिली की इंकम को काऊंट करके गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिये मापदण्ड रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि गरीबी की रेखा से नीचे एस0सी0, बी0सी0 और जनरल लोग कितने-कितने हैं । इनकी अगर कोई संख्या आपके पास है तो बताएं ।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऐसा इन्होंने पूछा नहीं है । इसके लिये अलग से लिख कर हमें भिजवा देवें । हम सूचना दे देंगे । इस समय ऐसी कोई सूचना हमारे पास अवेलेबल नहीं है ।

Agra Canal

*1070 **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Irrigation be pleassed to state whether there is any proposal under the consideration of the Govenment to claim for extra share of water in Agra Canal; if so, the details thereof ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) No, Sir. Not applicable in view of above.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में 'न' कहा है । मैं इनसे आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आगरा कैनाल है, यह हमारे फरीदाबाद व समस्त मेवात एरिया के किसानों के लिये लाईफ-लाईन है, उसमें टोटल कितना पानी चलता है और उसमें हरियाणा का कितना शेयर बनता है ? दूसरे, जब आगरा कैनाल बनी थी तो क्या उस वक्त उसमें इतना पानी नहीं आता था जितना कि आज आ रहा है ? गंग कैनाल का पानी भी उसमें पड़ता है । दिल्ली-फरीदाबाद का जितना सीवरेज का पानी है, वह भी उसी नहर में आता है । मुख्य मन्त्री महोदय क्या इस बात का आश्वासन देंगे कि हरियाणा सरकार, जो फालतू पानी उसमें आ रहा है, उसमें से हरियाणा का शेयर क्लेम करने के लिये यू0पी0 सरकार से बातचीत करेगी ? स्पीकर साहब, यह आगरा कैनाल का मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण है लेकिन हरियाणा सरकार इस बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है । शायद मुख्य मन्त्री महोदय अब इस बात को भूल गये हैं लेकिन जब उन्होंने फरीदाबाद से इलैक्शन लड़ा था तो लोगों से इसी बात को लेकर उनके आगे झोली फैलाकर वोट भी मांगे थे और यह कहा था कि हरियाणा सरकार इस नहर का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लेगी । क्या इस बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह आगरा कैनाल करीब 150 साल पहले से ही चल रही है, तब से ही इसका मैनेजमैंट यू० पी० सरकार के पास है और उसमें जो टोटल पानी आता है उसका 20.69 परसैन्ट पानी हरियाणा के लिये है। जोकि रफली 782 क्यूसिनस बनता है और हिडन नहर का जो पानी आता है, उसमें से भी अपना हिस्सा हम लेते हैं। इसके साथ-साथ इन्होंने मैनेजमैंट की बात भी यहां पर कही। उस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने इसके लिये काफी कोशिश की है और इस बारे में हरियाणा व यू० पी० के मुख्य मंत्रियों की बातचीत भी हुई है। पिछली सरकार ने 1989 में मुख्य मंत्री स्तर पर बातचीत की थी। उसके बाद सचिव लैवल पर भी डिस्कशन हुई। उससे पहले 1975 में यू० पी० और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। फिर यही बात 26-5-89 को मुख्य मंत्रियों के लैवल पर हुई। 29-6-89 को सचिव लैवल पर फिर बातचीत हुई कि यह जो मैनेजमैंट है, यह हरियाणा के हाथ में होनी चाहिये। उसके बाद जब एकोर्ड हो रहा था, उस वक्त हरियाणा के मुख्य मन्त्री महोदय ने यू० पी० के मुख्य मन्त्री से कहा कि हमें इस नहर का मैनेजमैंट दिया जाना चाहिये। उसके बाद 12-5-94 को फिर सचिव लैवल पर यह मीटिंग हुई कि इसका मैनेजमैंट हमारी हरियाणा सरकार के हाथ में होना चाहिये। यह बात दुरस्त है कि आगरा कैनाल की मैनेजमैंट हरियाणा के हाथ में होनी चाहिये। हम बार-बार मीटिंग करके इस बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं और यू० पी० की सरकार बार-बार इस पर एतराज कर रही है, वह भी भिन्न-भिन्न तरीकों से, चाहे आबियाना न दिया गया हो या दूसरा कोई कारण हो। वे यह बात कह रहे हैं कि हमारा कई सालों का आबियाना नहीं दिया गया जोकि कई सालों का एक्युमुलेट हो गया है। तो ऐसी कई बातें हैं जिनकी वजह से उस नहर की मैनेजमैंट हमारे पास नहीं आ रही है। अब चूंकि हथिनी कुंड बैराज का एकोर्ड हो गया है, इसलिए हम यह मामला अपर यमुना बोर्ड के सामने रखेंगे और ऊपर के लैवल से इसका फैसला करवाएंगे।

श्री अजमत खां : स्पीकर साहब, आगरा कैनाल फरीदाबाद जिले के लिए मौत और जिन्दगी का सवाल बन गई है। अभी मन्त्री जी ने बताया कि इसमें हमारा पानी का हिस्सा 20.69 परसैंट है। सवाल यह है कि जितना पानी हमें वहां से मिलता है, क्या वह सारा आगे जाता है या नहीं। गुड़गांव कैनाल में सिल्ट की वजह से भी हमें पूरा पानी नहीं मिलता। गुड़गांव कैनाल जहां से शुरू होती है, वहां पर भी वह सिल्ट से भरी पड़ी है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आगरा कैनाल की सारी नहरों में सिल्ट भरी पड़ी है। क्या सरकार गुड़गांव कैनाल की सफाई करवाएगी ताकि हमें पूरा पानी मिल सके। मेवात के एरिया में जहां पहले गन्ना होता था, आज वहां पीने के लिए पानी भी नहीं रहा। हम चाहते हैं कि हमें गुड़गांव कैनाल से अपने पानी का पूरा हिस्सा मिले। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हमारे एरिया की नहरों की डि-सिल्टिंग कब करवाएंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, गुड़गांव कैनाल और आगरा की बात अलग-अलग है। आगरा कैनाल की मैनेजमैंट यू0 पी0 वालों के पास है और गुड़गांव कैनाल की हमारे पास है। यह बात ठीक है कि गुड़गांव कैनाल की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन उसमें पानी कम है। इसका कारण यह है कि वह एस0 वाई0 एल0 से जुड़ी हुई है। जहां तक उसकी सफाई की बात है, यह बात दलाल साहब की भी ठीक है और अजमत खां जी की भी ठीक है कि इनकी सफाई कम हुई है। गुड़गांव कैनाल के जरिए राजस्थान में भी पानी जाता है। इसलिए यह मामला दोनों स्टेट्स के अंडर कंसिडेशन है। आगरा कैनाल में भी कई जगह सिल्ट हो गई है इसलिए हम यू0 पी0 वालों को कहते रहते हैं कि वहां की मैनेजमैंट उसको ठीक करवाए। लेकिन वे कहते हैं कि पहले हमें आबियाना दिया जाए। यही वजह है कि फरीदाबाद जिले में पानी की दिक्कत आ रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा कैनाल का कन्ट्रोल हरियाणा सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही यह तो हरियाणा सरकार ही जानती है लेकिन आज फरीदाबाद और गुड़गांव जिले के किसानों को तारीखें भुगतने के लिए मथुरा और आगरा जाना पड़ता है। उनके बड़े-बड़े सभी अधिकारी मथुरा और आगरा में बैठते हैं। क्या मन्त्री महोदय यू0 पी0 सरकार से बात करेंगे कि उनके सभी अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पलवल में आया करें ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें हमारा हिस्सा 782 क्यूसिक पानी का है। अध्यक्ष महोदय, यू0 पी0 सरकार इस पानी के वितरण में भी हमारे साथ ज्यादती कर रही है। वे पानी इस तरीके से देते हैं कि पानी की जरूरत तो किसान को आज है लेकिन वे दो महीने के बाद देंगे। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटरी की सौ क्यूसिक की कैपेसिटी है, तो उसमें 20-25 क्यूसिक पानी देते हैं। तो क्या मन्त्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि जब तक इस नहर का नियंत्रण हरियाणा को नहीं मिलता, तब तक सरकार उन समस्याओं का समाधान करेगी जो मैंने बताई हैं ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की यह बात दुरुस्त है 10.00 बजे कि उनके ऑफिसर्ज मथुरा में बैठते हैं। पिछली बार जब इस बारे में मीटिंग हुई थी तो सैक्रेटरी लैवल पर और मुख्य मंत्री लैवल पर यह इनसिस्ट किया गया कि फरीदाबाद के किसानों को दूर न जाना पड़े इसलिए ओखला और पलवल में एस0 डी0 ओ0 लगाएं। हम फिर कोशिश करेंगे कि वहां के एक्सीयन और एस0 ई0 कम से कम हफ्ता या एक महीने के बाद टूर लगा कर वहां पर आएं और किसानों को जो दिक्कत है, उसको ठीक करें। माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही कि जो पानी की कैपेसिटी है, उसके मुताबिक वे पानी नहीं छोड़ते हैं। इनकी यह बात कुछ हद तक ठीक है। यह इसलिए ठीक है क्योंकि ओखला का

[चौधरी जगदीश नेहरा]
मैनेजमैंट यू0पी0 गवर्नमैंट के पास है और वे कई बार इस बारे में दिक्कत करते हैं लेकिन इस बारे में भी हम पूरा ध्यान रखेंगे ताकि हमें हमारा शेयर ठीक मिले और उसका ठीक इस्तेमाल हो ।

श्री सूरज मल : स्पीकर साहब, मैं सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नहरों की जो डीसिल्टिंग की गई है, क्या उससे आपको तसल्ली हो चुकी है ? मेरे देखने में आया है कि 25 या 30 परसैंट यानि बहुत मामूली-मामूली, एक दिखावे के तौर पर नहरों की डीसिल्टिंग का काम किया गया है । सारी नहरें गाद से अंटी पड़ी हैं । सभी नहरों में अंड़गा भरा हुआ है । यह तो मुझे पता नहीं है कि सरकार ने नहरों की डीसिल्टिंग पर कितना पैसा खर्च किया है लेकिन कई सालों के बाद डीसिल्टिंग का काम किया गया है और वह भी ठीक तरह से नहीं किया गया है । अगर डिसिल्टिंग इसी तरह से की गई, जैसे पहले होती थी तो नहरों में पानी नहीं चलेगा । टेल पर पानी नहीं पहुंच सकेगा । अब जो डीसिल्टिंग की गई है, वह बैड तक नहीं की गई, केवल ऊपर-ऊपर से मिट्टी खुर्ची गई है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि डीसिल्टिंग कितनी हुई है और जितनी रह गई है, वह कब तक हो जाएगी ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इस सप्लीमैंटरी का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य चौधरी सूरजमल जी को इस बारे में बताना चाहूंगा । इनके इलाके में दुल्हेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी और बहादुरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी, दो हैं । उनकी 76,000 आर0डी0 तक सफाई हो चुकी है और आगे भी सफाई कराएंगे । इस बारे में तसल्ली इसलिए नहीं होती क्योंकि आज डीसिल्टिंग की गई और कल सिल्ट आ सकती है इसलिए इसमें तसल्ली वाली बात नहीं है । इस बारे में कोशिश है कि डिसिल्टिंग का काम ठीक ढंग से किया जाए । मैंने पिछली बार भी कहा था कि नहरों की डीसिल्टिंग के लिए जितना पैसा जाता है, उसकी कंसर्न्ड डी0सी0 और वहां के एम0एल0ए0 को कापी भेजते हैं । (शोर) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि सभी नहरों की सिल्ट कब तक निकल जाएगी । सरकार इस काम के लिए जागरुक है ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सवाल यह पूछा है कि नहरों की सिल्ट को केवल ऊपर-ऊपर से छील कर जाते हैं, उसकी डैप्थ तक डीसिल्टिंग नहीं करते हैं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, सिल्ट निकालने के बारे में हाईड्रोलिक सर्वे करते हैं कि डैप्थ कितनी है और चौड़ाई कितनी है, उसके बाद मिट्टी बाहर निकालते हैं ।

Construction of road from village Karor to Pahrawar

*1083. **Ch. Balwant Singh Maina :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Karor to Pahrawar in district Rohtak during the year 1995 ?

Public Works Minister (Ch. Amar Singh):

No Sir.

चौधरी बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाते हुए कहना चाहता हूं कि यहां पर कई बार सरकार घोषणा कर चुकी है कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, सरकार गलत बायदे करती है । जिला रोहतक के गांव करोर से पहरावड़ तक की सड़क अभी तक नहीं बनाई गई । चौधरी अमर सिंह जी जब अपोजीशन में बैठते थे, तो दूसरी बात कहते थे, अब सरकार की बात कहते हुए जवाब "नो" में दे दिया । मुझे उम्मीद थी कि वे इस सड़क को बनवा देंगे । क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इन गांवों को कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री अमर सिंह धानक : मैं अपने लायक दोस्त को बताना चाहता हूं कि यह गांव सड़क से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है । Karor village is connected with Rohtak-Jhajjar Road at Shimli and with Delhi-Rohtak Road from two sides. Another road is connected with Dighal. So, this village Karor is connected with four sides.

चौधरी बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है, उस रास्ते से 25-30 किलोमीटर का चक्कर काट कर रोहतक के किसानों को अपना अनाज मण्डी में ले जाना पड़ता है और जिधर से मैं चाहता हूं, यदि वहां से सड़क निकाल दी जाये तो यह रास्ता रोहतक से पहरावड़ और करोर अढ़ाई किलोमीटर और छः किलोमीटर का रास्ता रह जायेगा । आप देखिए कि जिस रास्ते से ये इन गांवों को सड़कों से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, उससे एक बैलगाड़ी कितने घण्टे में रोहतक पहुंचेगी ?

चौधरी अमर सिंह : पहरावड़ से यह रास्ता 5.20 कि0मी लम्बा पड़ता है । करोर भी चारों तरफ से सड़क से जुड़ा हुआ है । अगर माननीय सदस्य इस सड़क को बनवाना जरूरी ही समझते हैं तो धन की उपलब्धि पर इसको बना देंगे ।

Occurrence of Financial Irregularity in Meham Sugar Mill.

*1086. **Chaudhri Zile Singh Jakhar :** Will the Minister for Co-operation be pleased to state—

(a) whether any case of financial irregularity in Cooperative Sugar Mill, Meham, district Rohtak has come into the notice of the Government during the month of March, 1994 to date; if so, the amount involved therein ; and

[Chaudhri Zile Singh Jakhar]

(b) whether any enquiry in regard to the afore-said case has been conducted; if so, the result there of, togetherwith the action taken thereon?

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) :

(क) हां, एक 1,07,366 रुपये गबन का मामला हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के नोटिस में आया ।

(ख) हां, जांच-पड़ताल अधिकारी (इन्क्वायरी औफिसर) की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि कब यह जांच की गई, और उसके बाद उसके रिजल्ट क्या रहे ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस घपले में किसी अफसर या लीडर का तो हाथ नहीं है । तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी वित्तीय अनियमितताएं भविष्य में न हों, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? जो इंक्वायरी चल रही है, वह कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह गबन का मामला है । इसमें 1,07,366 रुपये का गबन हुआ है । यह मामला 10-6-94 को नोटिस में आया । वहां पर श्री कर्मवीर नाम का एक केन क्लर्क इसमें शामिल पाया गया था । उसने 7-7-94 और 9-7-94 को यह पैसा जमा करा दिया । इस इन्क्वायरी की फाईनल रिपोर्ट 15 मार्च 1995 तक पूरी होने की उम्मीद है ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : जो पैसा गबन हुआ था, वह जमा हो गया है । What is the fate of that enquiry, which has been constituted against him. जब सरकार मानती है कि वह दोषी है, तो उसके खिलाफ इन्क्वायरी करवाने की क्या जरूरत है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी रिपोर्ट मंगवा कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि मार्च, 1995 तक सारी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी । जो पैसा गबन हुआ था, वह 7-7-1994 और 9-7-1994 को जमा करवा दिया गया है । मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अन्य अनियमितता हुई है । इन्होंने लीडर का हाथ होने की बात पूछी है । अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी ने गबन किया है और उसने इस बात को माना भी है कि "मैंने गबन किया है" फिर इसमें लीडर का हाथ कहां से आ गया ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से स्टेट का पैसा खाने लगे तो स्टेट का काम चलना ही मुश्किल हो जाएगा। उस कर्मचारी के ऊपर कोई तो अधिकारी होगा और कोई लीडर होगा जिसके नीचे वह काम करते हैं। लीडर या अफसर कोई भी इसमें इन्वाल्व हो सकता है। अगर अफसर का भय नहीं होगा तो कर्मचारी तो गबन करेगा ही।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, गबन करने वाले कर्मचारी का नाम कर्मवीर है जो कि कैन क्लर्क है। उसने स्वयं माना है "हां, मैंने पैसे का गबन किया है" जो पैसा गबन हुआ था वह उसने स्वयं जमा करवाया है, इसमें लीडर का हाथ कैसे हो गया ?

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा कि क्या अकेले कर्मवीर ने यह राशि गबन की है ? अकेला व्यक्ति कभी इतना पैसा गबन नहीं कर सकता अगर उसने किया है तो कैसे किया है, जो इन्क्वायरी कान्स्टीच्यूट की गई है, उसमें इन्क्वायरी ऑफिसर को कितने समय में इन्क्वायरी करने के लिए कहा गया है। (विघ्न) इन्क्वायरी के लिए समय दिया जाता है 2 महीने या 3 महीने। इस केस में कितना समय दिया गया है ? अगर समय फिक्स किया गया था, तो इन्क्वायरी को कम्पलीट करने में डिले जो हुई है वह कितनी है ? इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि यह कर्मवीर कहां का रहने वाला है ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह कर्मवीर मदीना का रहने वाला है। इस गबन में 2 और कर्मचारी भी इसके साथ थे (विघ्न)

Mr. Speaker : Please complete the inquiry at the earliest and the report be sent.

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया यह बताएं कि इस इन्क्वायरी के लिए कितना समय दिया गया है ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: 15 मार्च, 1995 तक यह समय पूरा हो जाएगा।

Purchase of Tomato Seed

*1096. **Shri Dhir Pal Singh** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether tomato seed has been imported from Israel during the year 1994-95; if so, the total quantity thereof alongwith the rate thereof ?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Yes Sir. In order to help farmers in horticulture cultivation in those regions of Haryana which have underground brackish water, small quantities of five varieties of hybrid tomato seeds from Israel have been imported for trial at 25 places in the State.

The varietywise quantity and rates are as under:—

Name of Variety	Quantity	Total amount involved
675	200 gms.	14,490/-
Daniela	100 gms.	22,050/-
5656	100 gms.	8,505/-
FA-67	90 gms.	7,655/-
FA-58	100 gms.	8,505/-
	590 gms.	61,205/-

श्री वीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में हमारे लायक कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जहां जमीन में खारा पानी है, वहां पर इन्होंने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इतने मंहगे बीजों का प्रयोग किया है । ये लायक मंत्री हैं और इजराईल घूमने गए थे । वहां से इतने मंहगे बीज ले आए । इनके लायक होने की वजह से इनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा । अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इन बीजों को खरीदने से पहले इजराईल में कितने अधिकारी गए और कितना खर्चा आया ? यह भी बताएं कि वहां पर कौन-कौन से अधिकारी गए थे । अध्यक्ष महोदय, आप भी एक लायक किसान हैं । आप यह भी जानते हैं कि हमारे किसान की इतनी क्षमता नहीं है कि वह इतनी महंगी परचेजिंग कर सके । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जहां-जहां पर यह बीज बोने की चेष्टा की है, क्या वहां पर लोगों को इन बीजों को लगाने की ट्रेनिंग दी है । अगर किसान लगभग 22 हजार के बीज खरीद कर बो देता है और कल को उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो क्या सरकार उसको उसी हिसाब से मुआवजा देगी ? अध्यक्ष महोदय, पहले भी कई जगहों पर ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई थी और इस सरकार ने किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया था । क्या कृषि मंत्री जी ने या मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला किया है कि अगर इतने महंगे बीज खरीदने के बाद किसी की फसल खराब हो जाती है, वहां सरकार फसल बीमा योजना लागू करना चाहेगी ? आप यह भी बताएं कि इसकी क्या गारन्टी है कि मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे आनरेबल मैम्बर किसान हैं और ये किसानों की बात कहते हैं लेकिन इन्होंने अपने टाईम में किसानों के भले की बात नहीं सोची, जिस वजह से आज किसानों की खराब हालत है । अध्यक्ष महोदय, आने वाले वक्त में किसानों के साथ क्या-क्या होगा । उनका परिवार बढ़ता ही जा रहा है। जिस किसान के पास 50 एकड़ जमीन थी, आज वह बंट कर 5 एकड़ ही रह गई है । जो किसान छोटा है, हम उसकी भलाई के लिए सोच रहे हैं जो कि आप नहीं सोच सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, इजराईल की जो जमीन है वह हरियाणा की जमीन से मिलती-जुलती है । उनका पानी भी ब्रैकिश था । हमारे हिसार, भिवानी और रोहतक में भी वहां की तरह खारा पानी है जोकि खेती के लिए ठीक नहीं है । इजराईल ने साईस एंड टैक्नोलोजी का प्रयोग करके इस पानी का प्रयोग किया और वहां खेती इतनी अच्छी हुई कि शायद आज वर्ल्ड में इस मामले में इजराईल का एडवांस्ड कंट्री में नाम आता है । इजराईल एक ऐसा कंट्री है, जिसने साईस में और ऐग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की है । मुख्य मंत्री जी वहां गए थे और इनको वहां पर दिखाया गया । वहां पर देखने के बाद इन्होंने पाया कि वहां लैंड ऐसी ही थी जैसे हमारे यहां पर टिब्बे हैं, ऐसे ही वहां खराब पानी था जैसे हमारे यहां पर है। लेकिन वहां पर टमाटर की फसल बहुत अच्छी हो रही है । अगर आप हरियाणा के छोटे किसान को उसकी इनकम बढ़ाने के लिए नये-नये बीज लाकर नहीं दोगे तो आप मुझे बताएं कि फिर उसका गुजारा कैसे होगा । इनको मालूम होना चाहिए कि यह जो बीज मंगवाया गया है, तो यह बीज हाई ब्रिड है, नयी वैराइटी है और इसका बीज बिल्कुल बारीक होता है । स्पीकर सर, ये कह रहे हैं कि ये बीज बहुत महंगा लिया गया जबकि मैं कहता हूं कि अगर आप एक किसान को अच्छा क्वालिटी का बीज दे दें तो वह उससे एक एकड़ में अपनी दुगनी फसल लेने के लिए ज्यादा प्राईस पर भी बीज खरीद लेगा ।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरदार साहब मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि क्या किसानों के लिये कई लाख रुपये का बीज खरीदा जायेगा ?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर सर, अगर यह सही रिप्लाई न पढ़ें तो उसका क्या इलाज है । यह बीज टोटल 61,205 रुपये का आया है । (विघ्न) सर, इनको तो यह भी पता नहीं है कि टमाटर के बीज का साईज क्या होता है । आप इनसे इस बारे में पूछिए । मैं इनको बताता हूं । वह बीज बहुत ही बारीक होता है । यह बीज डिमांस्ट्रेशन के लिए लाया गया है । किसानों के छोटे-छोटे प्लाट्स पर इनकी नर्सरी लगायी गयी और खुशी की बात तो यह है कि इस बीज का जर्मीनेशन 90 परसैंट तक है । इस टमाटर के पौधे की नर्सरी 25 जगहों पर किसानों की दी गयी है ताकि वह इसको लगाकर ट्रायल कर सकें । फिर आप ही बताइये कि इसमें कहां

[श्री हरपाल सिंह]

नुकसान है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये आगे आने वाले समय के लिए, छोटे किसानों के भले के लिए भी सोचें और अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है, तो इनको उसको अच्छा ही कहना चाहिए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरदार साहब ने तो बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया और इनकी बात में कोई दम-खम नहीं है। मैंने मुख्य मंत्री जी के बाहर के दौरे के बाद ही कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, के एवं दूसरे साईंटिस्ट्स, जो कृषि से संबंध रखते हैं, से इस बारे में जानकारी ली थी। तब मुझे पता चला कि इस बीज का इस्तेमाल एयरकूल्ड भवन में ही हो सकता है। क्या छोटा किसान एयरकूल्ड शीशे का भवन बना सकता है? आज प्रदेश में कितने ऐसे किसान हैं, जो एयरकूल्ड शीश महल बनाकर इतने मंहगे बीज से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस पर तो लाखों रुपये की लागत आएगी। ऐसे में क्या यह टमाटर का बीज तैयार हो सकेगा? जबकि ये छोटे किसानों की बात करते हैं, छोटे टिब्बों की बात करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को कहें कि वह हमें ऐसा आश्वासन दे और यह कहे कि यह बीज छोटे किसानों के लिए ठीक नहीं है? क्या यही छोटे किसानों के लिए इनकी हमदर्दी है? क्या आज प्रदेश में कोई ऐसा छोटा किसान है जो इस तरह के शीशमहल बनाकर इस टमाटर के बीज को तैयार कर सकेगा? मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर सर, ऐसा है कि किसान को जब तक हम नये बीज नहीं देंगे, किसान की हालत नहीं सुधरेगी। मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि आज स्टेट में हम डबल क्रौप करते हैं और ज्यादा क्या होता है कि हम पैडी और व्हीट पर आ गए हैं। पैडी और व्हीट का जो रोटेशन है इससे जमीन कमजोर हो रही है इसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इससे स्टेट के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि ऐसी क्रौप किसानों को दें जिससे पानी का कंजम्पशन भी कम हो और किसान की इंकम भी ज्यादा हो। पानी कम लगे और आमदनी ज्यादा हो। इस बात पर हम विचार कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि कौन सी क्रौप ऐसी हो सकती है जो जमीन की क्वालिटी भी खराब न होने दे और किसान की इन्वैस्टमैंट भी कम हो और इंकम भी बढ़े। रोहतक जिला इस मामले में थोड़ा पीछे है। व्हीट सीड की क्वालिटी का प्रौडक्शन जब हमने बढ़ाने का फैसला किया तो जो लेटैस्ट सीड था-व्हीट का 2329 वह रोहतक जिले में किसानों ने नहीं अपना रखा था। मैंने यह कहा कि जो सीड बैटर क्वालिटी का है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा वह रोहतक जिले में जाना चाहिए और सोनीपत में जाना चाहिए। हमने ऐक्सटैंशन के लिए रोहतक और सोनीपत जिले को अच्छी क्वालिटी का बीज भेजा। आज उनकी क्रौप पहले से ज्यादा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताइये कि जो सीड आपने इजराईल से लिया है उससे जो टमाटर होंगे उनसे आगे जो सीड बनेगा, उसी को सीड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे ?

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सीड अन्डर ट्रायल है । हाई ब्रिड सीड है। जैसे दूसरा सतफूनावर हाई ब्रिड बनने लग गया, इसी तरीके से हाई ब्रिड सीड बनाने के लिये यूनिवर्सिटी को इसे दिया है ताकि आगे इस सीड को हाई ब्रिड में कंवर्ट करते चले जाएं ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरदार हरपाल सिंह जी ने इस बारे में डिटेल से बता दिया है फिर भी मैं इसमें दो मिनट का समय लेना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, हम बहुत जल्दी किसानों की एक टीम इजरायल भेजेंगे । उसमें मैं चौधरी वीर पाल सिंह जी से कहूंगा कि अगर वे जा सकें तो मेहरबानी करके जाएं । वहां जाकर आपको देखने से पता लगेगा कि लोग कैसे खेती करते हैं । मैंने जाकर के वहां देखा है । वहां राजस्थान जैसे टीले हैं । उन टीलों में खारा पानी है । पानी भी घूंट लेकर देखा । वे लोग खारे पानी की एक-एक बूंद का भी इस्तेमाल करते हैं । बाकायदा लिफ्ट इरीगेशन से प्रयोग करते हैं । आपने कहा कि कितने रुपये लग जाएंगे । आपकी यह बात ठीक है । शुरु में 5–6 लाख रुपये खर्च होंगे । सरकार लोन देगी और वह जमीन 20–25 साल तक चलेगी । यह नहीं कि हर छठे महीने खराब हो जाएगी । उसे ग्रीन हाउस कहते हैं । इसमें एक एकड़ में 10 से 20 लाख रुपये तक की इंकम है ।

श्री अध्यक्ष : यह उनके यहां का भाव होगा । अपने यहां के हिसाब से नहीं होगा ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां के हिसाब से बता रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं वहां के पौंड की वैल्यू के हिसाब से ही बता रहा हूं । इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी एच0ए0यू0 ने 400 किस्मों के बीज वगैरह की वैरायटी तैयार की है और ऐग्री-इंडस्ट्रीज वालों ने खरीद करके उसकी आगे किसानों को डिमांस्ट्रेशन दी ताकि किसानों को इस बारे में पूरी जानकारी मिल सके । (शोर)

श्री वीर पाल सिंह : खारे पानी को मीठे पानी में कैसे कंवर्ट करोगे ?

चौधरी भजन लाल : मीठे पानी में कंवर्ट करने की जरुरत ही नहीं है । खारे पानी में ही होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, लहसुन, प्याज । हमने मौके पर जाकर देखा है और खाकर भी देखे हैं । (शोर)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Setting up of 33 KV Sub-Station at Village Alewa

*1109. Shri Ram Kumar Katwal : Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether the 33 KV Power Sub-station at Village Alewa has started functioning; and

(b) if not, the reasons therefor ?

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) अलेवा में 33 के0वी0 उपकेन्द्र वर्तमान समय में निर्माणाधीन है।

Water supply scheme Based on canal Water

*1126. Prof. Ram Bilas Sharma : Will the Minister for Public Health be pleased to state the present stage of the construction on the canal based water supply schemes in district Mohindergarh togetherwith the time by which the construction work is likely to be completed ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : "कथन" सदन के पटल पर प्रस्तुत है—

कथन

(क) ग्रामीण

क्रमांक	योजना का नाम	निर्माण की वर्तमान स्थिति	पूर्ण होने की संभावित तिथि
1	2	3	4
1.	नूनीवाला 16 ग्रामों की बढ़ौतरी योजना तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़।	जलघर का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।	योजना जनवरी 1995 में चालू कर दी गई थी तथा शेष कार्य 6/95 तक पूर्ण हो जायेंगे।

1	2	3	4
2.	खातौद 12 ग्रामों की समूह की विस्तार योजना तहसील एवं जिला महेन्द्रगढ़ ।	जलघर के प्रथम चरण के कार्य मार्च 1994 में बना दिये गये थे ।	योजना नहरी पानी उपलब्ध होने पर चालू की जाएगी ।
3.	पालडी 5 गांव की समूह की बढ़ौतरी योजना तहसील एवं जिला महेन्द्रगढ़ ।	जलघर के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है ।	प्रथम चरण के कार्य 6/95 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा इस योजना से 40 एल0 पी0 सी0 डी0 पानी उपलब्ध होगा ।
4.	बढ़ौतरी योजना ग्राम जाटवास समूह 8 गांवों की ।	जलघर के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है ।	प्रथम चरण के कार्य 12/95 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे तथा इस योजना से 40 एल0 पी0सी0डी0 पानी उपलब्ध होगा ।
5.	नौताना समूह के 3 गांव के लिये अलग से जलघर बनाने का कार्य तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ ।	जलघर के प्रथम चरण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।	योजना नहरी पानी उपलब्ध होने पर चालू की जाएगी ।
6.	बढ़ौतरी योजना श्योनाथपुरा समूह 10 गांव का ।	जलघर के प्रथम चरण का कार्य सम्पन्न होने वाला है ।	प्रथम चरण के कार्य 4/95 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे तथा योजना से 40 एल0 पी0सी0डी0 पानी उपलब्ध होगा ।
7.	बढ़ौतरी योजना गुलावाला समूह 11 नम्बर गांव ।	जलघर के प्रथम चरण के कार्य प्रगति पर हैं ।	मार्च 1996 में इस योजना से 40 एल0पी0सी0डी0 पानी उपलब्ध होगा ।
8.	बढ़ौतरी योजना भांखडी 4 गांव का समूह ।	जलघर के प्रथम चरण के कार्यों के लिये टैण्डर 2/95 में स्वीकृत किये गये हैं तथा कार्य आरम्भ किया जा रहा है ।	मार्च 1996 तक इस योजना से 40 एल0पी0सी0डी0 पानी उपलब्ध होगा ।
(ख)	शहरी		
1.	पेयजल योजना महेन्द्रगढ़ शहर ।	जलघर के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है ।	जुलाई, 1995 ।

———

Backlog in Government Jobs

*1112. **Shri Amar Singh Dhanday** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any special scheme under consideration of the Government to wipe off the back-log, if any, in Government jobs for the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the State ; and

(b) if so, the time by which the scheme as refetred to in part (a) above is likely to be materialized?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) व (ख) अनुसूचित जातियों व पिछड़ी श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में बैकलाग को समाप्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है कि इस बैकलाग को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाए ।

Construction of old age homes in the State

*1085. **Sathi Lehri Singh** : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct old-Age Homes in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह) :

(क) नहीं श्रीमान जी, क्योंकि हरियाणा में वृद्धों की देखभाल उनके बच्चों द्वारा ही की जाने की प्रथा चली आ रही है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 100 रुपये प्रतिमास प्रति व्यक्ति की दर से वृद्धावस्था पैंशन 6.39 लाख व्यक्तियों को प्रदान कर रही है ।

(ख) लागू नहीं है ।

Repair of Roads

*1124. **Shri Ramesh Kumar** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the

Government to repair the following roads of district Sonipat—

(i) Sivanaka to Chhathera ;

(ii) Butana to Gangana ;

(iii) Khola to Nijampur; and

(iv) Durana to Jawahara

(b) if so, the time by which the roads as referred to in part (a) above are likely to be repaired ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी अमर सिंह) :

(क) इन (i), (ii), (iii), तथा (iv) सड़कों पर पैच वर्क (मुरम्मत) कर दिया गया है ।

(ख) उपरोक्त (क) के कारण प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Industrially Backward area in the State

225. **Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Industries be pleased to state the names of cities/blocks/areas declared as industrially backward during the period from July, 1991 todate togetherwith the facilities being provided for setting up the industries at the places as referred to above ?

उद्योग मन्त्री (श्री ए० सी० चौधरी) : सूचना सदन के पटल पर रखी है—

'सूचना'

जुलाई 1991 के पश्चात राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 1992 के अन्तर्गत निम्न 76 खण्डों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है ।

[श्री ए० सी० चौधरी]

क्रम संख्या	जिला	खण्ड	क्र० संख्या	जिला	खण्ड
1.	हिसार	1. आदमपुर	5.	जीन्द	1. पिल्लूखेड़ा
		2. बरवाला			2. सफीदों
		3. फतेहाबाद			3. उचाना
		4. अग्रोहा			4. नरवाना
		5. भट्टूकलां			5. अलेवा
		6. उकलाना			
		7. हांसी	6.	सिरसा	1. डबवाली
		8. बास			2. बड़ागूड़ा
		9. नारनौंद			3. ऐलनाबाद
					4. रानियां
					5. श्रीधान
2.	भिवानी	1. बादरा	7.	महेन्द्रगढ़	1. महेन्द्रगढ़
		2. बवानी-खेड़ा			2. कनिना
		3. तोशाम			3. अटैली-नंगल
		4. दादरी–I			4. नंगल चौधरी
		5. सिवानी			5. नारनौल
		6. लोहारू			
3.	कैथल	1. गुहला	8.	रिवाड़ी	1. खोल
		2. पुण्डरी			2. नाहर
		3. राजौंद			
4.	यमुनानगर	1. बिलासपुर	9.	अम्बाला	1. बराड़ा
		2. छछरौली			2. बरवाला
		3. रादौर			3. रायपुररानी
		4. सढ़ौरा			4. मोरनी
					5. नारायणगढ़
					6. पिजौर
			10.	कुरुक्षेत्र	1. लाडवा
					2. थानेसर
11.	करनाल	1. इन्द्री	14.	रोहतक	1. झज्जर
		2. नीलोखेड़ी			2. बेरी
		3. निसिंग			3. कलानौर
		4. असन्ध			4. लाखन-माजरा
					5. सालारास

क्रम संख्या	जिला	खण्ड	क्र0 संख्या	जिला	खण्ड
12.	पानीपत	1. इसराना			6. मातन हैल
		2. मतलोडा			7. सांपला
		3. समालखा			
		4. बापोली			
			15.	गुड़गावां	1. फरुखनगर
13.	सोनीपत	1. खरखोदा			2. सोहना
		2. गोहाना			3. फिरोजपुर झिरका
		3. कथूरा			4. नगीना
		4. गन्नौर			5. तावडू
		5. मुण्डलाना			6. पुन्हाना
					7. नूंह
			16.	फरीदाबाद	1. हथीन
					2. पलवल

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न दस औद्योगिक सम्पदाओं और दो विकास केन्द्रों (एक बावल, जिला रिवाड़ी तथा दूसरा साहा, जिला अम्बाला में) को भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है :—

1. रिवाड़ी
2. धारूहेड़ा
3. भिवानी
4. जीन्द
5. टोहाना
6. हिसार
7. मुरथल (स्पोर्टस गुडज कम्पलैक्स)
8. सिरसा
9. बहादुरगढ़
10. नारनौल

राज्य सरकार इन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये निम्न सुविधाएं/प्रोत्साहन प्रदान कर रही है :—

(क) पूंजी निवेश अनुदान

(i) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की अचल पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये तक है, दिया जाता है ।

[श्री ए० सी० चौधरी]

(ii) राज्य सरकार द्वारा नोटिफाइड एग्रो बेस्ड व फूड प्रोसैसिंग उद्योगों को अचल पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है, दिया जाता है ।

(iii) इलैक्ट्रॉनिक इकाइयों को 25 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है, दिया जाता है ।

(iv) ऐसी पायनियर इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक है, को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है । जिन इकाइयों में 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश है उन इकाइयों को 75 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है ।

(v) ग्रामीण उद्योग योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों को 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है ।

(ख) जैनरेटिंग सैट अनुदान

जैनरेटिंग सैट अनुदान सभी लघु औद्योगिक इकाइयों जिसमें पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इकाइयां भी शामिल हैं, को 1200 रुपये प्रति के० वी० ए० की दर से या जैनरेटिंग सैट की कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, के अनुसार 15 लाख रुपये की सीमा तक प्रति इकाई दिया जाता है ।

(ग) बिक्री-कर से छूट/स्थगन

बिक्री-कर छूट/स्थगन की सुविधा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगिक इकाइयों को उनकी अचल पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तथा बड़े तथा मध्यम उद्योगों को 125 प्रतिशत की दर से 9 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है । ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयां जो विस्तार एवं विविधिकरण करती हैं, को बिक्री कर छूट/स्थगन की सुविधा अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश पर 100 प्रतिशत की दर से तथा बड़े तथा मध्यम उद्योगों को 90 प्रतिशत की दर से 9 वर्ष के लिये प्रदान की जाती है । इलैक्ट्रॉनिक इकाइयां अचल पूंजी निवेश पर 500 प्रतिशत की दर से सात वर्षों के लिये बिक्री कर छूट/स्थगन की पात्र हैं ।

(घ) बिजली शुल्क से छूट

राज्य सरकार सभी नई औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्ष के लिये बिजली शुल्क से छूट दे रही है ।

(ङ) चुंगी शुल्क से छूट

पिछड़े क्षेत्र में स्थापित सभी नई औद्योगिक इकाइयों को स्थायी संयंत्र/भवन सामग्री तथा कच्चे माल पर 9 वर्ष के लिये चुंगी शुल्क से छूट उपलब्ध है ।

(च) मूल्य अधिमान

राज्य सरकार नन्हें व लघु उद्योगों को 10 प्रतिशत की दर से तथा बड़े तथा मध्यम उद्योगों को 5 प्रतिशत की दर से सरकारी खरीद पर मूल्य अधिमान दे रही है ।

(पूंजी निवेश अनुदान, बिजली कर से छूट और बिक्री कर छूट/स्थगन का लाभ नकारात्मक सूची में आने वाली इकाईयों को नहीं मिलेगा। नकारात्मक सूची ग्रामीण औद्योगिक स्कीम के यूनिटों पर लागू नहीं है ।

Arrival of rice and wheat

237. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the total quantity of wheat and rice arrived in the Market Committees (Mandis) of district Faridabad during the year 1994 ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : वर्ष 1994–95 के दौरान 28–2–95 तक जिला फरीदाबाद की मार्किट कमेटियों (मण्डियों) में 1,70,008 टन गेहूं तथा 1,38,296 टन पैडी (चावल) की कुल आमद हुई ।

Lining of distributaries of Agra Canal

238. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for lining of distributaries and drains of Agra Canal; if so, the time by which the lining of the said distributaries are likely to be started/completed ?

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) :

(क) नहीं जी ।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत लागू नहीं होता ।

School buildings declared un-safe

239. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any school building of district Faridabad have been declared un-safe during the year 1994; and

(b) if so, the names of said school buildings togetherwith the time by which these are likely to be repaired ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) फरीदाबाद जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई स्कूल भवन असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Rooms constructed under Black Board Scheme

240. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the rooms constructed under operation 'Black Board' Scheme in Village Jaindapur Tehsil Palwal have been collapsed; and

(b) if so, the names of the officers/officials who are responsible for aforesaid unfortunate incident togetherwith the action taken against the officials involved in the matter ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) अप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला जैन्दापुर में निर्मित कमरे गिरे नहीं हैं । बल्कि भवन निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी आवश्यकताओं को नजरअन्दाज किया गया है ।

(ख) सम्बन्धित विभाग (विकास एवं पंचायत विभाग) द्वारा जिम्मेवारी निर्धारित करने बारे जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर दोषी पाए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएँ/विभिन्न मामले उठाना

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मेरा काल अटैन्शन मोशन राजधानी क्षेत्र बनाए जाने से सम्बन्धित था कि उसमें सारे किसानों की जमीन चली जाएगी और फिर किसानों के पास खेती के लायक कोई जमीन नहीं रहेगी । इससे फरीदाबाद, सोनीपत व गुड़गांव जिला प्रभावित होते हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि इसके बदले में उन किसानों को आप क्या आल्टरनेटिव रोजगार देंगे जिन किसानों की जमीन, सरकार लेने जा रही है क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आधा एकड़ जमीन किसी के पास एक एकड़ जमीन है । आप मेरे इस काल अटैन्शन मोशन का फेट बताएं ।

श्री अध्यक्ष : आप का काल अटैन्शन मोशन डिस-अलाऊ कर दिया है ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक काल अटैन्शन मोशन था । ओलावृष्टि से सम्बन्धित था जिसके कारण कई जिलों में किसान बिल्कुल बरबाद हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह आपका काल अटैन्शन मोशन 10 तारीख के लिये लगा है ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : दूसरा मेरा काल अटैन्शन मोशन था बिजली के बारे में । पिछले तीन सालों में बिजली के दाम बहुत बढ़े हैं बिजली मिल नहीं रही है । हर जगह पर किसान परेशान हैं । मजदूर परेशान हैं । पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान हैं । मैंने यह काल अटैन्शन मोशन रूल 73 के तहत दिया है ।

श्री अध्यक्ष : यह डिस-अलाऊ हो गया है ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप इसको रि-कंसिडर करें । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है । किसान, मजदूर व पढ़ने वाले विद्यार्थी बिजली न मिलने के कारण बड़े परेशान हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपको जब बोलने का समय मिलेगा, उस समय आप अपनी बात कह लेना ।

प्रो0 छतर पाल सिंह : धन्यवाद, स्पीकर साहब, आपने मेरी तरफ तवुज्जह तो दी । मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था जोकि हरियाणा के किसानों को डी0 ए0 पी0, यूरिया आदि खाद देने से सम्बन्धित था ।

श्री अध्यक्ष : यह काल अटैन्शन मोशन आलरैडी आज यानि 8 को लगाया गया है । आप उस वक्त इस पर सप्लीमैन्ट्री पूछ लेना ।

प्रो० छतर पाल सिंह : सर, इसके अलावा मेरा एक और महत्वपूर्ण काल अटैन्शन मोशन है। गवर्नमैंट लाईव स्टाक फार्म हिसार की जमीन चौधरी भजन लाल के लड़के श्री चन्द्र मोहन द्वारा लिये जाने के बारे में आज जन सत्ता अखबार के फ्रंट पेज पर दिया हुआ है। वह अखबार मेरे हाथ में है, (शोर) इसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : छतर पाल सिंह जी, मेरे पास अभी तक आपका काल अटैन्शन मोशन नहीं आया, जब आएगा तो हम कंसिडर करेंगे ।

प्रो० छतर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पास यह आज का जन सत्ता अखबार है । इसकी कापी मैं आपको देता हूं । (शोर)

श्री अध्यक्ष : इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये मैंने भी कुछ कहना है । छतर पाल सिंह जी ने एक अखबार दिखा कर कोई बात करने की कोशिश की । यह पेपर मैंने आज सुबह पढ़ा है । इसे पढ़ कर मुझे भी हैरानी हुई । इसमें लिखा हुआ है कि भजन लाल के लड़के चन्द्र मोहन ने दो कनाल 19 मरले जमीन गवर्नमैंट लाईव स्टाक की मौल ले ली । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं ताकि सदन को असल बात का पता चले । मैं प्रो० छतर पाल सिंह का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे पोजीशन क्लीयर करने का मौका दिया । मेरी बात सुनने के बाद प्रैस वालों की भी और सदन की भी गलतफहमी दूर हो जाएगी । छतर पाल सिंह भी हिसार जिले के रहने वाले हैं । हिसार से सात किलो-मीटर दूर चन्द्र मोहन और कुलदीप की जमीन है । उसका नक्शा मेरे पास है । यह जमीन हिसार-सिरसा रोड पर है । यह जमीन किसी अलाटी की थी । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कहूंगा धर्म और ईमान से कहूंगा । यह जमीन रिकार्ड में दो कनाल 19 मरले है लेकिन मौके पर एक कनाल 11 मरले के करीब है । क्योंकि बाकी जमीन सड़क में चली गई । जो वहां पर नेशनल हाई-वे बना हुआ है, उसमें चली गई है । इस जमीन को साथ वाला काश्त करता था । साथ वाले की जमीन भी चन्द्र मोहन ने ले ली । साथ वाली जमीन को जो आदमी काश्त कर रहा था, उसने 1986 में एप्लीकेशन दे रखी थी कि साथ वाली जमीन मुझे दी जाए ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * * *(शोर)

श्री अध्यक्ष : यह बात रिकार्ड न की जाए ।

चौधरी भजन लाल : अगर किसी ने कोई संस्था बनानी हो, तो मैं इससे

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

दोगुनी जमीन दान में दे सकता हूं । ये सबको अपने जैसा समझते हैं । वहां के डी० सी० ने 1990 में लिखा कि इस जमीन की कीमत साठ हजार रुपए एकड़ लगाई जाए । इतने में इन भाइयों की सरकार चली गई और मैं मुख्य मन्त्री बन गया । यह केस मेरे पास आया । मैंने कहा कि यह गलत है । हालांकि वहां पर मिट्टी डाल कर सड़क को ऊंचा कर रखा है और उस जमीन में से ट्रैक्टर भी नहीं मुड़ सकता फिर भी मैंने कहा कि इसकी कीमत कम से कम एक लाख रुपए एकड़ होनी चाहिये । कागजों में तो वह जमीन दो कनाल 19 मरले है, लेकिन मौके पर एक कनाल 11 मरले है । दाम तो दो कनाल 19 मरले के दिये गए हैं लेकिन असल में जमीन कम है यानि लगभग आधी के बराबर है । अखबारों में लिखा है कि गवर्नमैंट लाईव स्टाक की कुछ जमीन की कीमत पांच लाख रुपये एकड़ की है और कुछ तीन लाख रुपए एकड़ की है । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट लाईव स्टाक की जो जमीन है, वह हिसार में तलाकी गेट के पास है, जहां हस्पताल बना हुआ है, मार्किट बनी हुई है और बस स्टैंड बना हुआ है । मेरे से पहले जो मुख्य मन्त्री थे, मेरे पास लिस्ट है, उन्होंने इस जमीन को 30 और 35 रुपये गज के हिसाब से दे रखा है । मेरे पास 37 आदमियों के नामों की लिस्ट है । यह जमीन चौधरी बंसी लाल के वक्त में भी दी गई और चौधरी देवी लाल के वक्त में भी दी गई है । अध्यक्ष महोदय, इस पेपर में जो लिखा गया है, उससे मुझे बड़ी भारी तकलीफ हुई । किसी बात की हद हो रही है कि बगैर इस बात की तह में जाए, इतना गलत लिखा गया । इस बात को इस तरह से लिख दिया जैसे यह कोई बड़ा भारी स्कैण्डल है । मैं एक बात कहता हूं । सदन में सभी भाई बैठे हुए हैं । यह तो केवल दो कनाल जमीन की बात है । अगर किसी भाई ने किसी संस्था के लिये कुछ बनाना हो तो मैं चार कनाल जमीन फ्री देने के लिये तैयार हूं ।

प्रो० छतर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी दरखास्त है कि एक चीज अखबार में छपी है और उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी दिया है । (शोर) The Rules of procedure and Conduct of Business should be followed in the House. (Interruptions)

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मेरा एक कालिंग अटैन्शन नोशन था कि कुरुक्षेत्र में शराब बंदी के लिये लोग पीसफुल डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया ।

श्री अध्यक्ष : वह कमैंट्स के लिये गवर्नमैंट को भेजा हुआ है । इसके बारे में आप कल पूछ लेना ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, भिवानी, दादरी और लोहारू में हुई ओलावृष्टि के बारे में मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था, उसका क्या फैसला किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : वह 10 मार्च को लगा हुआ है ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्शन मोशन है कि ब्यूरोक्रेट्स ने एक मंत्री के बारे में टीका टिप्पणी की है । यह एक बहुत ही चिन्ता का विषय है ।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में कल पूछ लेना ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्शन मोशन है कि भिवानी जिले में खानक गांव के लोगों की स्टोन क्रैशर के कारण हैल्थ खराब हो चुकी है ।

Mr. Speaker : It is under consideration.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, जो ओलावृष्टि के बारे में कालिंग अटैन्शन मोशन है, वह तो आपने 10 मार्च को लगा दिया, लेकिन मेरा एक काल अटैन्शन मोशन लिफ्ट इरीगेशन के बारे में है, उसका आपने क्या फैसला किया है ।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आप कल पूछ लेना ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

राज्य में यूरिया तथा डी०ए०पी० खाद की कमी सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., regarding acute shortage of D.A.P. fertilizer in district Faridabad and in the areas of Mewat. I admit it. The Calling Attention Notice given by Shri Om Parkash Chautala and 12 other M.L.As. has also been bracketed with this Calling Attention Notice. Shri Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिला फरीदाबाद तथा मेवात के क्षेत्र में डी०ए०पी० खाद की भारी कमी है जिसके कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं । अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे कर अपनी स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : अब चौटाला साहब भी अपना मोशन पढ़ दें ।

@सर्वश्री ओम प्रकाश, सम्पत सिंह, धीर पाल सिंह, अमर सिंह डांडे, बलवन्त सिंह, सुरजभान काजल, जिले सिंह, जयपाल सिंह, कृष्ण लाल, रमेश कुमार, राम कुमार कटवाल, मख्ख सिंह तथा जसविन्द्र सिंह : हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि पिछले दिनों पर्याप्त वर्षा होने से किसानों की रबी की फसल बहुत अच्छी है । इस समय फसलों को यूरिया खाद की अति आवश्यकता है । परन्तु पिछले एक से अधिक मास से यूरिया खाद खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है तथा किसान खाली हाथ घर वापिस आ जाते हैं। भूखे प्यासे किसानों को यूरिया खाद लेने के लिये सारा दिन लम्बी लम्बी कतारों में खड़े होना पड़ता है । कई जगह तो किसानों की जेब कटने की घटनाएं भी हुई । यूरिया खाद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ता है । यूरिया खाद की कमी के कारण किसान एक एक कट्टे के लिये मारे मारे फिर रहे हैं । कई मंडियों में किसानों पर लाठी चार्ज भी हुआ है । जुलाना में यूरिया खाद लेने गये राम कुमार नामक किसान को पुलिस ने पीट पीट कर बेहोश कर दिया । सत्तासीन राजनीतिज्ञों के नजदीकी लोगों ने यूरिया खाद को जगह जगह स्टाक किया है । लोगों को यूरिया खाद का एक कट्टा 161 रुपये की बजाए 200 रुपये से 225 रुपये की दर से ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है । कई स्थानों पर किसानों को ब्लैक में नकली खाद भी सप्लाई की गई जिससे उनकी फसलें खराब हो गई हैं । कुछ व्यापारियों तथा सत्तासीन राजनीतिज्ञों के नजदीकी लोगों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कीटनाशक दवाईयां भी जबरदस्ती खाद के साथ थोंपी हैं जोकि उनको पहले समय पर सप्लाई नहीं की गई थीं । इस बात को लेकर किसानों ने कई जगह प्रदर्शन भी किए हैं । खाद की कमी के कारण किसानों की रबी की फसलें बरबाद हो रही हैं । सरकार अभी तक पर्याप्त प्रबन्ध नहीं कर सकी । खाद प्राधिकृत दुकानों या सहकारी समितियों की बजाए सत्तासीन राजनीतिज्ञों के नजदीकी** लोगों द्वारा बेची जा रही है । इसके कारण एक तरफ किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं तथा दूसरी ओर ब्लैक करने वाले लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं । **डीलरों द्वारा करोड़ों रुपये का घपला किया गया है । सरकार खाद का इन्तजाम करने में बिल्कुल विफल रही है । लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष तथा गुस्सा है । अतः हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें ।

डा० राम प्रकाश : मैं इस गरिमामय सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक एवं लोकहित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले दिनों हरियाणा में किसानों को यूरिया खाद समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सका । इस कारण किसानों को न केवल परेशानी ही हुई अपितु भारी नुक्सान भी हुआ । सम्भवतः कृषि विभाग अनुमान नहीं लगा पाया कि कब कितना यूरिया चाहियेगा या वितरण-प्रणाली दोषपूर्ण थी । मैं चाहूंगा कि कृषि मन्त्री महोदय इस विषय में इस

@Read by Chaudhry Om Parkash Chautala.

*Expunged as ordered by the Chair.

[डा0 राम प्रकाश]
सदन में एक वक्तव्य दे कर विभाग की स्थिति स्पष्ट कर तथा भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु इस दिशा में उठाए गए पगों पर प्रकाश डालें ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज के कृषि मंत्री को किसी प्रकार की इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है । ये लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या किया जाये । इनको यह जानकारी ही नहीं है कि खाद कैसे खरीदी जा रही है और कहां से खरीदी जा रही है? इनको इस संबंध में जानकारी न होने के कारण ग्रो-मोर-फूड की पालिसी के बावजूद किसानों को नुक्सान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपने अपना मोशन पढ़ दिया है । अब आप बैठिये । इन्होंने अपना मोशन पढ़ते समय जो बेईमान शब्द पढ़ा है, उसको एक्सपंज कर दिया जाये ।

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैंने यूरिया की कमी के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था । कल आपने यह कहा था कि उसको विचार-विमर्श के लिए गवर्नमैंट के पास भेजा गया है और उसको एडमिट कर लिया गया है। लेकिन आज उसे सर्कुलेट नहीं किया गया । आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मेरा नाम नहीं है । विपक्ष उसी मसले को उठाता है तो आप उनको मौका देते हैं चाहे वे किसी को * * ही कहें ।

श्री अध्यक्ष : 'बेईमान' शब्द को एक्सपंज कर दिया है ।

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर होने के बावजूद भी क्यों नहीं हमें पढ़ने का मौका दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को इसके साथ क्लब कर दिया गया है ।

डा0 राम प्रकाश : यदि उसे क्लब कर दिया गया है तो इस काल अटैन्शन मोशन में मेरा नाम भी तो आना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष : डा0 साहब, आप इस बारे में सवाल पूछ लेना । Now I would like the Agriculture Minister to make his statement.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

वक्तव्य--

कृषि मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इनकी जानकारी के लिये यह कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के बारे में ये चाहे जितने सवाल पूछें, कितनी ही कालिंग अटैन्शन मोशन्ज दें, मैं उनका जवाब दूंगा। जो सवाल किए जाएं, वे ठीक तो होने चाहिएं। पिछले सैशन में चौधरी कर्ण सिंह दलाल को पता नहीं लगा कि "टिड्डी दल" और टिड्डा" में अन्तर क्या होता है। मैं ग्रास हापर के बारे में कह रहा था लेकिन इनको इसका पता नहीं था (विघ्न) अब ये सवाल यूरिया का पूछ रहे हैं लेकिन जो काल अटैन्शन मोशन इन्होंने लिख कर दिया है वह डी० ए० पी० का है। जो सवाल इन्होंने लिख कर पूछा है जवाब तो उसी का मैंने देना है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Sardar Sahab, you may start to make your statement. (Interruptions.)

Shri Harpal Singh : Sir, there is no shortage of DAP fertilizer either in Faridabad district, Mewat area or in any part of the State. There has been adequate supply of DAP fertilizer in the district of Faridabad and in the areas of Mewat during kharif, 1994 as well as rabi 1994-95. There have been no complaints of shortage of DAP throughout the year. The condition of standing crops in current rabi is excellent and there is no question of damage to crops on account of shortage of DAP.

As regards urea fertilizer, the Govt. of India makes allocation for the State under the Essential Commodities Act. The Govt. of India made allocation of 4.70 lakh M.T. for kharif, 1994 against the consumption of 4.31 lakh M.T. in kharif, 1993. Govt. of India made allocation of 6.20 lakh M.T. for rabi 1994-95 as against the actual consumption of 5.65 lakh M.T. during rabi 1993-94. There is a consumption of 5.57 lakh M.T. urea fertilizer till February, 1995 during the current rabi season against the consumption of 5.45 lakh M.T. till February, 1994 during rabi 1993-94.

There was an adequate supply of urea during kharif, 1994. However, during the current rabi season there were uniform and widespread rains in January, 1995 all over the State and in the entire northern region. This led to spurt in demand of urea simultaneously all over the State. Moreover, during the peak demand period, there was a break-down of urea plant of NFL at Panipat for 20 days. This led to reports of urea shortage in some parts of the State.

The State Government took immediate steps to rush urea fertilizer to all the districts. Hon'ble Chief Minister spoke to the Union Minister for Fertilizer & Chemicals on more than one occasion.

[Shri Harpal Singh]

Officers of the State Govt. maintained constant liaison with the Govt. of India officers to ensure additional and adequate supplies of urea to the State. As a result, during the month of January this year 1,32,308 M.T. urea was received in the State as against 1,04.222 M. Ts. received during January, 1994. Similarly, during February this year 1,37,878 M.T. urea was received as against 86,680 M.T. during the month of February last year. Thus as a result of efiorts made by the State Government during these 2 months of January & February this year, an additional quantity of 79,284 M.T. urea fertilizer has been received in the State as compared to the corresponding period of last year.

89,577 M.T. urea was distributed by HAFED through Cooperative Agencies including Primary Co-op. Marketing Societies and Mini-banks during January & February, 1995 as against 88,221 M. T. during January and February, 1994.

At present there is no shortage of urea in any part of the State.

The Agriculture Department with the help of district administration supervised the distribution of available stocks of urea to the farmers properly. No businessman was allowed to force the sale of insecticides or pesticides alongwith urea. The Department kept a constant vigil and ensured the sale of urea at the rate of Rs. 166/- per bag. Six FIRs have been registered against those unscrupulous persons who attempted to indulge in black-marketing. 750 samples have been drawn as a quality control measure to check adultration of urea fertilizer.

The Agricultural Department rendered all possible assistance to the farmers in getting the fertilizer. There was no lathi-charge on the farmers in connection with the distribution of urea fertilizer. An FIR was registered in the Police Station Julana on the statement of one Shri Ram Kumar against the alleged use of un-parliamentary language by a Head Constable against him. This case was investigated by a senior police officer of district Jind. Shri Ram Kumar has filed an affidavit to the investigation officer that this case was registered due to some mis-understanding and he has no ill-will against the police officer.

The allotment of urea is made by the Govt. of India to the suppliers/manufacturers who further distribute it to their whole-sellers and retail dealers. The Co-operative institutions like hafed, Iffco, Kribhco and HAIC also supply urea in the State. The State Government does not allocate urea to any Agency. Private as well as Govt. agencies/Cooperative institutions directly procure urea fertilizer from the suppliers/manufacturers. Therefore, it is incorrect to say that the uaea fertilizer was sold through businessmen and persons close to the politician in power.

The foodgrain production touched a record level of 102.83 lakh tonnes during the year 1993-94. There was a record production of 30.85 lakh tonnes foodgrains during kharif, 1994

against the target of 29.60 lakh tonnes. As record production of 22.00 lakh of rice and 7.5 lakh tonnes of bajra was achieved. The prospects of standing crops in the current rabi are also very bright.

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप अपना प्रश्न पूछ लें लेकिन लैक्चर न करना।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब बहुत लम्बा चौड़ा अंग्रेजी में पढ़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने तो 166 रुपए का खाद का एक बैग हरियाणा में बेचा गया बताया है जबकि इनकी सरकारी एजैन्सीज ने यह बैग 250 रुपये से 350 रुपये पर बैग के हिसाब से बेचा है मंत्री जी यह बताएं कि इस प्रकार की कितनी शिकायतें इनके नोटिस में आई हैं और उन पर ये क्या कार्यवाही करेंगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सरकारी खजाने का मुंह सिरसा, हिसार, कालका और आदमपुर की तरफ खोल रखा है। मंत्री जी हमें यह बताएं कि 89.577 एम टी० यूरिया में से कितनी आदमपुर और कालका में दी है और कितनी यूरिया हरियाणा के बाकी हिस्सों में दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ौसी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में यूरिया गवर्नमैंट आफ इण्डिया द्वारा दी जाती है। सिर्फ हरियाणा की गवर्नमैंट ही यूरिया को हैफैड और कारपोरेशन के थ्रू बेचती है और यह इसलिये है क्योंकि यह सरकार खुद चोर बजारी में लिप्त है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने आज किसान को नीलामी के कगार पर खड़ा कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब अंग्रेजी में पढ़ा है। कृपया ये हिन्दी में जवाब दें।

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं इन्हें हिन्दी में ही जवाब दूंगा। 11.00बजे (शोर) स्पीकर सर, दलाल साहब समझने की कोशिश तो करते नहीं। यह जो यूरिया है तो यह असैंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में गवर्नमैंट आफ इंडिया कंट्रोल करती है तथा इसकी प्राईस भी वह ही मुकर्रर करती है और इसकी ऐलोकेशन भी किस स्टेट को कितनी खाद जानी है, गवर्नमैंट आफ इंडिया ही करती है। वह ही मैनुफैक्चरर्ज को खाद की ऐलोकेशन भेज देती है कि कौन से मैनुफैक्चरर को कितनी खाद कौन सी स्टेट को कितनी क्वांटिटी में भेजनी है। इसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं है। इसकी केवल भारत सरकार ही एलोकेशन करती है। वह उन्हीं डीलरों के थ्रू स्टेट में खाद भेजते हैं, जिनके डिमांड ड्राफट प्राप्त हो जाते हैं। वह उसी के मुताबिक उसी हैड पर जिस पर डीलर डिमांड करते हैं, चली जाती है। स्टेट गवर्नमैंट का इससे कुछ लेना देना नहीं

[श्री हरपाल सिंह]

है कि कितनी खाद जानी है कहां जानी है। इस खाद के आने में स्टेट गवर्नमैंट की रिकमेंडेशन भी नहीं होती कि कहां कहां पर देनी है और कहां कहां पर नहीं देनी है। स्टेट गवर्नमैंट तो इस बात का ख्याल करती है कि जो हैफेड या एग्रो हैं, कुछ खाद उनके थ्रू भी आनी चाहिए ताकि जो मार्किट प्राईस है, उसको कंट्रोल किया जा सके। हम तो केवल हैफेड या एग्रो के लिये एफर्ट करते हैं। वैसे इस सरकार ने किसी व्यक्ति के थ्रू खाद लाने के लिये नहीं लिखा और न ही उसको लिखने की अथॉरिटी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एवं सदन के नेता से भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हरियाणा सरकार का इसमें कहीं कोई हाथ नहीं होता तथा भारत सरकार ही अपने नियमों के अनुसार खाद की सप्लाई हरियाणा में करती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों न सदन आज एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करे तथा उसको पास करके भारत सरकार को भेजे कि खाद की जो सप्लाई हरियाणा में होती है, उसके बारे में वह हरियाणा सरकार से पूछेगी कि कौन-कौन सी एजेंसियों को खाद दी जाए। तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जिस बात के लिये इंट्रैस्टिड हैं, उसी के लिये बात करें। स्टेट गवर्नमैंट इस बारे में बिल्कुल भी इंट्रैस्टिड नहीं है कि कौन से मैनुफैक्चरर, कितने डीलरों को कितनी खाद बांटते हैं। जहां तक गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखने की बात है, वह स्टेट गवर्नमैंट से एक बात जरूर पूछती है कि आपको इस साल इस फसल के लिये कितनी कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी और अपनी जरूरत को हमारे अफसर दिल्ली में जाकर उनको बता देते हैं कि इस साल इस फसल के लिये हमें इतनी टोटल खाद चाहिए। ऐलोकेशन तो भारत सरकार ही करती है कि कौन-कौन सी कम्पनी से, कौन कौन से मैनुफैक्चरर से कितनी खाद जाएगी। यह वही डिसाईड करते हैं। हम नहीं करते।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वह मौके के मुताबिक हर चीज उपलब्ध कराए, जिससे ग्रो-मोर पालिसी को बढ़ावा मिले। यहां जब सोईंग सीजन में बिजाई शुरु होती है तो सरकार बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाती। नहरों में पानी नहीं चलवाती और बीज के मामले में भी मन्त्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में यही माना है कि समय पर बीज उपलब्ध नहीं होता। जब खाद का समय आया तो खाद उपलब्ध नहीं होती और जब किसानों की फसल मार्किट में आ जाए

तो इनके सरकारी खरीद अदायरे उसको समय पर सरकार की स्पॉट प्राईस के मुताबिक खरीद नहीं सकते । इसी बात को लेकर अभी कर्ण सिंह जी ने बात की तो मन्त्री जी ने हाउस को गुमराह करने की कोशिश की। यह कहा है डी0 ए0 पी0 खाद की कमी नहीं है । यह मैं मानता हूं कि आज अभी नहीं है लेकिन नवंबर में डी0 ए0 पी0 खाद की कमी कैसे हुई जबकि सोईंग सीजन था ? मन्त्री जी को खुद को इस बात का ज्ञान नहीं है । ये तो दूसरों से पूछकर बता देते हैं। यूरिया खाद के 161 रु0 के बैग 300 रुपये प्रति बैग के हिसाब से प्रदेश में बिके हैं। मन्त्री जी कहते हैं कि यह एलोकेशन केन्द्र सरकार की तरफ से होती है, यहां इसको भी स्पष्ट करें कि केन्द्र सरकार की तरफ से जो ऐलोकेशन होती है, वह स्टेट के हिसाब से होती होगी, स्टेट गवर्नमैंट की जिम्मेवारी होती होगी कि वे आगे जिला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर उसकी तकसीम करें । सरकार ने इस प्रकार से अलौटशुदा खाद को किस हिसाब से अलौट किया । क्या डिस्ट्रिक्टवाईज किया है ? थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें कि 10 फरवरी को हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिये 6 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद आई थी । उसमें से 5 हजार मीट्रिक टन अकेले आदमपुर क्षेत्र में गई है । इसको भी स्पष्ट करें कि क्या यह सारी सुविधाएं एक क्षेत्र के लिये हैं या हरियाणा प्रदेश की एक करोड़ 60 लाख जनता को बराबर का अधिकार है ? सरकार की मिली भगत से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास तो नहीं किया गया ? यह कमी क्यों आई और इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह स्पष्ट करें ?

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनरली मैंने बता दिया कि इसका सिस्टम क्या है, खाद कैसे आती है कौन सी एजैन्सी के थ्रू आती है । मैं आनरेबल मैम्बर को यकीन दिलाता हूं कि स्टेट गवर्नमैंट इस मामले में बड़ी विजिलैंट रही है । स्टेट गवर्नमैंट एक दिन भी आराम से नहीं बैठी । मुख्यमन्त्री जी डेली कंटैक्ट करते रहते हैं । एक दम बारिश की वजह से डिमांड आ गई। यह कमी अकेले हरियाणा में नहीं बल्कि सारी कंट्री में आई । पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यू0 पी0, राजस्थान सभी जगह शार्टेज आई । सिस्टम यह होता है कि किसान जैसे फसल बोता है उसके एक महीने बाद फर्स्ट टाटरिंग होती है। बारिश हुई तो किसानों ने सोचा कि इसके साथ ही खाद दे दें, उसकी वजह से डिमांड राईज हुई । सप्लाई पिछले वर्ष से कम तो नहीं थी, पर डिमांड एकदम से राईज करने से, उसमें दिक्कत आई । चीफ मिनिस्टर साहब ने सैंट्रल गवर्नमैंट से कंटैक्ट बनाए रखा और कहा कि वैगन वगैरह जल्दी आने चाहिएं। स्टेट गवर्नमैंट के आफिशियलज ने सारी सारी रात बैठकर मौनिटरिंग की कि कहां पर कितनी शार्टेज है, कहां ज्यादा है । हमें देखना होता था कि सप्लाई एक जगह तो नहीं है । जैसे हिसार के लिये गई

[श्री हरपाल सिंह]
तो हमने हिसार से सिरसा शिफ्ट की, जींद गई तो कैथल भेजी । सोनीपत में ली गई तो रोहतक भेजी, करनाल आ गई तो यमुनानगर भेज दी । इस प्रकार डे-टू-डे मौनिटरिंग की । आफिसर्ज ने शार्टेज को कंट्रोल करने के लिये जो योगदान दिया है, वह सराहनीय है । स्टेट में घूमकर देखें तो आपको पता लगेगा कि इतनी अच्छी फसल बगैर खाद के देने से नहीं हो सकती । अगर किसान को खाद मिली है तो ही फसल अच्छी हुई है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, ये फिर हाउस को गुमराह करने की बात कर रहे हैं । यह तो इनका रोज का रवैया हो गया है । मैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं आप सन्तुष्ट हो सकते हैं क्योंकि मेरे सवाल का तो इन्होंने जवाब दिया ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, इतना लम्बा चौड़ा सवाल न पूछिये । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मैंने तो इन से यह पूछा था कि क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह समय पर किसानों को सारी चीजों का प्रबन्ध करके दे । या तो सरकार के आंकड़े गलत हैं और सरकारी आंकड़ों में यह दर्शाया जाता है कि इतने इतने हैक्टेयर में यह यह फसल बोई गई है । तो क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं है कि उस क्रौप के लिये इतनी इतनी मात्रा में उन्हें खाद भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये कहते हैं कि चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई इसलिये एकदम खाद की ज्यादा जरुरत बढ़ गई तो क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि वह खाद का पहले से ही प्रबन्ध करती ? अब जब बम्पर क्रौप बाजार में आएगी तो क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं होगी कि बारदाने की खरीद का प्रबन्ध करवाए । मैंने मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि स्टेट को कितनी खाद की जरुरत थी और क्या सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने उतनी मात्रा में खाद दी यदि दी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है । (शोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : इसका उत्तर आ चुका है । (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, यह क्या तरीका है कि ये बिना आज्ञा के बीच में उठ कर बोलने लग जाते हैं ? (शोर) मैं सवाल पूछ रहा हूं और मुझे पूछने का अधिकार भी है । ये किस बात पर प्वायंट आफ आर्डर के लिये खड़े हो गये हैं (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : हमें भी अपनी बात कहने का पूरा पूरा अधिकार है * * * * * * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब क्या आपका सवाल पूरा हो गया ? (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता था * *

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आपस में बात न करो । चेयर को ऐड्रैस करो ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अरे किसी की * * * * * * * * * * * * * *

सर, मैं तो आपको मुखातिब होकर कह रहा हूं । ये बीच में वैसे ही उठ खड़े हुए (शोर) सर, मैं जो सवाल पूछ रहा था । मन्त्री महोदय ने उसका जवाब बलांवां देकर इधर उधर भागने की कोशिश की है । मैं इनके जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं (शोर) मेरा अधिकार सवाल पूछने का है और जवाब देने की जिम्मेवारी मन्त्री महोदय की है । अगर मन्त्री महोदय के पास * * * * *

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत के बगैर इन्होंने जो आमने सामने बातें की हैं उनको रिकार्ड न किया जाए । (शोर) इन बातों की कोई जरूरत नहीं है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, इनका बीच में खड़े होकर बोलने का कोई तरीका था ? आखिर हाउस का कोई डेकोरम होता है (शोर) जिन लोगों की *

श्री अध्यक्ष : इन बातों को रिकार्ड न किया जाए ।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इस जवाब में क्लीयर था, जो इनको मैंने पढ़कर सुनाया । उसमें यह था—

"The Govt. of India made allocation of 4.70 M.T. for Kharif 1994 against the consumption of 4.31 lakhs M.T. in Kharif 1993".

4.70 मीट्रिक टन खाद हमें सरकार ने अलाट की । उससे पहले जो लगी थी, वह थी 4.31 लाख टन और उससे बढ़कर हमने डिमांड की और उसी

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[श्री हरपाल सिंह]

वजह से हमें खाद और फालतू मिली। और आज जो जनवरी-फरवरी में खाद आई है वह पिछले साल जनवरी-फरवरी से ज्यादा आई है । इसको फिगर्ज के साथ आप देख सकते हैं । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह भी था कि किस किस जिले में कितनी कितनी अलाट की गई (शोर) 10 तारीख को हिसार के अन्दर 6 हजार मीट्रिक टन खाद आई और उसमें से लगभग 5 हजार मीट्रिक टन खाद केवल आदमपुर के इलाके में दी गई । क्या कृषि मन्त्री महोदय को इस बात का ज्ञान है ? अगर आपकी जानकारी है तो बताएं कि ऐलोकेशन किस हिसाब से हुई ?

श्री हरपाल सिंह : मुझे यह ज्ञान है कि जहां भी खाद की शार्टेज थी वहां हमने खाद पहुंचाई है । आज मैं खुशी से कहता हूं कि किसान की फसल टाप क्लास है और बहुत बढ़िया है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है मैंने ऐलोकेशन के बारे में पूछा था ।

श्री हरपाल सिंह : जहां जहां पर यूरिया खाद के रेक गए, उनकी लिस्ट मेरे पास है । अम्बाला में दो रेक, यमुनानगर में 10, कुरुक्षेत्र में 5, कैथल में 7, करनाल में 11, रोहतक में 6, सोनीपत में 7, भिवानी में 2 और रिवाड़ी में एक रेक गया ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आप इसकी क्वांटिटी बताएं ।

श्री हरपाल सिंह : ये रेकस सिर्फ डीलर्ज की डिमांड पर लगते हैं । मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जिस डीलर का मैनुफैक्चरर के पास डिमांड ड्राफ्ट जाता है, उस डीलर के यहां वह रेक भेज देता है । उसके बाद सभी जगहों पर डिस्ट्रिब्यूशन पूरी कर दी गई ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने आदमपुर का जिक्र किया कि वहां पर सारा बीज और खाद बांट दिया, बाकी जगहों पर नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छे किसान हैं और आप जानते हैं कि खाद की कमी क्यों आई । इस बारे में मन्त्री जी ने भी तफसील से बताया है लेकिन इनका दिमाग बहुत मोटा है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एक तो सारे देश में एकदम इतनी बरसात हो गई । इस मौसम में इतनी ज्यादा बरसात बहुत सालों के बाद हुई है, इसलिये एकदम यूरिए की मांग बढ़ गई ।

श्री धीर पाल सिंह : बारिश तो 15 जनवरी के आस पास हुई थी, जबकि डिमांड 18 दिसम्बर के आस पास बढ़ी थी। तो दिसम्बर के महीने में तो बारिश नहीं हुई थी। आप सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मांग बढ़ गई। हमें इस बारे में ज्यों ही इत्तलाह मिली उसी समय हमारे मन्त्री श्री हरपाल सिंह जी, हमारे डायरैक्टर एग्रीकल्चर, चीफ सैक्रेटरी और प्रिंसिपल सैक्रेटरी और मैंने पूरी कोशिश की। तीन दफा भारत सरकार के जो कृषि मन्त्री श्री राम लखन यादव जी हैं, जो फर्टीलाइजर को डील करते हैं उनसे बात करने की कोशिश की। मुझे पता लगा कि वे बिहार में गए हुए हैं तो मैंने उनसे पटना टैलीफोन पर बात की कि हमारे यहां यूरिया खाद की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिये आप मेहरबानी करके हमें जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा खाद रिलीज करने की कृपा करें। हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश दो ही ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करके सारे देश के लोगों का पेट भरते हैं। उनसे मैंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी खाद के रेक रवाना करें। उन्होंने स्पैशल खाद के रेक भिजवाए। उसके बाद तीन चार दिन के अन्दर ही सारी समस्या का समाधान हो गया। इनको आदमपुर का फोबिया हो गया और कह दिया कि वहां पर 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया भेज दिया गया। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मैंने 6 लाख मीट्रिक टन नहीं कहा मैंने तो 6 हजार मीट्रिक टन कहा है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : आपने पहले 6 लाख मीट्रिक टन कहा था। आप रिकार्ड निकाल कर देख लें। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मैंने पहले 6 लाख बोल दिया था लेकिन साथ ही मैंने इसको ठीक करके 6 हजार मीट्रिक टन भी कहा था। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपने पहले 6 लाख कहा था फिर बाद में 6 हजार मीट्रिक टन कहा था।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैंने पहले 6 लाख बोल दिया था लेकिन उसी वक्त 6 हजार मीट्रिक टन कह दिया था।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनका दिमाग मोटा है। इनके दिमाग में बात पहुंच गई और इन्होंने 6 हजार की बजाय 6 लाख कह दिया। सारी स्टेट में 4 लाख 70 हजार मीट्रिक टन तो खाद आई है। (शोर)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आपके मन्त्री मेरी बात का जवाब नहीं दे सके । आप अपने मन्त्री से कहें कि वे तैयारी करके हाउस में आया करें । हमने चार दिन पहले काल अटैंशन मोशन दिया था ।

चौधरी भजन लाल : आपने 6 लाख बोल दिया । 6 लाख मीट्रिक टन खाद तो सारी स्टेट में नहीं आया । हमारी तरफ से इनको यह सुन गया होगा कि यह 6 हजार मीट्रिक टन है इसलिये इन्होंने बाद में 6 हजार मीट्रिक टन कह दिया । चौटाला साहब, नेहरा साहब को बार बार यह कह रहे थे कि जिसकी जमानत जब्त हुई हो, वह क्या बोल सकता है ? मैं कहता हूं कि जिनके बाप की जमानत जब्त करवा रखी हो, वह हमारे सामने इस तरह की बातें नहीं कह सकता । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मेरी और मेरे बाप की जमानत कभी भी जब्त नहीं हुई । आप * * * बोल कर हाउस को गुमराह कर रहे हैं । आप असत्य बोल रहे हैं । मेरे बाप की कभी भी जमानत जब्त नहीं हुई । हाउस में ऐसे लोग बैठे हैं, जिनकी मैंने जमानत जब्त करवा रखी है ।

चौधरी भजन लाल : भजन लाल ने आपके बाप को आदमपुर से हराया था या नहीं । इस बारे में बताएं । (शोर) आदमी को बार बार घमंड से बात नहीं करनी चाहिए । जो नेहरा साहब ने कहा था, वह सुनने की हिम्मत आप में होनी चाहिए । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : हम कोई गलत बात नहीं कहते । मेरे बाप की कभी भी जमानत जब्त नहीं हुई । आप यह साबित कर दें कि मेरे बाप की कभी जमानत जब्त हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । आप हाउस को गुमराह कर रहे हैं । यह कोई तरीका नहीं है । आप हर वक्त हाउस को गुमराह करने की बात करते हैं । जो सदन में लिखा हुआ है उसको भी ध्यान में रखा करें । (शोर)

चौधरी भजन लाल : भजन लाल ने चौधरी देवी लाल को 1972 में हराया था या नहीं । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : : इस देश में इन्दिरा गांधी भी हारी थी और दूसरे लोग भी हारे हैं । अगर आज चुनाव करवा दिए जाएं तो आपकी तरफ जितने बैठे हैं, इनमें से एक भी चुनाव जीत कर नहीं आ सकता । (शोर)

चौधरी भजन लाल : और आएं या न आएं कम से कम आप नहीं आएंगे (शोर)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आप आज ही इस्तिफा दे दें और चुनाव करवा दें । हम भी अपने इस्तीफे दे देते हैं । चुनाव हो जाएं अगर आप में से एक भी चुनाव जीत कर आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा । (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat.

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इलैक्शन की बात कर दी । ये अपनी बात कहते हुए बड़े आवेश में आ जाते हैं । इन्होंने कहा कि मैं इनकी जमानत जब्त करा दूंगा । आज तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कभी भी जनरल इलैक्शन में चुनाव जीत कर नहीं आए । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि मैं जमानत जब्त करा दूंगा मैंने तो यह कहा है कि आज इलैक्शन करवा कर देख लें, इनमें से कोई दुबारा मैम्बर बनकर नहीं आएगा । (शोर एवं व्यवधान) यह हाउस में गलत बात कह कर हाउस को गुमराह करते हैं । जो बात मैंने कही है, उसको मैं मानता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब आप बैठिए । जो मेरी परमिशन के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाये ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * *

श्री वीरेन्द्र सिंह : : स्पीकर साहब, मैं यह गुजारिश कर रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज तक कभी भी जनरल इलैक्शन में चुनाव जीत कर नहीं आए । हमेशा जब भी ये चुनाव जीते हैं तो बाई इलैक्शन में चुनाव जीत कर आए हैं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आपकी सरकार के रहते हुए बाई इलैक्शन में विपक्ष का आदमी जीत कर आए, कोई छोटी बात है । मैं वहां से 19 हजार मतों से जीत कर आया हूं । सरकार के नाक में दम करके चुनाव जीता हूं । मेरी जब सरकार होती है तो कभी मैं अपने क्षेत्र में नहीं जाता । ये यहां पर @ @ @ करने में लगे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : ये टोलरेट कर नहीं सकते ।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

@Expunged as ordered by the Speaker.

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, आप चौटाला जी को कहिए कि ये सभ्य ढंग से बात करें। यह इनका कोई बोलने का तरीका है कि * * * * कर रहे हैं। (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं यही कह रहा था कि जब भी ये चुनाव जीते तो बाई इलैक्शन ही जीते हैं। अब भी बाई इलैक्शन जो ये जीत कर आये हैं वह भी किसी मुख्यमन्त्री की कृपा से जीत कर आए हैं। उनका नाम तो अब मैं नहीं बताउंगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के रहमो कर्म पर चुनाव नहीं जीत कर आया। मैं तो मतदाताओं के रहमो कर्म से चुनाव जीता हूं। (शोर) बाई इलैक्शन जीतना कोई आसान काम नहीं है। सारे विपक्ष की तरफ से आफर है कि आप जनरल इलैक्शन करवा लें पता लग जाएगा कि कौन जीतता है ? (शोर) * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मेरी परमिशन के बगैर जो बोला जा रहा है, रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आदमी को कभी घमण्ड नहीं करना चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : अब आप यह मामला बन्द करें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : जब ये कोई बात कहते हैं तो हमको उसका जवाब तो देना पड़ता है। श्रीमान जी ने कहा कि किसी के रहमो कर्म पर नहीं जीतते। अभी आगे इलैक्शन आएगा तो इनको बता देंगे। (विघ्न तथा शोर)

आवाजें : हम सभी आफर करते हैं। ये लोग इस्तीफे दे दें और इलैक्शन लड़ कर देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग इस बात को यहीं बन्द करें (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी 5-4 दिन पहले जो इलैक्शन हुआ, वह भी मैं इनको बता देता हूं कि वहां क्या हुआ (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न एवं शोर) कर्ण सिंह जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें। आप किस लिए खड़े हो गये हैं (विघ्न एवं शोर)

* Expunged as ordered by the Chair.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज से 5 दिन पहले एक इलैक्शन हुआ था । * * * * * *

श्री अध्यक्ष : अब इस मामले पर और डिस्कशन नहीं होनी चाहिए । (शोर) सतबीर सिंह जी आप अपनी सीट पर बैठिये । (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठें । (शोर) आपको बोलने के लिए बाद में समय दिया जाएगा । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं । क्या यह इनका अधिकार नहीं है । इनको बोलने का टाईम दिया जाना चाहिए । (विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आपको बाद में टाईम देंगे । आप फिलहाल बैठिये । (विघ्न) जो ये बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं आएगा ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : इससे पहले लीडर ऑफ दि हाउस ने जो कहा है वह भी रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए । वह सब एक्सपंज होना चाहिए । (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह गुजारिश है कि अगर कादयान साहब की बात रिकार्ड नहीं होनी है तो फिर लीडर ऑफ दि हाउस ने जो बात कही है, वह भी रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : 'इलैक्शन' वाली जो बात है, वह सारी रिकार्ड न की जाए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में खाद के बारे में बात चल रही थी । मैं आदमपुर का नुमाइन्दा हूं और 1968 से लगातार वहां से मैं विधायक हूं । बीच में एक बार मैंने इलैक्शन नहीं लड़ा तो लोगों ने मेरी धर्मपत्नी को वहां से जिताया । ये श्रीमानजी हर इलैक्शन में नये हल्के से खड़े हो जाते हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये किसी का कोई काम नहीं करते इसलिए इनको वोट कौन देगा ? इन्होंने कहा कि खाद की कमी है । मुझे भी लोगों ने कहा कि खाद की कमी है । मैंने मौके पर ही डिप्टी कमीश्नर को कहा कि वे इस मामले को देखें । सभी जगह पर खाद की कमी थी । जहां कहीं भी कमी थी, हमने उसको पूरा करने की कोशिश

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[चौधरी भजन लाल]

की । इस बारे में श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा । चौधरी अमर सिंह जी ने भी कहा । मैंने इस बारे में तवज्जूह दी और हरपाल सिंह जी से भी बात की । (शोर एवं व्यवधान) मैं गलत बात नहीं बोलता हूं । हम अपने इलाके के लोगों की तकलीफ को सुनते हैं । मैं चीफ मिनिस्टर बाद में हूं और उससे पहले पब्लिक का नुमायंदा हूं । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं रही है । इन्होंने जब राज छोड़ा था तो उत्पादन 90 लाख टन था और आज 104 लाख टन है । आज उत्पादन 14 लाख टन बढ़ा है । अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों को बहुत अच्छे भाव दिए हैं जिससे उनको 29 सौ करोड़ का फायदा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम पब्लिक के नुमायंदे हैं और हमें उनकी बात कहनी चाहिए । जैसा कि एग्रीकलचर मिनिस्टर जी ने कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर राम प्रकाश जी, आप बैठे-बैठे इतना न बोलें । हमें आपका भी ध्यान है । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हरियाणा का किसान खाद के लिए हा-हा कार मचा रहा है और उन्हें खाद नहीं मिल रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने के लिए उसकी कुछ बैक-ग्राउन्ड भी तो बतानी पड़ेगी । साथ ही हमें यहां पर किसानों की बात भी तो पहुंचानी है । अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो और कौन पहुंचाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने क्या कोई प्रश्न पूछना है ?

प्रो० छत्तर पाल सिंह : हां, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछने जा रहा हूं । पहले आप हाऊस में व्यवस्था मेनटेन करें ताकि हम किसानों की बात कह सकें । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बिठाएं । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए इकट्ठे खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं । छत्तर पाल सिंह जी आप प्रश्न पूछें ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि खाद की सप्लाई हरियाणा के किसानों को की गई है । यह सदन को भ्रमित करने वाला जवाब था । (शोर) इनके पास लोगों की शिकायतें आती रहती थीं । सारे लोगों को परेशानी थी कि खाद की ब्लैक मार्किटिंग की गई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छत्तर पाल जी, आप सवाल पूछिए ताकि उसका जवाब दिया जा सके ।

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मैं सवाल ही कर रहा हूं । आप तो यहां पर हरियाणा के हितों के लिए बैठे हैं और उसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं । (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठिए । पहले उनका सवाल पूरा हो जाने दीजिए । (विघ्न) छत्तर पाल जी, आप अपना सवाल पूछिए ।

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, हरियाणा में खाद की ब्लैक मार्किटिंग हुई । खाद की सप्लाई की कमी की वजह से लोगों ने नकली खाद भी हरियाणा के देहातों में दी । उसका कारण यह था कि हरियाणा के * * * की नीयत को देखकर लोगों को इस बात का बढ़ावा मिला । (विघ्न) सर, मेरा प्रश्न यह है कि खिराई गांव के लोगों की शिकायत थी कि वहां पर नकली खाद वितरित की गयी । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : 'मुखिया' शब्द को रिकार्ड से निकाल दिया जाए । छत्तर पाल सिंह जी, क्या आपका सवाल पूरा हो गया है ? (विघ्न)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : सर, ये लोग मुझे बीच में इंट्रप्ट कर रहे हैं । * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए । आप सवाल तो कोई पूछ नहीं रहे । अब आप बैठिए । (व्यवधान)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी आदमपुर से इस्तीफा देकर देख लें और मैं भी खिराय से इस्तीफा देता हूं । उसके बाद वहां से इलैक्शन लड़ लें । तब सारा फैसला हो जाएगा । वैसे भी ये चुनाव तक तो मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं हैं । (विघ्न) सर, मैं कायदे की बात ही कर रहा हूं । आज बड़ी अनकांस्टीट्यूशनल बातें यहां पर हो रही हैं * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : अभी जो ये बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए । Please take your seat.

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, फिर यह सरकार कैसे चलती रहेगी ? सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा का नहीं हो सकता ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप या तो क्वैश्चन पूछें या फिर बैठ जाएं । (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । आप इस हाउस की कार्यवाही पिछले चार साल से अध्यक्ष के तौर पर चला रहे हैं और अभी शायद एक या सवा साल और चलाएंगे । उसके बाद तो शायद आप मंत्री बन जाएं । मैंने यह बात पिछले सदन में भी कही थी और आज फिर मैं वही बात दोहराता हूं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो परम्पराएं, जो व्यवस्था या जो रूल्ज हैं—बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, वह हाउस के हैं । हाउस एक अथॉरिटी है । आप हमारे प्रिविलेजिज और हमारे जो राईट्स हैं, उसके कस्टोडियन हैं । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मैम्बर्ज के राईट्स की जहां तक बात है, उसको पूरा प्रोटैक्ट करना आपका फर्ज है । काल अटैंशन मोशन पर आप तमाम मैम्बर्ज को सवाल पूछने का हक देते हो । ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा । पार्लियामैंट में यह प्रोसीजर है कि काल अटैंशन मोशन ऐडमिट हो जाएगी तो जिन मैम्बर्ज ने वह दी है, उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है और मिनिस्टर को उसका जवाब देने का पूरा हक है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अब 11 बजकर 40 मिनट हो गए हैं । इस सवा घंटे में न तो सवाल पूछे जा सके हैं और न कोई जवाब दे सका है । इससे हाउस का सवा घंटा बर्बाद हुआ है । (विघ्न) सवाल पूछे जाएं तो जवाब आते हैं, भाषण देने से नहीं आते हैं । अगर भाषण की परम्परा आप ठीक समझते हैं तो रूल्ज में अमैंडमैंट कीजिए कि जब भी काल अटैंशन मोशन हाउस के सामने आए तो एक-डेढ़ घंटे का टाईम उस पर चर्चा के लिए मुकर्रर होगा । Please do not make farce of the House and this is your responsibility and your duty to protect the interest of the members. That is what I have been repeatedly saying for the last 3½ years that the Parliamentary procedure followed for calling attention motions is not conducive and in the interest of the members rights. मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ सवाल पूछने में क्यों सवा घंटा लगता है ? हमें गवर्नर एड्रैस पर भी बोलना है । दूसरी बातें भी कहनी हैं । एक काल अटैंशन मोशन पर 15 मिनट से ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए । अगर आप इजाजत देते हैं तो समय निर्धारित कर दें एक घंटा या सवा घंटा । जिन लोगों ने काल अटैंशन मोशन दी है, वे अपनी बात कहेंगे और मंत्री या मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे । यह प्रथा पड़ी तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष : पहली बात तो यह है कि अगर एक काल अटैंशन मोशन पर 17 मैम्बर्ज के नाम हों तो 17 के 17 मैम्बर्ज को पूरी तरह बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे काफी टाईम चला जाता है । इसलिए एक पार्टी से सिलैक्टिड मैम्बर्ज को बोलने दिया जाता है और वे कोऑपरेट भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने यूरिया खाद की कमी के बारे में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, मैं उसके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक और बात जानना चाहता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि एन० एफ० एल० का पानीपत यूरिया प्लांट बंद रहा, उसकी वजह से अव्यवस्था हुई। यह प्लांट कब से कब तक बंद रहा था ? क्या यह सारा यूरिया एन० एफ० एल०, पानीपत से आता है ? अगर यह एकमात्र सोर्स नहीं है तो कमी का यह कारण कैसे रहा ? मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यह प्लांट जो समय पर खराब हुआ है, दोबारा खराब न हो इसके लिए क्या व्यवस्था की है ? आपके द्वारा मंत्री महोदय से गुजारिश है कि खाद की खपत का उनके विभाग ने जिलेवार क्या-क्या अनुमान लगाया था और वह अनुमान किस आधार पर लगाया गया था ? क्या वह अनुमान इस आधार पर तो नहीं लगाया गया था कि समय पर बारिश नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष : एन० एफ० एल० केन्द्र का है न कि स्टेट गवर्नमैंट का।

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुख्यमन्त्री महोदय ने सारी बात को एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जो सिचुऐशन अब बनी है, हर साल नहीं आती। एन० एफ० एल० का जो प्रोडक्शन प्लांट है, वह जनवरी के अन्त में मशीनरी खराब होने की वजह से बन्द रहा और बड़ी कोशिश के बावजूद 20 दिनों के बाद चालू किया गया। लेकिन मैं डाक्टर साहब को बताना चाहता हूं शायद उनकी नालिज में यह नहीं होगा कि एन० एफ० एल० का जो प्लांट है, वह स्टेट गवर्नमैंट का नहीं है, वह केन्द्र का है। हम तो एम० डी० वगैरह को उसकी देखभाल के लिये ही कह सकते हैं ताकि वह चालू रहे। (शोर)

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। (शोर) ये मुझे क्या बताना चाहते हैं ? मैंने कैमिस्ट्री में पी० एच० डी० कर रखी है और मुझे पता है कि यूरिया कैसे बनता है। मैं तो उनसे यह जानना चाहता हूं एन० एफ० एल० किस तारीख से किस तारीख तक बन्द रहा ?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, उन्होंने एक बार बता दिया कि एन० एफ० एल० का प्लांट 20-21 दिन बन्द रहा। यह बहुत है। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि आप ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय से यह कहें कि वे तैयार हो कर हाउस में आया करें। अगर वे तैयार हो कर नहीं आ सकते तो आप मुख्य मन्त्री महोदय से कहें कि जिस प्रकार से उन्होंने इरीगेशन और पावर को दो विभागों में बांट दिया है, उसी तरह से इनके ऐग्रीकल्चर विभाग किसी और को दे दिया जाए और इनको केवल रटड फार्मिंग का विभाग ही दे दें जिसकी इनको खूब नालिज है। ऐग्रीकल्चर की नालिज इनको शायद नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं । (शोर)

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके समय में जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी या लोकदल की सरकार थी और अब की चौधरी भजन लाल जी की सरकार, जोकि 1991 में बनी थी, आज उसे चार साल होने जा रहे हैं, दोनों समय की प्रोडक्शन को देख लें कि उस वक्त प्रोडक्शन क्या थी और आज क्या है ? इनको सही पोजीशन का पता चल जाएगा । (शोर) ये आज किसानों के हितैषी बन रहे हैं । जरा फिगर्ज को सुन लें तो इनको पता चल जाएगा । स्पीकर सर, उस समय पैडी का रेट जो दिया गया था, वह 205 रुपये था और आज की सरकार ने उसी पैडी का रेट दिया है 360 व 380 रुपये । 155 रुपये का इन तीन सालों में फर्क है । (शोर) इनके समय में गेहूं का रेट था 235 रुपए क्विंटल और आज उसका रेट 380 रुपए है यानी 145 रुपए फालतू है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से कुछ पूछना भी चाहूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा । जो इनको जानकारी नहीं है वह जानकारी मैं इनको दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप केवल सवाल पूछें ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, जो इस साल खाद की कमी हुई, उसके लिए केवल हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि सैंट्रल गवर्नमैंट भी जिम्मेदार है । वह इसलिए है कि तीस लाख टन खाद इम्पोर्ट होती है । * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो आदमी सदन में अपने आपको डिफैंड नहीं कर सकता, उसके नाम से बात रिकार्ड में न लायी जाए ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : जहां तक हरियाणा गवर्नमैंट का ताल्लुक है, खाद की एलोकेशन प्लांटवाईज होती है । यह नहीं है कि अगर एन0 एफ0 एल0 खराब हो गया तो सारी खाद यहां से ही मिलनी थी । सारे देश के प्रदेशों में खाद की एलोकेशन मन्थ वाईज होती है और सुनिश्चित किया जाता है कि हर महीने हर प्रदेश में टाईम पर इतनी खाद पहुंचेगी । जैसे डी0 ए0 पी0 दो तीन महीने में पहुंचाना है इसी तरह से यूरिया भी नवम्बर-दिसम्बर तक सारा पहुंच जाना चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी एलोकेशन के हिसाब से आपको कितनी खाद पहुंची और उसमें कितनी कमी रही । कमी इसलिए रही कि इसमें मिस-मैनेजमैंट है । आपने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है क्योंकि आपने कहा कि प्राइवेट डीलर्ज ने मैनुफैक्चरर्ज के पास पैसा जमा करवा रखा होता है इसलिए वे उसको खाद

* Not recorded as ordered by the Chair.

भेज देते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजेंसी खाद को एक निश्चित जगह पर देती है क्योंकि उनका प्वायंट तय होता है वहां खाद आती है उसके बाद आपका मंत्रालय उसे आगे बांटता है। उसमें भी आप प्राईवेट डीलर्ज को ज्यादा खाद देते हैं और सरकारी एजेंसीज को कम देते हैं । आपने खुद माना है कि 6 जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 750 सैम्पल्ज में से कितने सैम्पल फेल हुए ।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, कादयान साहब ने जो बात पूछी है वह मैंने काल अटैंशन के जवाब में बता दी थी । उस समय मैंने जनवरी-फरवरी की सारी डिमांड बता दी थी । मेरे पास मन्थली रिपोर्ट भी है । मैंने आपको टोटल बताया था कि इतनी डिमांड थी । हमारे पास जो जनवरी में खाद आना था वह पहले से ज्यादा आया ।

श्री सतबीर सिंह कादयान: आप यूरिया के बारे में बताएं ।

श्री हरपाल सिंह : अक्तूबर में यूरिया की बात नहीं होती । अक्तूबर में तो डी0 ए0 पी0 आता है । (विघ्न) आप अगर इस बारे में नहीं जानते तो कृपया बीच में न बोलें । सारे किसान जानते हैं कि रबी की सोइंग अक्तूबर-नवम्बर में होती है और उस वक्त डी0 ए0 पी0 की मांग होती है, यूरिया की मांग नहीं होती । स्टेटमैंट से पढ़ कर मैंने बताया था कि खरीफ 1994 में 4.31 लाख मीट्रिक टन की खपत 12.00 बजे की तुलना में भारत सरकार द्वारा खरीफ 1994 के लिए 4.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया का प्रावधान किया गया था और रबी 1993-94 के दौरान 5.65 लाख मीट्रिक टन की वास्तविक खपत की तुलना में भारत सरकार द्वारा रबी 1994-95 के लिए 6.20 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया गया ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : आप मंथली इज टारगेट बताएं ।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, जनवरी में 1,32,308 मीट्रिक टन आया और फरवरी में 1,37,878 मीट्रिक टन आया । (शोर)

मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनाउंसमैंट करना चाहता हूं । आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है । इस अवसर पर मैं राज्य में सभी माताओं, बहनों एवं बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं । मैं बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी प्रगति एवं विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, क्योंकि जब तक करीब 48 प्रतिशत वर्ग का विकास नहीं किया जाता तब तक समाज की स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो सकता । सरकार की नवीनतम स्कीम

[चौधरी भजन लाल]

"अपनी बेटी अपना धन" और लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा इस बात का प्रतीक है । मेरी राज्यवासियों से अपील है कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं । उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित करें । आज सरकार ने, जो महिलाएं सर्विस में हैं, उनको आज की छुट्टी देने का फैसला किया है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब राज्यपाल के अभिभाषण पर डिस्कशन होगी । अब श्री सम्पत सिंह जी बोलेंगे ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी कालिंग अटेंशन मोशन जो गवर्नमैंट लाईव स्टाक फार्म हिसार के बारे में है, का आपने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : नो नो, आप बैठिए । अब श्री सम्पत सिंह जी बोलेंगे ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : छतरपाल सिंह जी, आप बैठिये । (व्यवधान) आप बिना इजाजत से बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं । (व्यवधान) मेरी परमिशन के बगैर जो कुछ बोला है, वह रिकार्ड न किया जाए । (व्यवधान) Please take your seat.

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, आप * * * *

(इस समय प्रो० छत्तर पाल सिंह सदन में आपत्तिजनक ढंग से खड़े हो गए और अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बिना इजाजत से बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप अपनी स्पीच शुरू करें ।

प्रो सम्पत सिंह (भट्टू कलां) : स्पीकर साहब, परसों महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर आने का कष्ट किया था और उसके बाद अपना अभिभाषण पढ़ने का कष्ट किया, उनका उनको कष्ट हुआ, उसका कष्ट हमें भी हुआ और खेद भी है । स्पीकर साहब, सारे साल की सरकार की जो कारगुजारियां होती हैं, उनका लेखाजोखा गवर्नर ऐड्रैस में होता है । पिछले साल सरकार ने क्या-क्या किया और

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

आगे आने वाले साल में सरकार क्या-क्या करने जा रही है, यह लेखा-जोखा गवर्नर ऐड्रैस में होता है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सरकार आगे क्या करने जा रही है, वह कतई डायरैक्शनलैस है । इसके बारे में कोई बात इस ऐड्रैस में नहीं है। स्पीकर साहब, अखबारों में सरकार की परफारमैंस के बारे में डिफैंट पोलिटिकल पार्टीज और सोशल आर्गेनाइजेशन्ज की टिप्पणियां आती हैं । मैं ज्यादा डिटेल्ज में न जाते हुए अखबारों के जो हैडिन्ज/टाईटल्ज छापा हुए हैं, उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा । मैं सबसे पहले ट्रिब्यून अखबार में जो टिप्पणी आई है, उसका जिक्र करना चाहता हूं । इसमें लिखा है—"लो अचीवमैंट ईयर फार हरियाणा" ।

वाक आउट

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री चन्द्रमोहन ने जो जमीन खरीदी * * *

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बार-बार कहा है कि आप बिना इजाजत से न बोलिए । जिस ढंग से आप खड़े हैं, यह ठीक नहीं । (व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठिये ।

(प्रो० छत्तर पाल सिंह जी उसी ढंग से खड़े रहे और बोलते रहे ।)

जो कुछ ये कह रहे हैं, यह रिकार्ड न किया जाए । (व्यवधान)

चौधरी श्याम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब, आप कैसे बोल रहे हैं, आपको बोलने की मैंने इजाजत नहीं दी । आप बैठिए ।

(इस समय श्री श्याम प्रकाश बेरी तथा प्रो० छत्तर पाल सिंह दोनों इकट्ठे बिना इजाजत से बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जो कुछ आप बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं होगा । (व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इनके बोलने का यह ढंग ठीक नहीं है । इस तरह से हाउस की कार्यवाही नहीं चलेगी, ये बार बार चेयर को डिफाई कर रहे जो ठीक नहीं है । (दोनों सदस्य उसी ढंग से बोलते रहे) स्पीकर साहब, इनके एटीच्यूड को देखते हुए मैं एक रैजोल्यूशन लाना चाहता हूं कि छत्तर पाल सिंह जी को पूरे सैशन के लिए हाउस की कार्यवाही से निकाला जाए ।

---

*Not recorded as ordered by the Chair

श्री अध्यक्ष : ठीक है, श्री सम्पत सिंह जी, आप अपनी स्पीच जारी रखें।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अखबारों में जो टिप्पणियां आई हैं, वे सरकार के किए गए कार्यों के बारे में आई हैं। इस पिछले एक साल में क्या कुछ सरकार की कारगुजारी रही है, उस बारे में .....

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुन लीजिए। चन्द्रमोहन के इस केस की एन्क्वायरी होनी चाहिए ...(व्यवधान)

(इस समय प्रो0 छत्तर पाल सिंह तथा ओम प्रकाश बेरी वैल आफ दी हाउस में आ गए)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, चन्द्रमोहन ने जो जमीन खरीदी है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट्स पर चले जाएं, यह तरीका ठीक नहीं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, आप मेरी तो बात सुन लीजिए ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप अपनी सीट पर चले जाइए।

(माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए।)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अगर आप मुझे बोलने का टाईम नहीं देना चाहते तो मैं एज ए प्रोटैस्ट वाकआऊट करता हूं।

(इस समय श्री ओम प्रकाश बेरी सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री अध्यक्ष : छत्तर पाल सिंह जी, आप भी अपनी सीट पर चले जाएं। (व्यवधान)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, आप इसकी * * * *

श्री अध्यक्ष : ये मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं, यह रिकार्ड न किया जाए। आप अपनी सीट पर चले जाइए।

(माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए।)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : मैंने जो कहा है कि चन्द्रमोहन * * * *

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं, आप पहले अपनी सीट पर जाइए और बिना इजाजत से तो आप बोल नहीं सकते । (व्यवधान) जो कुछ मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं, यह रिकार्ड न किया जाए ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : ठीक है जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं सदन से वाक आउट करता हूं । * * * * * * * * * * *

(इस समय प्रो० छत्तर पाल सिंह सदन से वाक आउट कर गए ।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें ।

प्रो सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि पिछले साल में क्या-क्या कुछ सरकार ने किया है, उसके बारे में ट्रिब्यून अखबार में लिखा है :—

"Low achievement year in the Haryana"

दूसरे अखबारों ने टिप्पणी की । वह सुर्खियों में आई । मंत्रियों के काम-काज के बारे में भी अंगुलियां उठाई जाती रही हैं । जो आजकल हालात हैं, वे आपके सामने हैं । आज सारी सरकारी मशीनरी एकदम से बिल्कुल फेल हो चुकी है । ब्रेकडाऊन हो चुकी है । आज के दिन सब कुछ कालैप्स हो चुका है । स्टेट में कोई ला एण्ड आर्डर नहीं है । मंत्री मंडल के सदस्य इस तरह से काम-काज करते हैं जैसे वे लोगों के चुने हुए नुमायंदे नहीं हैं । आज हरियाणा में कोई कानून नहीं है । कत्ल बढ़ रहे हैं और इन कत्लों में पोलीटिकल मर्डर ज्यादा हो रहे हैं । स्पीकर साहब रेप्स की घटनाएं भी बढ़ी हैं और इनमें माइनोरिटी, शिडयूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज से संबंधित ज्यादा घटनाएं हुई हैं । इसी प्रकार से किडनैपिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं । इस घटना में अब एक नई मांग फिरौती की भी जुड़ गई है । चोरी-डकैती की घटनाएं भी दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं । इसी प्रकार से छोटे बच्चों की बलि देना यानी उनकी हत्या की घटनाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं । थानों में हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं । इतना ही नहीं लोगों को मार कर उनको झूठी मुठभेड़ों में मारा गया दिखाया जाता है । स्पीकर सर, थाने जो लोगों की रक्षा के लिये हुआ करते हैं वहां ऐसा कुछ हो रहा है । पोलिटिकल लोगों को मतदाता अपनी प्रोटैक्शन के लिये चुन कर भेजते हैं । थाने और सैक्रेटेरियेट पोलीटिकल लोगों के हाउसिज आज अपराधियों के लिये शरणस्थली बने हुए हैं । उनके लिये सेफ जगह बनी हुई है । ऐसे लोगों के लिये ये सेफ सैंक्चुअरीज बन गए हैं । क्रिमिनलज पर तो लाठियां

*Not recorded as ordered by the Chair.

[प्रो0 सम्पत सिंह]

गोलियां नहीं चलतीं लेकिन अगर कोई प्रजातान्त्रिक ढंग से प्रदर्शन करता है तो उसका लाठियों और गोलियों से जवाब दिया जाता है। अभी हाउस के अन्दर कल भी इस बारे में काफी चर्चा हुई। उस के बारे में मैं और जिक्र नहीं करना चाहूंगा। तकरीबन 7-8 जगहों पर गोलियां चलीं और किसानों को मारा गया। बुरी तरह से लोगों की रीढ़ की हड्डियां तक तोड़ी गईं। उसके बाद मुकद्मे दर्ज हुए। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब कह रहे थे कान्स्टेबल ने किसान से अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज बोल दी थी और उसमें मुकद्मा दर्ज हुआ है और अब उस मामले में कम्प्रोमाईज हो गया है। स्पीकर सर, बड़ी अजीब बात है। एक साधारण आदमी जो किसान होगा और पुलिस का आदमी उसको अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकद्मा दर्ज होगा, यह बात सम्भव नहीं है। इस का मतलब यह है कि उस किसान को बुरी तरह से पीटा गया था और उसको बेहोश किया गया। जींद-रोहतक रोड जाम हुआ, उसके बाद केस दर्ज हुआ। सिम्पली यह कह देना कि अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज के कारण पुलिस वाले के खिलाफ मुकद्मा दर्ज हुआ और आज कम्प्रोमाईज हो गया, यह बात बिल्कुल गलत है। स्पीकर सर, इसी तरह से डाक्टरों और नर्सों तक को भी नहीं बख्शा गया। उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। उन पर भी लाठियां बरसाई गई हैं। स्पीकर सर, आज ऐसा लग लग रहा है कि एक किस्म से सरकारी आतंकवाद है और आज सारे हरियाणा प्रदेश में स्टेट मिलिटैन्सी जोरों पर है। आज पब्लिक में सैंस आफ इन सिक्योरिटी आई हुई है। चाहे कोई लोकल इलैक्शन हो रहा हो या कोई और सारी की सारी सरकारी मशीनरी का मिसयूज करके एकदम डैमोक्रेसी और प्रजातन्त्र का कत्ल किया जा रहा है। इस बारे में मैं आगे पूरी डिटेल्ज दूंगा। स्पीकर सर, एक मिनिस्टर के बारे में तो मुख्य मन्त्री जी और सारे हाऊस को मालूम है कि आज वह अम्बाला जेल के अन्दर अपनी एड़ियां गर्म कर रहा है। इसी तरह से स्पीकर सर, कई और मन्त्री अपराधिक मामलों में वांछनीय हैं या गैर कानूनी कार्यों में शामिल है तथा जेल जाने की इन्तजार में हैं। यही नहीं, स्पीकर सर, आज इन को कोर्टस की तरफ से भी बार-बार रोज प्रताड़ना मिल रही है। कोर्टस से बार-बार हैबियस कोरप्स में इनको प्रताड़ना मिलती जा रही है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार को तो लीगेलाईज ही कर दिया है, इसलिये इस पर क्या जिक्र किया जाए। स्पीकर साहब, इनकी किस-किस बात का जिक्र करूं। एक तरफ यह हाल है तो दूसरी तरफ प्लान कट हो रहा है, एक तरफ फाईनैंशियल क्राईसिज हैं तो दूसरी तरफ टैक्सिज की चोरी हो रही है तथा स्टेट के इन्ट्रैस्ट्स को सैक्रिफाईस किया जा रहा है। एस0वाई0एल0 और जमुना जल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। आज सारे प्रदेश से पानी और बिजली गायब है। सड़कों पर से बसें गायब हैं। लेकिन मुख्य मंत्री में कुर्सी की कमजोरी है। स्पीकर सर, आज प्रदेश में ऐसे हालात हो रहे हैं, जो मैं आपको बतला रहा हूं। एक तरफ तो स्टेट में पैसे की कमी है दूसरी तरफ बाहर विदेशी दौरों पर जाने की होड़ लगी हुई है। मुख्य मन्त्री जी बड़ी टीम के साथ विदेश गए,

कोई बात नहीं। इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर हो आए और दूसरे और मन्त्री भी जा रहे हैं। स्पीकर सर, यह तो हद ही हो गई कि श्री मांगे राम जी इनको कोई चैक नहीं कर रहे हैं। स्पीकर सर, यहां तक कि मछली पालन मंत्री भी अपने मछली मण्डल के साथ बाहर गए। पता नहीं ये कौन सी मछली का पालन करेंगे या कोई मछली पकड़ेंगे या कोई मछली मारेंगे, यह तो मालूम नहीं लेकिन वे भी बाहर हो आए। स्पीकर सर, अगर कन्क्लूड करें तो सारी स्थिति का पता लगेगा कि कहां क्या हो रहा है। यहां तो वही बात हो रही है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये लोग ऐश-ओ-आराम के लिये बाहर के देशों में जा रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन इन लोगों के कतई खिलाफ है। आज इनको कहीं पर भी पब्लिक मीटिंग करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बार-बार घोषणा कर देते हैं कि फलां जगह करेंगे लेकिन ये लोगों से दूर भाग रहे हैं। इनकी इन्हीं बातों को ले कर और स्टेट इन्ट्रैस्ट को ले कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है। चाहे वह नारनौल की रैली हो, चाहे चंडीगढ़ की रैली हो, चाहे वह 2 3 तारीख का बन्द हो, सब ने प्रमाणित कर दिया कि यही पार्टी और यही नेता हैं, जो लोगों के इन्ट्रैस्ट को प्रोटैक्ट कर सकते हैं। इसी लिये वे सारी की सारी चीजें कामयाब हुईं। अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री मण्डल के सदस्य बैठे हुए हैं इनके दिमाग में भी सैंस आफ इन्सक्यारीटि है। अध्यक्ष महोदय, ये भी डरे हुए हैं, जहाज डूब रहा है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि कब इससे छलांग लगा दें ताकि इससे बच पाएं। मांगे राम जी इसमें हंसने की बात नहीं है, अगर जहाज से कूद नहीं लगाओगे तो डूब कर ही मरोगे। आपके पास मौका है कि छलांग लगा दें। अध्यक्ष महोदय, एक बढ़िया काम इनकी सरकार ने किया है, वह यह है कि हमारे बहुत से सीनियर साथी थे और वे बहुत ही बढ़िया थे और आज भी हैं। हमारे सामाजिक तालुकात अलग होते हैं और राजनैतिक अलग होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने डिफैक्शन की है, इनकी तरफ बदले हैं, उनको रिवार्ड दिया गया है और इस चीज के लिये मैं गवर्नमैंट का धन्यवादी हूं कि उन लोगों को कम से कम रिवार्ड तो दिया है। ये और लोगों को तो रिवार्ड देते नहीं है। अगर अलग-अलग मुद्दे का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले मैं बिजली और पानी के बारे में बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आज बिजली और पानी की सबसे बड़ी प्रायर्टी होनी चाहिए। आज पानी की क्या पोजीशन है? हमारे पास नहरों के द्वारा पानी के तीन साधन हैं। उनमें से सबसे पुराना साधन यमुना का था और उसके बाद भाखड़ा का और नया जो साधन है, वह एस0वाई0-एल0 से रावी-व्यास पानी आने का है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। हां, एक और हो सकता है जैसा कि इस बार भगवान ने पानी बरसा दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसे भाखड़ा है, उसकी पोजीशन के बारे में कोई झगड़ा नहीं। उसको बनाने का कोई झगड़ा नहीं था वह बना हुआ है और हम अपना शेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सरकार उसका रख-रखाव भी नहीं कर सकी। यह तो इस सरकार की इनकैपेबिलटी है। भाखड़ा की 12 हजार क्यूसिक की कैपेसिटी थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें रिपेयर की

[श्री० सम्पत सिंह]

जरूरत थी, इसके किनारे कमजोर हो गए थे। आज वह कैपेसिटी घटते-घटते 6 हजार क्यूसिक की रह गई है। अगर उसमें साढ़े 6 हजार क्यूसिक पानी भी डाल दें तो वह नहर खत्म हो जाएगी, उसकी आज यह पोजीशन है। अध्यक्ष महोदय, 1990 में जब हमारी सरकार थी तो हमने एक करोड़ 90 लाख रुपये पंजाब सरकार को दिए थे। ताकि भाखड़ा पंजाब में मुरम्मत की जा सके। मैं भाखड़ा मेन लाईन की बात कर रहा हूं और उसमें से 1 करोड़ 70 लाख तो 1991 में इनकी सरकार के आने के दो-तीन महीने पहले खर्च हो गए थे। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के आने के बाद इन्होंने एक नया पैसा भी पंजाब सरकार को इसकी रिपेयर के लिये नहीं दिया। मांगे राम जी, आठ करोड़ रुपए का उन्होंने नया एस्टीमेट बनाया था। स्पीकर साहब, अब हरियाणा सरकार की यह अयोग्यता ही है कि उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया। उससे हरियाणा का ही पानी आना था। एक तरफ तो हम डिस्प्यूटिड केसिज के लिये लड़ते हैं और दूसरी तरफ जो आलरेडी डिसाईडिड केसिज हैं, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। स्पीकर साहब, इसी तरह से एस०वाई०एल० नहर की बात है। उससे हमें नया पानी मिलता था। कल भी इस बारे में बड़ा शोर-शराबा पड़ा और स्वाभाविक है कि हर आदमी इसमें इन्ट्रैस्टिड है। अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में इनके अपने कांग्रेस के भाई की सरकार है। हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी हो। सैन्टर में भी उनके अपने प्रधान मंत्री हैं और ये उनकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकते हों। लेकिन इसमें हरियाणा प्रदेश का अपना इन्ट्रैस्ट है। आज एस०वाई०एल० नहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चन्द्रशेखर जी की सरकार को इनका समर्थन था और उनकी सरकार ने 20 फरवरी, 1991 को बी०आर०ओ० को यह काम दिया था। हम इनके धन्यवादी हैं। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त तो इनके समर्थन वाली सरकार थी और आज तो इनकी अपनी सरकार है। अपने प्रधानमन्त्री हैं और कई बार तो इन्होंने जो रिकार्ड हरियाणा में स्थापित किए हैं, वही रिकार्ड सैन्टर में भी स्थापित कर दिए हैं। उनकी कुर्सी भी आपने बचाई है। इसलिये वे आपकी पूरी मदद करेंगे। उनको कह कर आप यह आर्डर क्यों नहीं करवा लेते हैं। आपको किस बात की डिफिकल्टी है। स्पीकर साहब, एस०वाई०एल० नहर पंजाब में 119 किलो मीटर लम्बी है और बाढ़ की वजह से 264 उसके अन्दर कट हैं। एक किलोमीटर में दो से फालतू कट हैं। बड़ी नहरों में जो कट होते हैं, वह 100-150 मीटर से कम नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह नहर 1/3 बीच हो चुकी है। अगर हम उस नहर को बनाएंगे तो पांच सौ करोड़ से कम खर्चा नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते रहे हैं कि तीन महीने में नहर बनकर तैयार हो जाएगी। हमने तो महीना 28,29,30 और 31 दिन का सुना था लेकिन इतना लम्बा साल का महीना नहीं सुना था। आज पौने चार साल हो गए हैं लेकिन इनके तीन महीने पूरे नहीं हो रहे हैं। और आज भी बार-बार केन्द्र के मन्त्री आ जाते हैं। प्रधान मंत्री जी ने तो कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। ये कभी तो उनका प्रोग्राम सिरसा में और कभी और

कहीं बनाते हैं लेकिन उन्होंने हरियाणा में आने के लिये मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि वहां के लोग पूछेंगे और कहेंगे कि एस0वाई0एल0 नहर बनाओ। प्रधान मन्त्री तो आते नहीं लेकिन ये मन्त्रियों को ले आते हैं कभी शुक्ला जी आ जाते हैं तो कभी प्रणव मुखर्जी आ जाते हैं। बार-बार अखबार में उनके बयान आ जाते हैं। मैं अखबार वालों से भी निवेदन करता हूं कि जब ये लोग बार-बार एक ही बात करते हैं फिर आप उनकी बात अखबार में क्यों छापते हैं। प्रणव मुखर्जी गुड़गांव में आए और कह गए कि ये नहर तैयार हो जाएगी। स्पीकर सर, महामहिम ने भी इस हाउस को चार बार ऐड्रैस किया और वे भी कह कर चले गए कि यह नहर तैयार हो जाएगी। इस बार भी उन्होंने कहा है कि बस, अब यह नहर जल्दी तैयार हो जाएगी। पता नहीं यह अब कब आएगी और कब यह नहर तैयार होगी। आज तक भी यह पता नहीं लगा है। स्पीकर सर, इसी तरह से इसे जमुना वाटर सबसे पुराना हमारा साधन था। लोग आज भी गंगा और जमुना को मैय्या कहते हैं। इनको मां यूं ही नहीं कहते, बल्कि इसलिये कहते हैं कि इन्होंने लोगों को जीवन दान दिया है। लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करके यमुना की शक्ल ही इन्होंने बिगाड़ दी है। हमने 1993 में भी कई बार इसका जिक्र किया था। मैं आपको 3 मार्च, 1993 के सैशन की प्रोसिडिंग पढ़कर सुनाता हूं। चौधरी भजन लाल जी की जब लास्ट में स्पीच कन्क्लूड हुई थी, तो इन्होंने कहा था :--

> "यह हरियाणा के हित की बात है। इसलिये अगर इस समय हम कोई ऐसी वैसी बात करेंगे तो यू0पी0 वाले झगड़ा करेंगे। इसलिये मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब भी इसका फैसला होने लगेगा तो अपोजीशन के लीडर्ज और सबको बुलाकर बात करेंगे और बातचीत के बाद ही ऐग्रीमैंट पर साईन करेंगे।"

स्पीकर सर, हमने कहा था कि यह बड़ा ही सैंसटेटिव और सीरियस इशू है। यह मेरे और बीरेन्द्र सिंह (डिसीडेन्ट) के सवाल नं0 476 के उत्तर में इन्होंने बताया था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हमसे तो पूछना दूर रहा अपनी कैबिनट और लैजिस लेटिव पार्टी व अन्य किसी से भी नहीं पूछा जबकि इनको हमसे पूछना चाहिये था। स्पीकर सर, यह ब्रीच आफ अथोरैन्स था। आप ही बताइये कि फिर अथोरैन्स की क्या कीमत रह गई जबकि इनको ऐग्रीमैन्ट पर साईन करने से पहले हमसे और कैबिनट से पूछना चाहिये था। शायद आज इसीलिये ही शांगे राम जी सीरियस बैठे हैं। स्पीकर सर, तो यह पोजीशन सरकार की है। इनको इस पर साईन करने से पहले कैबिनेट को और बाद में असैम्बली को कांफीडैन्स में लेना चाहिये था और उसके बाद ही इस अहम ऐग्रीमैंट पर साईन करने चाहिये थे। ऐसा कमिटमैंट उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने किया भी था। स्पीकर सर, यमुना वाटर के शेयर में पहले हरियाणा और यू0पी0 का हिस्सा था। इन दोनों के बीच में इसका ऐग्रीमैंट पहले से ही है इसलिये हमारा तो सबसे पहले यही आब्जैक्शन था कि जब पहले से ही ऐग्रीमैंट साईन

[प्रो० सम्पत सिंह]

हुआ पड़ा है तो फिर आप इसको अब क्यों कर रहे हैं। स्पीकर सर, ऐग्रीमैंट में नं० दो पैरा है, जिसमें लिखा है—

"Whereas the water was being utilised by the westrern States—Ex-Tajewala and Ex-Okhla for meeting the Irrigation and Drinking water needs without any specific allocations."

बड़ी अजीब बात है। आज तक यमुना के पानी का बंटवारा इन दोनों ही स्टेट्स के बीच हो रहा था, क्यों हो रहा था क्योंकि इनके बीच ऐग्रीमैंट था। जब वह ऐग्रीमैंट साईन हुआ था, तो यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर्ज के बीच हुआ था for and on behalf of Governor of Punjab and Governor of Uttar Pradesh. यह कोई चीफ इंजीनियर्ज का ऐग्रीमैंट नहीं था बल्कि यह बाकायदा गवर्नमैंट का ऐग्रीमैंट था। इस ऐग्रीमैंट को नेहरा साहब ने पढ़ा होगा लेकिन अफसोस कि इस ऐग्रीमैंट को नहीं माना गया और आज हमको ये कुछ कहने नहीं दे रहे हैं। रोने नहीं दे रहे हैं। आज यह कह रहे हैं—

"and whereas demand has been made by some western States on this account and the needs for a specific allocation of the utilisable water resources of river Jamuna has been felt for a long time."

स्पीकर सर, यह डिमांड हमने नहीं रखी, हो सकता है किसी दूसरी स्टेट ने रख दी हो। हरियाणा की कभी भी यह डिमांड नहीं रही कि इस ऐग्रीमैंट को रिओपन किया जाए। इस समझौते से यमुना जल में दूसरी स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की भी हिस्सेदारी मान ली गई है। इस बात का विरोध आज चाहे चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी न करें, लेकिन उस वक्त इन्होंने इसका विरोध किया था। इनकी यह बात रिकार्ड में है। इन्होंने कहा था कि यह बात गलत हुई है और उन स्टेट्स का यमुना वाटर में कोई शेयर नहीं है। स्पीकर सर, इसके अलावा इस ऐग्रीमैंट में इन्होंने और अगली क्लाजिज ऐसी डाली हैं जिससे हमारा पानी का हिस्सा और कम हो गया। स्पीकर सर, जहां हरियाणा का 77 परसैंट पानी था, यू०पी० का 23 परसेंट था आज हरियाणा का घटकर 47 परसेंट रह गया है। अब ताजेवाला की जगह हथिनीकुंड बैराज बनेगा। उसका कंट्रोल अपर यमुना रिवर बोर्ड के पास होगा। हरियाणा के पास नहीं होगा जबकि 1954 में जो समझौता हुआ था उसमें साफ लिखा था कि इस पर हरियाणा का कंट्रोल होगा। आप कहते हैं कि पानी बढ़ जाएगा। पानी कैसे बढ़ेगा ? यह डैम नहीं है। यह बैराज है। इससे पानी रैगुलेट होगा। पानी कहां से बढ़ेगा ? इनके पास अब नया पैसा नहीं है। कोई प्रोजैक्ट ऐप्रूवल नहीं है, कोई ऐस्टीमेट एप्रूवड नहीं है, केवल मात्र लोगों में भ्रामक प्रचार किया गया है कि हथिनी कुण्ड बना रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली के, हिमाचल के, यू०पी० के चीफ मिनिस्टर खुश हुए हैं। खुश क्यों न होंगे जब उनको पानी का और बिजली का फायदा होगा तो वे खुश तो होंगे ही। स्पीकर सर, ये अपना दीया बुझाकर दिल्ली का दीया जलाकर आए हैं। अब उनको रोशनी और पानी मिल

रहा है, तो वे खुश क्यों न हों ? पानी तो जितनी बरसात हो जाएगी, उस हिसाब से आएगा । कभी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होती है । जब अप्रैल-मई में पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी नहीं मिल पाएगा । क्योंकि समझौते के अनुसार पहले दिल्ली के पीने के पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद दूसरी स्टेट्स को शेयर दिया जाएगा । एक यमुना एकौर्ड पर अगर स्पैशल डिबेट रख लें तो छह दिन लगातार चर्चा हो सकती है । इस फैसले से हरियाणा की जनता को लूट लिया है । इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है ? हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि हालांकि सरकार ने अपने हाथ काट लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के हितों की बलि चढ़ा दी है लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता इस बात को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे । इस ऐग्रीमैंट को नहीं मानेंगे चाहे जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े । अब तक नोटीफिकेशन नहीं हुई है और उस नोटीफिकेशन को होने भी नहीं देंगे । नोटिफिकेशन हो गई तो इस सरकार को उखाड़कर फैंक देंगे । स्पीकर सर, खर्च के लिये इनके पास एक पैसा नहीं है । वर्ल्ड बैंक के चक्कर काट रहे हैं और वे तरह-तरह की शर्तें लगा रहे हैं । गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हरियाणा वाटर कंसोलिडेशन प्रोजैक्ट पर 1858 करोड़ रुपये खर्च करेंगे । अमाउंट बहुत बड़ी लगती है जैसे बहुत कुछ करने जा रहे हैं । मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं इरीगेशन मिनिस्टर भाषण देते हैं । मैंने पहले भी कहा था कि आधा हमारा पैसा होगा । आधा लोन आएगा । पहले खर्च करेंगे उसके बाद उसकी री-इम्बर्समैंट होगी । आपके पास तो सारा सौदा खतम है, उसके बदले में नया पैसा नहीं मिल रहा है । 1858 करोड़ रुपये के बारे में जवाब देते समय कैटेगोरीकली बता देना । मैंने पहले भी कहा था कि आधा पैसा हमारा होगा, आपने कहा था कि नहीं होगा । मैं फिर कह रहा हूं कि आधा हमारा होगा । न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी । बहुत बुरी हालत है । सारे काम बन्द पड़े हैं । मुख्यमंत्री महोदय, व नेहरा साहब का आना-जाना तो मेरे हल्के में रहता ही है । वहां सभी प्रोजैक्ट्स बन्द पड़े हैं । जैसे पावड़ा लिंक कैनाल प्रोजैक्ट है, जोकि 2 करोड़ की लागत से बनेगा, पिछले चार सालों से काम बिल्कुल बन्द पड़ा है । उस पर कोई काम नहीं हुआ और न ही हो रहा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है । पैसा लगाएं कहां से ? मामला बिल्कुल साफ है । (शोर)

जहां तक पावर की बात है उसकी हालत भी बुरी है । बीरेन्द्र सिंह जी जब आये, तब इनके बाजुओं में बड़ा दम खम था लेकिन काटने लगे तो कुछ नहीं मिला । चौधरी देवी लाल जी की मिनिस्ट्री में ये वजीर थे । उस समय इनको याद होगा कि किसानों को 24 घन्टे बिजली मिला करती थी । अब इस सरकार के वक्त में सारा मामला साफ हो गया । पैसा ही नहीं इनके पास । यह सारा मामला तो सी0एम0 की पालिसी पर ही डिपैन्ड करता है । ये बेचारे अकेले क्या करें ? (शोर) फरीदाबाद में बिजली की चोरी रोकने का, स्पीकर साहब, इन्होंने बड़ा यत्न किया । केस भी रजिस्टर करवाये गये । बड़ी बहादुरी दिखाई लेकिन बाद में कोई कार्यवाही नहीं की

[प्रो० सम्पत सिंह]

केस वापिस ही ले लिये हैं लेकिन सांय सात से 10 बजे तक इस तरह के हालात होते हैं जैसेकि देश में ऐमरजैन्सी लगी हो । अन्धेरा छाया रहता है जैसे ब्लैक आउट हो । यह सब कुछ पावर कट के कारण हो रहा है । करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन व इन-ऐफीशीऐन्सी के कारण ऐसा हो रहा है । आज बिजली बोर्ड का घाटा भी है 1800 करोड़ रुपये का हैं। जबकि हमारी सरकार केवल 200–250 करोड़ रुपये का घाटा ही छोड़कर गई थी HSEB has bottom less spit जितना डालो, अध्यक्ष महोदय, नीचे से उतना निकल जाएगा । अब ये क्या कर रहे हैं। सारा घाटा किसानों पर डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि किसानों की वजह से यह घाटा हो रहा है क्योंकि उनको 50 पैसे प्रति यूनिट के रेट पर बिजली दे रहे हैं । बिना मीटर के फलैट रेट पर किसानों को बिजली दे रहे हैं, जिसकी वजह से घाटा हो रहा है । असल बात यह है कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रीलिस्टों को बिना मीटर के बिजली दे रहे हैं और उसकी बिलिंग कर रहे हैं किसानों के नामों पर ये सब कुछ किसानों के सिर मढ़ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, कोई नया काम जनरेशन का नहीं हो रहा है । मुख्यमन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि फलां-फलां सरकार के वक्त में यह काम नहीं हो सका जोकि हम कर रहे हैं । हिसार में पलवल में, फरीदाबाद में थर्मल लगा रहे हैं और यमुनानगर के बारे में तो यह कह दिया कि बस अभी लगा कि लगा । पौने चार साल का समय बीत गया, इन कामों पर एक पैसा भी सरकार ने खर्च नहीं किया । छटा यूनिट पानीपत में अप्रैल 90 में शुरू हुआ था । उसका भी कुछ पता नहीं । उसके लिये जो मशीनरी आई, आज तक उसकी यह हालत है कि वह मशीनरी 70–80 करोड़ की होगी , पानीपत रेलवे स्टेशन पर सड़ रही है । उसे छुड़ाने के लिये इन के पास पैसे नहीं हैं और फिर ये कहते हैं कि हम पावर जनरेशन करेंगे । और इसके लिये नई नई विदेशी कम्पनियों को ठेके दे रहे हैं । एक मैगावाट पर लगभग 4 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा । टोटल लगभग ये 4 हजार करोड़ का ठेका देने जा रहे हैं और उधर दूसरी Bhel वगैरह कम्पनियां थीं, जोकि 3 या 3 से कम करोड़ पर करने के लिये तैयार थीं लेकिन उन को यह काम नहीं सौंपा गया । कोई टेन्डर नहीं, कुछ नहीं । जब कोई भी टेण्डर होते हैं, चाहे पी डब्ल्यू डी का हो, चाहे इरीगेशन का हो, तो टेन्डर देने वाला आदमी आफिस में आता है ।लोऐस्ट टैण्डर को स्वीकार कर लिया जाता है लेकिन यहां क्या हुआ कि जिस ठेकेदार ने टैण्डर दिया, उसके घर में जाकर ये उससे सौदा करते हैं । अगर विदेशी हैं तो अपने घर में होंगे , हरियाणा के मुख्य मन्त्री को उसके घर में नहीं जाना चाहिये था । ये उसके घर में जा कर समझौता करके आए हैं, जबकि उसको खुद इनके पास आना चाहिए था । इन्होंने आइजनबर्ग से समझौता किया और वह विदेशी कम्पनी है । कल को पी० डब्ल्यू० डी० का कोई ठेका होगा तो क्या मन्त्री ठेकेदार के घर जाएगा । तो स्पीकर साहब, इन-एफिशिएंसी और करप्शन की वजह से यह घाटा हो रहा है । आज मैं आपको बताना चाहता

है कि इन्होंने डोमैस्टिक कंज्यूमर पर कितना बोझ डाला है ? ये कहते हैं जो लोग ए0सी0 यूज करते हैं, उन पर खर्चा बढ़ाया है। आप हमें यह बताएं कि एक महीने में 41 यूनिट बिजली कंज्यूम करने वाला कौन ए0सी0 लगाता है । एक महीने में 41 यूनिट तो छोटा कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है । अगर इसमें से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी निकाल दें तो पहले इसका रेट 90 पैसे यूनिट था लेकिन आज इन्होंने दो रुपए कर दिया है । इसका मतलब यह है कि एक यूनिट का 110 पैसे बढ़ा दिया जिसकी परसैन्टेज 122 या 123 बनती है । इन्होंने रातों-रात डोमैस्टिक कंज्यूमर को मार कर रख दिया । आप यह बात बताएं कि आज कल महीने में 40 यूनिट से कम बिजली खपत किस की है । आज हर आदमी बिजली का इस्तेमाल करता है । फिर दूसरी बात यह है कि इनके मीटर भी बहुत तेज चलते हैं । स्पीकर साहब, प्रदेश में 90 परसैंट कंज्यूमर 40 यूनिट्स से ज्यादा के हैं और उन पर इतना बोझ डाला है । फिर कहते हैं यह तो मामूली सा बोझ है । आपकी सरकार आने से पहले कोई फयूल सरचार्ज नहीं हुआ करता था, आपने 11-11-93 से डोमैस्टिक कंज्यूमर पर यह सरचार्ज लगा दिया । चौधरी बीरेन्द्र सिंह का ब्यान आया कि चूंकि कोयले के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं और गैस के रेट बढ़ गए हैं इसलिये बिजली के दाम बढ़ाये हैं । फयूल चार्ज के बाद तो नियम बन गया है कि अगर फयूल चार्जिज बढ़ेंगे तो आटोमैटिकली बिजली के चार्जिज भी बढ़ जाएंगे । यह तो आपका रूल है कि अगर तेल का रेट पांच पैसे बढ़ेगा तो बिजली का रेट भी पांच पैसे बढ़ जाएगा । यह तो आपका शायद 24 दिसम्बर, 1994 का नोटिफिकेशन है उसकी क्या जरूरत थी क्यों रेट बढ़ाए । वर्तमान मुख्यमन्त्री जी के समय में एक किलोवाट का मिनिमम रेट दस रुपए की बजाए बीस रुपए हो गया । इसी तरह से एग्रीकल्चर का मामला है । एक तरफ तो मीटर्ड सप्लाई है और दूसरी तरफ फलैट रेट है । हमारी सरकार में चौधरी बीरेन्द्र सिंह शामिल थे और उस समय 25 रुपए एक हॉर्स पावर का रेट था अब 65 रुपये है इसमें 160 परसैंट इन्क्रीज कर दी गई है । यानि साढ़े तीन साल में यह इतनी इन्क्रीज हुई है । फिर ये मीटर्ड सप्लाई की बात करते हैं । कल जो एक सवाल का जवाब आया था, उसमें लिखा है कि मिनिमम रेट नहीं बढ़ाए हैं । अगर आपने वे रेट्स विदड्रा कर लिए हैं, तब बताएं वरना आपने नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि 45 रुपए की बजाए 60 रुपए पर वैसे पावर रेट्स किए हैं । ट्यूबवैल्ज पर भी मिनिमम चार्जिज का सिस्टम वर्तमान मुख्य मन्त्री के वक्त में हुआ है, और पहले नहीं था । पहले मीटर पर जितनी कंजम्पशन आती थी, उतना ही चार्ज लगता था । फिर ये बार-बार कहते हैं कि हम किसानों को बिजली 50 पैसे यूनिट के हिसाब से देते हैं । जब आप हॉर्स पावर के हिसाब से लेते हैं, तो 50 पैसे कहां रह गए ? इसी तरह से इन्होंने कहा कि कमर्शियल वालों का भी रैशनेलाइजेशन हो रहा है । रैशनेलाइजेशन तो आपने बसों का किया था । पचास पैसे की टिकट एक रुपए की कर दी । तो इसी तरह से कमर्शियल सैक्टर में तीन सलैब थे उनको एक कर दिया । जो रेट हाइऐस्ट लैवल के थे, जैसे

[प्रो0 सम्पत सिंह]

डोमैस्टिक के चार से दो कर दिए । क्या यह रैशनेलाइजेशन है ? Rationalisation and simplification should be in the interest of the public, not in the interest of your Exchequer. इन्होंने इस तरह की पोजिशन बना कर रख दी है । इस तरह से कौमर्शियल मीटर की सिक्योरिटी 165 रुपए से बढ़ा कर 505 रुपए कर दी और डोमैस्टिक मीटर की सिक्योरिटी 85 रुपए से बढ़ा कर 335 रुपए कर दी । इस तरह से इस सरकार ने बिजली बोर्ड का सत्यानाश कर दिया । स्पीकर साहब, जब मैंने बोलना शुरू किया था उस समय मैंने थोड़ी सी कानून व्यवस्था की बात कही थी । हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोजीशन ऐसी है कि कई केसिज राजनैतिक कत्ल के हो गए । वे हरियाणा प्रदेश के माथे पर एक बदनुमा धब्बा है । सेखों मर्डर काण्ड हुआ । इस बारे में हमने पिछली बार भी जिकर किया था उस समय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे थे । उस समय इनके उस मंत्री ने मेरी तरफ इशारा करके यह कहा था कि मैं आपको भी देख लूंगा । मुझे तो कई लोगों ने देखने की कोशिश की है । आप क्या देख लेंगे ? उस केस के बारे में सी0 बी0 आई 0 ने जो कुछ इन्क्वायरी की है, उसके कारण आज वह मंत्री जेल में हैं । उस केस के जो विटनैसिज हैं, उनको थरैट किया जा रहा है । उन विटनैसिज को पीटने तक की बात हुई है । मैं कहूंगा कि ऐसी हरकतों को रोका जाए । इसी तरह से स्पीकर साहब, सुशीला कांड हुआ । उसका मर्डर हुआ । यह बड़े शर्म की बात है । सुशीला का 1 मई 1993 को मर्डर हुआ । लोगों ने इस बारे में एजीटेशन किया । पंचायतें हुई । खापें हुई । हमारी पार्टी ने और सोशल आर्गेनाइजेशंज ने, सभी ने इस बारे में कहा । मुख्य मन्त्री से मिलने आए । जब मुख्य मन्त्री से मिले तो मुख्य मन्त्री जी झुंझला कर प्रवोक हो गए और उन्होंने कह दिया कि वह किसी के साथ भाग जाए तो मुख्य मंत्री क्या करे ? मुख्य मन्त्री जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी । एक तरफ तो जो मुख्य मंत्री जी से मिलने आए थे, उनको घाव था और ऊपर से इन्होंने उस पर नमक छिड़क दिया । मुख्य मन्त्री जी को उनको सहलाना चाहिये था । मुख्य मंत्री का काम लोगों को प्रोटैक्शन देना है । लोगों की सुरक्षा करना है । स्पीकर साहब, इस बारे में सी0 बी0 आई0 ने जो इन्क्वायरी की, अब तक उनके सामने जो फैक्टस आए हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा । जहां तक सकल मारने का सवाल था, वह जिसकी बच्ची थी वह मुख्य मन्त्री जी आपके साथ एज ए डिप्टी सुप्रिन्टैन्डैंट डियूटी पर था ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुशीला कांड का जिक्र कर रहे हैं जिसकी इन्कवायरी सी0 बी0 आई0 कर रही है । जिस केस की जांच हो रही हो, उसका इनको जिक्र नहीं करना चाहिए ।

प्रो0 सम्पत सिंह : वह कोई कोर्ट नहीं है, वह तो केवल इन्वैस्टीगेशन अथोरिटी

है । उस कांड के बारे में हमारे सामने जो फैक्ट्स आए हैं, उससे ज्यादा इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा । आपने वह इन्कवायरी भी दो महीने से क्लोज करवा रखी है । इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा । स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जिसको नकल करवाई जा रही थी, वह उनकी बेटी थी । बेटी तो किसी की भी हो सकती है । स्पीकर साहब, सी0 बी0 आई0 ने उस कांड से संलिप्त दो आदमी मुकेश और बीरेन्द्र पकड़े । मुकेश तो मुख्य मन्त्री जी के भाई मनफूल का गनमैन था । मनफूल की आढ़त की दुकान है । क्या वे बहुत अच्छे आदमी हैं ? जो दूसरा बीरेन्द्र है, उसका दादा आपके अपने मांस का है जिसका नाम कांशीराम है । वह बहुत भला आदमी है । उसके भोलेपन की वजह से उसका आपके भाई के साथ आढ़त का काम रहा है । उसका पोता इस कांड में शामिल है । एक जोगिन्द्र नाम का लड़का सुसाईड कर गया । लेकिन लोग यह कहते हैं कि उसने सुसाइड नहीं की, उसका कत्ल किया गया है । मुख्य मन्त्री जी इस बात की इन्कवायरी कराएं । उसको कत्ल इसलिये करवाया गया है ताकि इस कांड के फैक्ट्स सामने न आएं । एक कुलदीप नाम का लड़का है, उसका आज पता नहीं है कि वह कहां पर है । उसको भी कत्ल करने की कोशिश की जा रही है । इस बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । सरकार का काम लोगों को प्रोटैक्शन देने का है । यदि इस तरह की बात हो तो यह शोभा नहीं देती । आज तीन महीने हो गए, इस कांड के बारे में फैक्ट्स सामने आने के बाद भी इन्कवायरी ठप्प पड़ी है । इसी तरह से रणबीर सिंह सुहाग का मर्डर किया गया । उसने आलरैडी रिप्रैजैंटेशन दी हुई थी कि उसे जान का खतरा है; बाकायदा आई नेम एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । वह सैर करने गया । गायब हो गया और गायब होने के बाद यानि 7 दिन के बाद उसकी लाश मिली । इसकी लाश उसी प्रकार से नहर में मिली जिस प्रकार से सुशीला की बड़ोपल नहर में मिली थी । उसके बाद इस पर आज तक कोई आगे कार्यवाही नहीं हुई । उसकी 4 बहनें और 3 बेटियां हैं । उसके परिवार पर क्या बीती, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं । आज के दिन गवर्नमैंट का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेल हो चुका है । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जसबीर सिंह, जो जिला परिषद का पलवल का मैम्बर था, उसको भी समाप्त कर दिया गया वह हमारी पार्टी का था । लोगों ने उसे चुना था लेकिन उसको मार देने के बाद भी उस केस के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही । उसी प्रकार से करनाल में अंकुश और रिंकू नाम के दो भाइयों को गायब किया गया । लोग नए साल के लिए खुशियां मना रहे थे और एक दूसरे को नए साल की बधाई के लिए चिट्ठियां लिख रहे थे, लेकिन इनके परिवार को क्या चिट्ठी मिली की आपके दोनों लड़कों को गायब कर दिया गया है । उनसे भी पैसे मांगे गए । एक दिन एक की लाश मिली और दूसरे दिन दूसरे बच्चे की लाश मिली । इनकी भी लाशें नहर में ही मिली । अपराधी न पकड़े पर वहां के लोग व परिवार वाले प्रौटैस्ट कर रहे थे लेकिन

[प्रो0 सम्पत सिंह]

उनको सरकार की तरफ से कोई सहानुभूति प्रकट करने की बजाये उनको परेशान किया गया और उनको लाठियों से पीटा गया । उसके बाप ने तंग आकर सोचा कि मुझे यहां तो न्याय मिलेगा नहीं इसलिए उसके बाप ने आत्महत्या कर ली । ये किस तरह से कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वह इन बातों से पता चलता है । इसी प्रकार से जमालपुर टोहाना में डा0 स्वर्ण सिंह व उसके रिश्तेदार जो वहां आये हुये थे दोनों को मार दिया गया । इस पर भी कोई आगे कार्यवाही नहीं की गई । इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भाई अजमत खां जी शायद हाउस में नहीं बैठे खिलुका गांव हथीन में है का लड़का उठाया गया । उसकी मां विधवा है और उसके नाम 70-80 एकड़ जमीन है, उसको लौटाने के लिए 15 लाख रुपये फिरौती के मांगे गए । उसकी बूढ़ी मां ने 7 लाख रुपये उठाने वालों को एक लाख रुपये किसी एम0 एल0 ए0 को यानि आठ लाख रुपये दिए तब जाकर वह लड़का वापस आया । इसी प्रकार से जीन्द के राम बिलास का भी तीन बार अपहरण हुआ । जब लोग रोष प्रकट करने के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां चलाई जाती है । फायरिंग की जाती है । फिर कहते हैं कि पुलिस को कन्ट्रोल करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं । इनका नारा जो वन फैमिली वन जोब का है, उसे एक को मारो, एक को नौकरी देकर पूरा कर रहे हैं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि गवर्नर एड्रैस पर जितना समय आप एलोकेट करें उसी हिसाब से हमारे सदस्यों की तादाद को ध्यान में रखते हुए हमें भी दें । ये काफी देर से बोल रहे हैं और इररेलेवैंट बोल रहे हैं । इनको बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं । आप इनको कहें कि ये इररेलेवेन्ट न बोलें और हमें भी समय दिया जाये । (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष : सभी को परपोर्शनेटली टू दी एकोर्डिंग न्यूमेरिकल स्ट्रैंथ टाईम मिलना चाहिए लेकिन अपोजीशिन को थोड़ा ज्यादा । सम्पत सिंह जी, आप जल्दी खत्म करिए ।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हाउस के अन्दर आप हमारे कस्टोडियन हैं, उसी प्रकार से देश के लोगों की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है । सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इनके बारे में एक ओब्जर्वेशन दी है। हमने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा है । स्पीकर साहब, पिछले दिनों जनवरी के महीने में स्पीकर सर, जो व्यक्ति व्यापार करेगा कारखाना लगाएगा उसके साथ किसी का डिस्प्यूट हो सकता है । मुख्य मन्त्री जी के रिलेटिव का भी डिस्प्यूट था । डिस्प्यूट किसी का भी हो सकता है । इस मामले में क्या हुआ कि कोर्ट के अन्दर जो डिस्प्यूटिड पार्टी थी, उसका कोई एम्प्लाई आया पुलिस ने उसको उठा लिया और ड्राईवर को भी

उठा लिया और उन्होंने हैबियस कोरमस रिट कोर्ट में डाल दी । उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आब्जर्वेशन की थी, वह अखबार में भी आई थी । 21 फरवरी की बात है । "हर पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी यह समझता है कि वही कानून है और अपने को कानून से ऊपर समझता है । यहां तक कि इस देश की सर्वोच्च अदालत के सामने झूठ बोलने से भी बाज नहीं आते हैं । समय आ गया है कि पुलिस को यह अहसास करवा दिया जाए कि वे अब नागरिक अधिकारों का और हनन नहीं कर सकते"। स्पीकर सर, इस तरह की बातें आज हरियाणा में घट रही हैं । यह भी हमारे लिए कोई सुखदाई चीज नहीं है । पुलिस कस्टडी में हर रोज डैथ्स हो रही हैं । ये आन्दोलन में मरने वाले न्यारे हैं और थाने में बुला कर जिनको मारा जाता है, वे न्यारे हैं । यमुना नगर में एक बाप और दो बेटों यानि तीन लोगों को मार दिया गया । उस विधवा ने कोर्ट में पैटीशन डाली है । ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं । मारने के बाद लाशों को भी थाने में खत्म कर रहे थे । लेकिन 10 हजार लोगों ने डिमांस्ट्रेशन करके पुलिस को रोक दिया और वे लाशें विधवा औरत को, उस विधवा मां को पुलिस ने सौंप दी । उसके बाद उस विधवा ने हाई कोर्ट के अन्दर अपील की है कि गवर्नमैंट उसमें कुछ नहीं करेगी क्योंकि उस वक्त भी पुलिस ने 2 लाख रुपये मांगे थे और एक परिवार के लोगों को दो लाख रुपये न दे सकने के कारण मार दिया गया । स्पीकर सर, इस तरह का सिस्टम बन गया है कि 2 लाख रुपये के बदले में आदमियों को गाड़ी चढ़ा दो । दो लाख रुपये पुलिस ने मांगे थे । 2 लाख दो, न हों तो उसको मार दो । अध्यक्ष महोदय, पुलिस फिरौती मांगती है । इससे बुरी और क्या बात होगी ? अध्यक्ष महोदय, नगीना का किस्सा हमने पिछले सैशन में भी उठाया था और अभी तक उस बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । पिछले सैशन में लास्ट दिन हमने कहा था । मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि हमने डी० एस० पी० को सस्पैंड कर दिया है अध्यक्ष महोदय, सस्पैंशन इज़ नोट ए पुनिशमैंट । नगीना के अन्दर डी० एस० पी० ने कमाल नाम के मुस्लिम लड़के को मारा था । वह किस्सा ऐसे है कि वह लड़का भेड़ चरा रहा था और उधर से डी० एस० पी० साहब की गाड़ी आ रही थी । सड़क पर कोई भेड़ आ गई । गाड़ी ने सायरन बजाया परन्तु वह सायरन भेड़ ने नहीं सुना । भेड़ जिप्सी के आगे आ गई और जिप्सी रुक गई । डी० एस० पी० ने आव देखा न ताव उस कमाल नाम के लड़के को पटक पटक कर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई । केस तो 302 का दर्ज होना चाहिये था लेकिन ये कहते हैं कि उसको सस्पैंड कर दिया है । इसी तरह से अम्बाला पड़ाव चौकी के अन्दर नरम सिंह नाम का इलैक्ट्रीशियन था, उसको भी मार दिया गया । उसके मां-बाप ने भी कोर्ट में अपील कर रखी है । स्पीकर सर, पानीपत, मेहम और जगह जगह पर लोगों को इस तरह से जान से मारा जा रहा है । लेखू काण्ड की भी काफी चर्चा रही । श्री मांगे राम जी को उस वक्त खूब पसीने आए और लछमन दास अरोड़ा जी को भी बहुत ही पसीने आए । लछमन दास अरोड़ा जी को वही तकलीफ थी जिसकी वजह से आज वे उपचार के लिए अस्पताल में

[प्रो0 सम्पत सिंह]

दाखिल हैं । जीन्द में जो मारा-मारी हुई थी, उसमें भी इन्होंने माना है कि ट्रेजडी हुई । वे लोग मिलिटैन्ट टाईप के और डकैत टाईप के लोग थे । स्पीकर सर, किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए । उन लोगों का पुलिस कस्टडी में जिस दिन लास्ट डे था उनको ऐलिमिनेट कर दिया गया । एक इन्स्पैक्टर और एक और कर्मचारी था, केवल दो आदमियों ने मुकाबला किया जिन्हें पर कोई निशान नहीं कोई चोट नहीं । इतने डरैडिड टाईप के वे टैरोरिस्ट्स थे उनको यूं कोई बिना सामने से विरोध हुए मार दें, यह कोई साधारण बात नहीं है । इसमें भी जरूर कोई कान्सपिरेसी की गई है ताकि किसी मामले की मिट्टी न उखड़ जाए इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया है । जीन्द में खुर्दपुरा का 45 साल का आदमी था, वह थाने में आया उसका कोई डिस्प्यूट था उसको अपने भतीजे के सामने नंगा कर दिया । बाद में शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली । नन्दकरण मोजरा गांव का कैथल में पृथ्वी सिंह नाम का क्लर्क था जोकि किसी केस में हिरासत में था । पुलिस ने उसको हथकड़ी लगा रखी थी । स्पीकर सर, न जाने क्यों हथकड़ी खोली और उसको बस के नीचे दे मारा । खोल थाने में भी एक आदमी को मार दिया । स्पीकर सर, बख्शते तो ये किसी बच्चे को भी नहीं । यूनिवर्सिटी में, कालेज में, डाक्टर और नर्सें सभी का काम तमाम करने में ये लग रहे हैं । स्पीकर सर, ये क्रिमैन ऐट्रोसिटीज की बात करते हैं । धारूहेड़ा का किस्सा भी अभी भूला नहीं था । स्पीकर सर, विशम्बर दयाल नाम का आदमी था; स्पीकर सर, उस बेचारे के साथ क्या बीती ? उसको पुलिस ने आदमी से नपुसंक बना दिया । उसी थाने में राजस्थान की 2 मजदूर औरतों के साथ रेप किया गया है । मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि आज का दिन महिला दिवस है । स्पीकर सर, महिला दिवस मनाने से महिलाओं की बात नहीं बनेगी । महिलाओं का भला चाहते हैं तो महिलाओं को प्रोटैक्शन दें । अगर थाने में रेप होंगे तो इससे घटिया और कोई बात नहीं हो सकती है । उसी धारूहेड़ा के अन्दर मजदूर औरतें आई तो थीं रोटी कमाने के लिए, लेकिन बेचारी अपनी इज्जत लुटवा कर चली गई । स्पीकर सर, इससे अधिक बुरी बात और कोई नहीं हो सकती । उन औरतों पर केस बनाया जा रहा है कि वे चोर थीं या फलां गलत काम उन्होंने किया । स्पीकर सर, अगर वे चोर थीं, तो अरैस्ट करके उनको कोर्ट में पेश कर देते लेकिन इस प्रकार से किसी की इज्जत लूटना ठीक बात नहीं है । इसी तरह से गाजियाबाद में भी पता नहीं कैसे-कैसे लोग लगा रखे हैं । वहां पर एक झुग्गी में एक इंसपैक्टर घुस गया । यह कितनी गलत बात है कि एक इंसपैक्टर रैंक का आदमी ऐसा काम करे । अध्यक्ष महोदय, नरवाना में नारनौद चौक के आगे पुलिस के लोगों ने शराब पी कर तमाशा किया और उस बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । अभी यहां पर कर्ण सिंह दलाल एम0एल0ए0 बैठे हुए नहीं हैं । आज किसी एम0एल0ए0 पर भी हमला किया गया । इससे बुरी बात और क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, यहां पर मक्कड़ साहब बैठे हुए हैं । उनके आदमी चुनाव जीत गए और

वे जश्न मना रहे थे । ठीक है, जीते हैं और जश्न मनाएं लेकिन यह नहीं कि वे गोलियां चलाएं । वहां पर गोली चली और आदमी घायल हो गए, उसमें भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है । दीगांवा में भी तीन आदमियों को पकड़ कर ले गए, उसमें भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है । भूत माजरा में भी यही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी अपने लड़के के सेंट कालका को पैरिस बनाने जा रहे थे लेकिन आज वह क्राईम का क्वैल बन गया है ।

श्रीमती सन्नावती : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी मेरे हल्के की जो बात कर रहे थे, वह बात बिल्कुल सच्चा है । वहां पर नकली खाद बनती थी । वे कौन आदमी थे और कौन उसे बनाता था । पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं है और न ही उस पर कोई कार्यवाही हुई है ।

प्रो० सम्पत सिंह : इसी तरह से फरीदाबाद में तेगांव गांव में किया हुआ है । पुलिस को पूरी तरह से छूट है, वह जो चाहे करे । अध्यक्ष महोदय, किसी मन्त्री के भाई का चुनाव था और उन्होंने गांव वालों को कहा कि वोट देना । लेकिन उन्होंने नहीं दिए और वह हार गया । वे उस गांव के आठ लाख के पत्थर उठाकर ले आए । स्पीकर साहब, हमने पंचकुला में एक पुलिस हैड-क्वार्टर का पत्थर रखा था और सोचा था कि वहां पर एक अच्छा सा पुलिस हैड-क्वार्टर बनाएंगे लेकिन आज वहां से भी फाईल चोरी हो गई है । अगर पुलिस हैड-क्वार्टर में भी चोरी हो जाएगी तो इससे बुरी बात क्या होगी ?

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एक-दो और महकमों का जिक्र करना चाहता हूं । अब मैं एग्रीकल्चर पर आता हूं । फर्टिलाईजर के बारे में इंक्वायरी करवाएं तो पता चलेगा कि करोड़ों रुपए का स्कैन्डल हुआ है । हमारे टाईम में खाद खुली मिलती थी लेकिन आज नहीं मिल रही है और जो मिलती है वह ब्लैक में मिलती है । जुलाना में भी खाद लेने वाले किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है । वह इनको भी पता है । अध्यक्ष महोदय, गन्ने की जो जे–74 क्वालिटी है, उसका रेट 64 रुपए है और साधारण गन्ने का रेट 56 रुपए है । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी नारायणगढ़ सढौरा गए थे। वहां से किसान अपना गन्ना पंजाब के धूरी गांव में बेचते थे । उन किसानों को कैरेज काट कर भी फायदा होता था । लेकिन एक दिन मुख्य मन्त्री का दौरा उस इलाके का था । मुख्य मन्त्री ने किसानों को गन्ना पंजाब ले जाते हुए देख लिया तो हुक्म दिया कि किसानों को हरियाणा से बाहर गन्ना ले जाते हुए तुरन्त रोको । अध्यक्ष महोदय, इसके बाद पुलिस वालों ने किसानों को पीटा और हुक्म दिया कि यहां से बाहर ट्राली नहीं जाएगी । उनको मारकर छोड़ दिया ।

स्पीकर सर, शुगर मिलों में शीरे का करोड़ों रुपये का मुनाफा हुआ । आज

[प्रो० सम्पत सिंह]

13.00 बजे | ये चाहें वह मुनाफा न दिखाएं । शीरा आधा तो कंट्रोल्ड है और आधा डि-कंट्रोल्ड । जो ओपन मार्किट में डी-कंट्रोल्ड है, उसमें शुगर मिलों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं । इसलिए उनका बैनीफिट किसानों को देना चाहिए था । सर, इस मामले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अखबार में कल भी यह खबर आयी थी और कल ही जो सी०ए०जी० की रिपोर्ट इस बारे में आयी है, उसमें भी शीरे का मापदंड दिया हुआ था कि शीरे से कितनी अल्कोहल बनेगी ? उसके मुताबिक 1990-91 का हमारे समय का हिसार डिस्टीलरी का जिक्र है । कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो बाद में आई है में बताया है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की कम एक्साईज डियूटी दी गयी है । सर, या तो एक्साईज डियूटी कम है और या फिर शीरा ओपन मार्किट में बेचा गया है । मुख्य मन्त्री जी चाहें तो इसकी इंक्वायरी करवा लें । लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि शीरे को बिल्कुल ही डी-कंट्रोल करवा दो । गवर्नमैंट आफ इंडिया की भी पालिसी है और मुख्य मन्त्री जी मिनिस्टर्ज की मीटिंग में सैंटर में जाते रहते हैं । उनको पता है कि उनकी डी-कंट्रोल की पौलिसी है । इसलिए इस शीरे को डी-कंट्रोल करें ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे । अगर कंट्रोल रखना है तो दवाईयों के लिए ही रखो लेकिन डिस्टिलरी, चाहे वह पब्लिक सैक्टर की हो या प्राईवेट सैक्टर की हो, उस के लिए कन्ट्रोल रेट पर शीरा नहीं होना चाहिए । दारू पीने वालों के लिए कंट्रोल रेट किस बात का ? जिस भाव में भी शीरा खरीदकर वे दारू बनाते हैं, उनको बनाने दो । वे दारू को महंगी बेच लेंगे । लेकिन स्पीकर सर, एक तरफ तो दारू लोगों को मार रही है और दूसरी तरफ उसी दारू को बनाने के लिए कंट्रोल रेट का शीरा दिया जा रहा है । तो यह बिल्कुल गल्त बात है । टोटल डी-कंट्रोल का शीरा होना चाहिए । धन्यवाद !

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात हिसार डिस्टिलरी जो कि मेरे दामाद की है, के बारे में कही । ये एक पेपर भी हिला रहे थे । इसके अलावा इन्होंने हथीन का भी जिक्र किया है । मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हाउस को भी और प्रैस को भी पता लगे कि असलियत क्या है । अध्यक्ष महोदय, शीरे में चीनी की जितनी मिकदार कम है उसके मुताबिक उसमें कम स्प्रिट बनता है । पहले शीरे में 55 परसैंट की मिकदार होती थी, लेकिन अब शुगर मिलें मोडेनाईज हो गयीं और अब 40 से 42 परसैंट चीनी के कंटैन्ट होते हैं । इसके बहुत पुराने नार्म्ज तय किए हुए हैं । उसके बाद दूसरी चीज है कि जितने भी डिस्टिलरी वाले हैं, इन्होंने 1989-90 में इनके वक्त में एप्लाई किया था । अध्यक्ष महोदय, अगर भजन लाल का दामाद गलत ढंग से काम करता तो इन्होंने उसको उल्टा लटका दिया होता लेकिन गलत काम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । डिस्टिलरी वालों ने कहा है कि इनके नार्म्ज ठीक होने चाहिएं क्योंकि इसमें चीनी कम होती है

इसलिए स्प्रिट कम बनती है और जब कम स्प्रिट बनती है तो उसके मुताबिक नार्म्ज होनी चाहिए । आडिटर जनरल ने भी लिखा कि नार्म्ज पुराने बने हुए है कि एक क्विंटल शीरे में 36.4 प्रूफ लीटर शराब बननी चाहिए । उन्होंने उसके हिसाब से हिसाब लगाया और लिखा कि इसमें कितनी शराब और बन सकती थी । जैसे मिसाल के तौर पर जिस क्वालिटी का कोयला झरिया और धनबाद से पहले आता था, उस क्वालिटी का वह आज नहीं आता है । भट्ठे वालों के लिए जो कोयला पहले आता था, वैसा आज नहीं आता । पहले अच्छा कोयला होता था और बीस टन कोयले में एक लाख ईंट पक जाती थी । इसी तरह से पहले थर्मल प्लांट में दस मैगावाट बिजली बनाने के लिए दस टन कोयले की जरुरत पड़ती थी, लेकिन आज उतनी मैगावाट बिजली बनाने के लिए 15 टन कोयले की जरुरत पड़ती है क्योंकि कोयले की क्वालिटी हल्की हो गयी है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उसके मुताबिक यू0पी0, पंजाब और हमारे यहां भी एक ज्वायंट कमेटी बनी । इस कमेटी में ज्वाइंट सैक्रेटरी, ई0टी0सी0 और डी0टी0सी0 थे । इसने अपनी रिपोर्ट दी कि इसके रूल्ज को रिव्यू किया जाए और इसमें अमैंडमैंट किया जाए क्योंकि यह 36.4 का नार्म ठीक नहीं है । कमेटी ने अपने सामने टैस्ट किया कि क्या होना चाहिए और उसने तीन जगहों पर सैम्पल टैस्ट करके यह बताया कि इसमें चीनी की कितनी मिकदार है और कितने परसैन्ट प्रूफ लीटर शराब बननी चाहिए । उन्होंने यह भी बताया कि एक जगह 29.5, दूसरी जगह 28.7 और तीसरी जगह 28.8 परसैंट अल्कोहल होना चाहिए जबकि हिसार की इस फैक्ट्री ने 30 परसैंट अल्कोहल दी है । मेरे पास आफिशियल रिकार्ड है । पंजाब ने बहुत पहले से 30.56 और 30.69 का नार्म तय कर दिया हुआ है कि इसमें इतनी शराब बन सकती है । कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी चीनी होगी, उसके मुताबिक उसमें प्रूफ लीटर स्प्रिट बनेगी । उसके हिसाब से 30 और 30.2 दिया हुआ है । यह कहा गया कि इसको रिव्यू करें । उसके लिए कमेटी बनी । कमेटी ने रिव्यू किया और एक-एक चीज को बाकायदा दोबारा से देखा। जो मैंने हिसाब बताया है, यह उसके मुताबिक है इसलिए ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है । मैंने अपनी पोजीशन आपके सामने साफ कर दी है ।

श्री शीश पाल सिंह : शीरा पिछले एक साल से केन्द्र सरकार में डी-कंट्रोल किया हुआ है, जबकि प्रदेश में आधा शीरा कंट्रोल में आता है और आधा डी-कंट्रोल से । आप कृपया यह बताएं कि हरियाणा प्रदेश में किस-किस डिस्टीलरी को कितना-कितना शीरा विसरित किया है ?

चौधरी भजन लाल : यह कागजात अभी मेरे पास नहीं हैं । जवाब देते समय मैं आपको इस बारे में बता दूंगा । वैसे कैपेसिटी के मुताबिक जिसका जितना हक बनता है, उसके मुताबिक देते हैं । डी-कंट्रोल हो सकता है । कोई दिक्कत

[चौधरी भजन लाल]

नहीं है । हमने ठेका नीलाम कर दिया । ठेका जब नीलाम करते हैं, तो उसी के हिसाब से डिस्टिलरी की कीमत तय करते हैं । (विघ्न)

श्री वीर पाल सिंह : यह स्टेट का अलग-अलग मामला है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्टेट का छोड़ दिया, यू0पी0 ने 75 परसेंट अपने पास रखा ।

श्री सम्मत सिंह : आपकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सम्मत सिंह जी, आप काफी देर तक बोल चुके हैं । अब आप बैठिए ।

प्रो0 सम्मत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बजट अभिभाषण का तीसरा दिन है, मैं पहले दिन बोल रहा हूं । लीडर आफ दि अपोजीशन हूं । सभी कांफ्रेंस में आप देखते हैं । आप चाहे यू0पी0 का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, रिकार्ड मंगाकर देख लें । वहां लीडर आफ दि अपोजीशन को 3-4 घंटे का समय बोलने के लिए दिया जाता है । हमें तो आप एक घंटे भी नहीं बोलने देते हैं ।

स्पीकर सर, इन्होंने सफाई में एक बात कही । हम तो कहते हैं कि जो कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट का पैरा है, उसको आप खत्म करवाएं । अब तो चार साल हो गये हैं । उसमें पैरा है । जिस बारे में आब्जेक्शन लगाया गया है, उस आडिट पैरा को आप वहां से निकलवा लें । हमें कोई एतराज नहीं है । आप की सरकार की किताब में यह छपा है ।

दूसरी बात, मैं एक और कहना चाहता हूं । जैसे सुबह मुख्य मन्त्री महोदय ने पशु-धन फार्म की बात कही । इन्होंने पशु-धन फार्म को ओबलाईज किया । बड़ी अच्छी बात है । खराब जमीन थी । बीच की जमीन थी और अच्छे पैसे देकर आपने जमीन ले ली । इसके लिये हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं । लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी मुख्य मन्त्री या मन्त्री महोदय के परिवार के किसी भी आदमी को सरकारी जमीन नहीं खरीदनी चाहिये थी । यह प्रोपरायटी है । मैं यह नहीं कहता कि कम दाम पे । मुख्य मन्त्री महोदय ने इस बात की सफाई दे दी है । हम उसका डिस्प्यूट नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : सम्मत सिंह जी, आप जल्दी समाप्त करें । दूसरी पार्टी के मैम्बर्ज ने भी बोलना है । आप पांच मिनट और बोलेंगे ।

प्रो0 सम्पत सिंह : इस से आगे मैं कोआपरेटिव की बात पर आता हूं। को-आपरेटिव की क्या हालत है। गांव में तो कोआपरेटिव सोसायटी को सौ-ग्राठी कहते हैं। जब लोन देने की बात आती है तो मांगे राम जी 100 में से 60 देते हैं। इतनी बुरी तरह से इस में करप्शन है। इसके सबूत हमारे पास हैं। पिछली बार बहिन चन्द्रावती जी ने भी इस बारे में कहा था। शायद आप वे सन्तुष्ट हो गई होंगी। इस को-आपरेटिव बैंक ने किसी बाहर के हाउसिंग बैंक को शायद 2 करोड़ का डिपोजिट दिया था और उसमें से चार लाख रुपया कमीशन का खा गये। इसके बाद उन आफिसर्ज को सस्पैन्ड किया गया था। इसकी जांच के आर्डर किये गये थे लेकिन बाद में पता नहीं क्यों, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वहां के एम0डी0 विद्यालंकार कहें या महालंकार कहें उन्होंने उन लोगों के नाम इनाम देने के लिये रिकमैन्ड किये। कितने गजब की बात है। अगर इसी तरह से काम चला तो फिर हरेक भ्रष्ट आदमी का हौंसला बुलन्द हो जाएगा।

स्पीकर साहब, अब मैं भूना मिल के बारे में कहना चाहूंगा। यह मिल कोआपरेटिव सैक्टर में लगाई थी, चौधरी देवी लाल जी ने और उस की सब से बैस्ट मशीनरी थी, जोकि उस समय लगभग 30–40 करोड़ की होगी और आज उसकी कीमत लगभग 60 करोड़ के आस-पास होगी। इन्होंने किसानों को मारने के लिए वह मशीनरी बेचने की योजना बनाई है ताकि किसान आगे से गन्ना न लगाएं। कहते हैं कल को कंकास्ट की तरह या ब्रिवरी की तरह इस मिल को बेचने की स्कीम सरकार बना रही है। जहां तक किसानों की पेमैंट का सवाल है, वह उनको नहीं हो रही है। मुख्य मन्त्री महोदय, लगभग तीन करोड़ से ऊपर किसानों की पेमैंट अभी तक रुकी पड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार यह नहीं चाहती कि वह भूना की मिल चले। हो सकता है कि उस मिल को भी बेच खाएं।

इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का भी बुरा हाल है। इसकी यह हालत है कि सरकार ने एक भी नई बस नहीं खरीदी है। एक सिंगल बस भी पिछले दो सालों में नहीं खरीदी गई। केवल मात्र एक्सप्रैस बसों के जोकि हाई वेज पर चलती हैं, उनको छोड़कर एक बस भी आर्डिनरी नहीं खरीदी गई है। अगर खरीदी हैं, तो वे रिकार्ड बता दें। इस ओर सरकार ध्यान दे।

इसके साथ-साथ मैं प्राईवेट बसों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि प्राईवेट आदमियों को परमिट दे दिये गये हैं लेकिन वे वायेबल नहीं हैं। उन पर लोन भी चढ़ रहा है और इसी वजह से वे लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। सड़कों पर बसें नहीं हैं और लोग परेशान हैं।

इसी तरह से स्पीकर सर, सेल्ज टैक्स की बात है। जय प्रकाश जी कल बता रहे थे कि 17 परसैन्ट टैक्स रिसीट में इक्रीज है। स्पीकर सर, 1992–93 में

[प्रो0 सम्पत सिंह]

यह 14 परसैन्ट थी । पिछले साल 10 परसैन्ट थी और आज भी 17 प्रतिशत नहीं है । जब कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट आएगी, उसमें वह भी इन्क्रीज 10 परसैन्ट निकल जाएगी । स्पीकर सर, 10 परसैन्ट इन्फलेशन है और 10 परसैन्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है । आलरेडी जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनकी जो इंक्रीमैंट होती है, वह अलग है । अगर सेल्ज टैक्स के अन्दर पिछले साल से 20-22 परसैन्ट से बढ़ौतरी कम है, तो इस का मतलब यह है कि टैक्स की चोरी है । यह आप भली भांति जानते हैं कि अगर आप कुछ भी न करो 20 परसैन्ट वृद्धि इसमें फिर भी आ जाती है ।

इसी तरह से इनकी फाइनैंशियल पोजीशन है । कई बार कोर्ट की डिग्रीज आती हैं । कोर्ट आर्डर करती है कि फलाने की कोठी, फलाने की जायदाद या फलाने की कार जब्त कर लो । लेकिन जब्त नहीं होती । सरकार पहले ही पैसा भर देती है । लेकिन यहां पर जब्त हो गई, स्पीकर सर, गुड़गांव के अन्दर । गुड़गांव के अन्दर इसलामपुर और नागपुर के किसानों को डेढ़ करोड़ रुपया मुआवजा नहीं दिया गया । वे लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने आर्डर कर दिये कि एस0डी0एम0 की कोठी को नीलाम कर दिया जाए और वह नीलाम हुई साढ़े पांच लाख में । यह बड़ी ही शर्म की बात है और खरीदने वाले से 25 परसैन्ट नकद भी भरवा लिया । वह शायद एक वकील था ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, मैं गुड़गांव का एम0एल0ए0 हूं और मुझे पता है कि वहां पर किसी ने भी कोठी नहीं खरीदी ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, वहां पर अजय गुप्ता नाम का एक एडवोकेट है, उसने वह कोठी खरीदी है । मौके पर 25 परसैंट रकम भी जमा करवाई गई थी ।

इसी तरह से एलोकेशंज पर कट हो रही है । आप देखिए कि प्लान तो इतने बड़े-बड़े बना दिए हैं, फिर बाद में कट करते हैं । इरीगेशन पर इन्होंने 16 परसैंट कट की, मैडिकल एण्ड एजुकेशन पर 12 परसैंट, टैक्नीकल एजुकेशन पर 31 परसैंट और इंडस्ट्री पर 20 परसैंट कट की है । यह कट करने के बाद भी इनकी यह हालत है । स्पीकर साहब, ये लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं । एच0एस0आई0डी0सी0 की ए0एम0 आयल्ज एण्ड फैट्स लि0 की कालका एरिया में एक यूनिट लगी थी । उस इंडस्ट्री को डेढ़ करोड़ रुपया लोन दिया गया था । आज उस आदमी के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि वह कहां चला गया । अगर इस तरह से लोग डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए खा जाएंगे तो प्रदेश का क्या होगा ? फिर दूसरी तरफ ये आंकड़े देंगे कि हमने इतना लोन दे दिया । (विघ्न)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जब से ये बोल रहे हैं हमने बीच में कोई दखल अन्दाजी नहीं की। इनको बोलते हुए सवा घंटा हो गया है। ठीक है, अपोजीशन के लीडर को बोलना चाहिए और इसीलिए हमने बीच में नहीं टोका। ये इर-रैलेवेंट भी बोलते रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप टाईम को हिसाब से बांटें और इनको बैठने के लिए कहें। मैंने भी एक रैजोल्यूशन लाना है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप 1.25 पर अपनी स्पीच खत्म कर देना। नेहरा साहब उसके बाद आप बोल लेना।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। तो स्पीकर साहब, इन्होंने लोकल बाडीज के इलैक्शन करवाए और महामहिम महोदय ने कह दिया कि गवर्नमैंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। जिला परिषद के चुनाव में, पंचायत समितियों के चुनाव में और सरपंचों के चुनाव में दो लोग तो भिवानी में मारे गए। इसी तरह से दो लोग सुंडावास में मारे गए। नारी गांव में नंगा नाच किया गया। वहां पर इलैक्शन डेढ़ घंटे में खत्म कर दिया गया। लोगों को राई रैस्ट हाउस में बुला कर मारा गया। इसी तरह से सम्भालखा म्यूनिसिपल कमेटी के कांउसलर के स्पोर्टर एजेंट की हत्या कर दी। लालवास में जो मुख्य मन्त्री जी की ससुराल है, वहां पर पीर चन्द जी को भागना पड़ा।

चौधरी भजन लाल : मारने वाले किस पार्टी के थे?

श्री पीर चन्द : स्पीकर साहब, इन्होंने जो बात कही है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पहले इनके लोक दल के आदमी गरीब लोगों को पकड़-पकड़ कर ले जाते थे और उनको जबरदस्ती वोट डालने के लिए कहते थे। वहां के लोगों ने इनके आदमियों का मुकाबला किया और गरीब आदमियों ने अपना सही वोट डाल कर इनके आदमी को हराया। मैं वहां गया था और मैंने उनको कहा था कि आप किसी भले आदमी को बनाएं।

प्रो० सम्पत सिंह : यह पहले जाखल में भी भागे थे और फिर चौधरी बंसी लाल को भी छोड़ कर भागे थे। (व्यवधान व शोर) आप जाखल में भागे और चौधरी बंसी लाल जी को छोड़ कर भागे। भागने वाली आदत तो आपकी है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वे कौन लोग हैं। वे लोग आपकी ससुराल के होंगे। कोई साला लगता होगा कोई साले का छोरा होगा। वे आपको जुहारी देने वाले लोग हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह के हालात हुए हैं। हमें चौधरी पीर चन्द जी के साथ बहुत ही हमदर्दी है। क्योंकि मैं जिला परिषद के चुनाव हुए। वहां पर बहुत विशीयस एटमोसफियर बना हुआ था। वहां पर हमारी पार्टी का चन्द्रभान नाम का आदमी जिला परिषद का मैम्बर जीत गया और इनके राज का

[प्रो0 सम्पत सिंह]

समर्थक चुनाव हार गया। आज हरिजनों के लिए मैं महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे। महात्मा गांधी का नाम लेने वाले लोगों ने वहां के हरिजनों को गांव से निकाल दिया और वे हरिजन दो महीने तक ठिठुरती सर्दी में खुले आसमान के नीचे कैथल में पड़े रहे। उनका केवल एक ही कसूर था कि उन्होंने चुनाव में इन सरकारी आदमियों के समर्थक को वोट नहीं दिए। जहां तक कर्मचारियों की बात है, आज उनकी बहुत बुरी हालत है। कर्मचारी बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं। कर्मचारियों के राजनीतिक तौर पर तबादले किए जाते हैं।

जन सम्पर्क राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र कुमार मदान) : स्पीकर साहब, मैं बात को थोड़ा क्लीयर करना चाहूंगा। चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि इनके राज का समर्थक वहां से चुनाव हार गया। पहली बात तो यह है कि वह असत्य कह रहे हैं। वहां पर जो चुनाव जीता है, वह इनकी पार्टी का है और जो चुनाव हारा है वह हरियाणा विकास पार्टी का है। उनके साथ हमारी पार्टी का कोई लिंक नहीं था। वहां पर जो डैथ हुई, वह आपस के लड़ाई झगड़े में हुई। इस बारे में रोहतक के तीन डाक्टरों की टीम ने रिपोर्ट दी है। स्पीकर साहब, उस गांव के हरिजनों का आपस में कोई झगड़ा था, उसकी वजह से कुछ लोग अपने गांव के ही साथियों से नाराज हो कर कैथल में आ गए थे। इस बारे में ज्यों ही मुख्य मन्त्री जी को पता लगा। मुख्य मन्त्री जी ने उसी वक्त अम्बाला के कमिश्नर और डी0आई0जी0 को कैथल भेजा। मैं भी उनसे मिला। मैंने भी उनसे बातचीत की। अधिकारियों ने भी उनसे बातचीत की लेकिन उससे पहले हरिजनों की अपनी पंचायत बीच में पड़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि यह हमारा आपस का मसला है। इसको हम आपस में ही निपटा रहे हैं। इतवार को उनकी पंचायत ने फैसला कर दिया और वे अपने गांव में वापिस आ गए। (शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : वे गांव में कितने दिन के बाद वापस आए।

श्री सुरेन्द्र सिंह मदान : वह कैथल में दो दिन धरने पर रहे थे। दो दिन के बाद गांव में आ गए।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, हम यह बात आप पर छोड़ते हैं आप ही बता दें कि क्या वे कैथल में केवल दो ही दिन रहे थे?

श्री अध्यक्ष : दो दिन नहीं, ज्यादा दिन तक कैथल में रहे थे।

प्रो0 सम्पत सिंह : ठीक है जी। इसी तरह से, स्पीकर साहब, श्री हरपाल सिंह जी के असावनी गांव में चुनाव हुए तो वहां पर वोटर बाहर से लाए गए। स्पीकर साहब, मैंने कर्मचारियों की बात शुरू की थी। आजकल कर्मचारियों के

तबादले राजनीति के आधार पर हो रहे हैं । मेरे पास पहले जो हरियाणा एग्री-कल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और आज राज्य मन्त्री हैं, उनका एक नोट है । उस नोट में ये क्या कहते हैं ? मैं आपको उसका सैम्पल देना चाहूंगा कि ये किस तरह से कर्मचारियों के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव करते हैं । इन्होंने जो नोट लिखा, वह इस तरह से है :—

"श्री अमर नाथ शर्मा, स्टोर-कीपर नगर पालिका करनाल, श्री ब्रज शर्मा चौटाला समर्थक, जिसने लोकदल से मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा था, को साथ ले कर घर-घर जा कर मेरे विरुद्ध प्रचार एवं प्रसार करता है तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि श्री अमर नाथ शर्मा, स्टोर कीपर नगर पालिका करनाल का करनाल जिले से बाहर किसी दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया जाए ।"

नीचे हस्ताक्षर हैं : जय प्रकाश, विधायक एवं अध्यक्ष, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला । तारीख है : 26-4-94 ।

स्पीकर साहब इस तरह के नोट लिखे जाते हैं । राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को पीड़ित किया जाता है । स्पीकर साहब, वोट डालने का अधिकार सब को बराबर का मिला हुआ है । अगर कोई कर्मचारी किसी तरह का करप्शन करता है, उसको सजा दो, हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन राजनीतिक आधार पर आप चौटाला समर्थकों को कितने दिनों तक फांसी दोगे । थोड़े दिनों बाद चौटाला समर्थक तो उधर होंगे और आप इधर आने के योग्य भी नहीं रहेंगे । स्पीकर साहब, हमारे यहां पर एक हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड बना हुआ है जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है । महिला मण्डल गांव-गांव में बने हुए हैं । इस महिला मण्डल में क्या हो रहा है, वह मैं बताना चाहूंगा । मेरे हल्के के अन्दर भी यह महिला मण्डल बना हुआ है । यहां से पैसा सैंक्शन होकर जाता है । हिसार जिले में वहां पर एक लेडी, जिले के इस महिला मण्डल की चेयरमैन है । अब वह लेडी क्या करती है ? वह जिले की महिला मण्डल की प्रधान होने के कारण गांव-गांव में जो महिला मण्डल बने हुए हैं, उनके पास जाती है और जो पैसा 94-95 हजार रुपये के करीब एक महिला मण्डल को जाता है, उस पैसे को वह अपने लिए इस्तेमाल करती है । पैसा वह लेडी खुद खाती है और नोटिस गांव की महिला मण्डल को जाता है । यह पैसा बगैर ब्याज के होता है और इसमें कुछ सबसिडी भी होती है । यह लेडी करोड़ों रुपया खा रही है । यह पैसा 42 महीनों में बिना ब्याज के वापस करना होता है । जिन लेडीज के नाम से यह पैसा लेकर यह लेडी खुद रखती है, नोटिस उनके पास जाने पर उनसे मिलती है तो वह लेडी कहने लगी कि नोटिस मेरे को दे दिया करो लेकिन दफ्तर में बैठा बाबू तो जिनके नाम लोन है, उस को नोटिस भेज देता है । स्पीकर साहब मेरे कहने का मतलब यह है कि वह लेडी का की पैसा खा

[प्रो0 सम्पत सिंह]

रही है । इस संबंध में मेरे पास शिकायत भी आई है लेकिन उस पर कोई रोक नहीं ।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से बुढ़ापा पैंशन का जिक्र करना चाहूंगा । यह स्कीम चौधरी देवी लाल जी ने बहुत अच्छी चलाई थी । बूढ़े आदमी चौधरी देवी लाल का गीत गा रहे थे । हमारे समय में 8 लाख लोगों को पैंशन दी जाती थी और 65 साल की उम्र निर्धारित की हुई थी । इनके समय में वह संख्या 6 लाख रह गई है । और उम्र 60 साल कर दी गई । मैं पूछना चाहता हूं कि 65 साल से घटाकर 60 साल की उम्र करने पर जहां संख्या बढ़नी चाहिए थी वहां यह बढ़ने की बजाय घट कैसे गई ?

अब मैं टूरिज्म के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । इस बारे में मैं तो ज्यादा क्या कहूंगा ? इस बारे में तो पहले चीफ सैक्रेटरी साहब और वर्तमान चीफ सैक्रेटरी साहब जानते हैं कि इनके साथ क्या-क्या हुआ था । बड़खल और मैगपाई में कमरे इनके नाम बुक थे लेकिन वहां पर कोई और कुछ और ही कर रहा है । यह हालत आज टूरिज्म की है ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभिभाषण में जिकर आया कि 450 करोड़ रुपया स्टेट प्रोजैक्ट के नाम से विश्व बैंक से पैसा आ रहा है । यानि ये वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर हरियाणा को गिरवी रख रहे हैं ।

पर्यटन राज्य मन्त्री (चौधरी लीला कृष्ण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट बोलने का समय देना ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि ये वर्ल्ड बैंक से स्टेट रोड प्रोजैक्ट के नाम से 450 करोड़ रुपया ला रहे हैं । इस काम के लिए ये 50 करोड़ रुपया तो कन्सलटंसी के लिए ही देंगे और जो दूसरे प्राईवेट या विदेशी इंजीनियर होंगे । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे यहां पर काबिल इंजीनियर बैठे हैं तो फिर ये बाहर क्यों कन्सलटंसी के पैसे दें । यदि इनसे ही यह काम करवाना है, तो यहां के इंजीनियर क्या करेंगे ? स्पीकर सर, जो इनके अपने इंजीनियरज हैं और इनकी इंटैलिजैंस है, वह क्या करेगी ? (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सैंस हो तो हाउस का समय आधा घण्टा बढ़ा लिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का टाईम आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, रोड्ज की वाईडनिंग का मामला है । वाईडनिंग के काम भी ऐसे हैं, कहीं 8 फुट से बढ़ा कर 10 फुट रोड करनी है या कहीं 10 फुट रोड है, तो उसको बढ़ा कर 12 फुट करना है तो इसके लिए प्राईवेट कन्सलटैंसियों से क्यों कन्सलटेशन ली जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, अपने महकमे के इंजीनियर्ज सरप्लस पड़े हैं और प्राईवेट कन्सलटैंसियों को सरकारी पैसा लुटाया जा रहा है । मांगे राम जी आप इसके लिए क्यों इजाजत देते हैं ? प्राईवेट लोगों के हाथों में सरकारी पैसा क्यों जा रहा है ? सरकार इस बारे में भी जरूर रोशनी डालें । अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन की हालत भी खस्ता है । लोकल बाडीज के चुनावों में डैमोक्रेसी का गला घोंटा गया । कहीं पर तो सिक्रेट बैलट से और कहीं पर हाथ खड़े करके फैसला करवा दिया और कहीं पर अगर किसी ने वोट डालने की कोशिश की तो उसकी बात नहीं सुनी गई । स्पीकर सर, मैं तो कहता हूं कि माननीय गवर्नर महोदय को इतना लम्बा-चौड़ा भाषण पढ़ने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी । होना यह चाहिए था कि उन्हें सिर्फ एक ही लाईन पढ़नी चाहिए थी कि इस प्रकार की कारगुजारी पर मैं अपनी सरकार को डिसमिस करता हूं । (विघ्न)

श्री अमर सिंह ढांडे : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । (विघ्न व शोर)

श्री अध्यक्ष : ढांडे साहब, बैठिए । अभी कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मैम्बर प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता है, तो उसको बोलने देना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, इन्होंने अपने प्वायंट आफ आर्डर से पहले ही यह बात बता दी । अब इन्होंने किस प्वायंट पर बोलना है ? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : सर, आप इनको बोलने तो दें ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ढांडे साहब, आप बोलें कि आप का क्या प्वायंट आफ आर्डर है ?

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जिला कैथल के क्योडक गांव में जिला परिषद के चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हार गया था। वहां पर एक आदमी मरा था। इस कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने वहां पर हरिजनों पर मर्डर का केस बनवा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिये। अध्यक्ष महोदय, 4 हरिजनों को जूतों का हार डाल कर, उनका मुंह काला करके सारे गांव में जलूस निकाला गया और 100 हरिजन परिवारों को उस गांव को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक महीने तक वे कैथल में बैठे रहे। रोहतक से मैडीकल की रिपोर्ट आई कि उसकी मौत चोट लगने से नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, यह घटना हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुई थी कि निर्दोष हरिजनों का जलूस इस तरह से निकाला गया। अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री जी ने भी माना था कि उसकी मौत झगड़े से नहीं हुई थी बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। वह अपने आप मरा था। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट को अगर कोई मोशन लाना है, तो वह बाद में लाए। लेकिन पहले मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं इरीगेशन डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज नहरों में पानी नहीं आता है। इनकी डि-सिल्टिंग नहीं होती है, जिससे किसानों को दिक्कत होती है। उनसे आबियाना तो पूरा लिया जाता है। पिछले दिनों आबियाना बढ़ा भी दिया था। सरकार ने यह कहा है कि हमने 18 सौ 58 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से सरकार से कहूंगा कि वह प्रोजैक्ट क्या है? इस बारे में डिटेल सदन के सामने रखें ताकि हम समझ सकें कि यह पैसा कहां-कहां पर खर्च होगा और यह क्या है। ऐसा करने से यहां सभी मैम्बर्ज को भी पता चलेगा और हरियाणा की जनता को भी पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, जो पानी पंजाब से भाखड़ा में आता है, उसका कंट्रोल बी०बी०एम०बी० के पास एकोरडिंग टू दी री-आरगेनाईजेशन आफ पंजाब स्टेट एक्ट होना चाहिए। मगर अभी तक उसका कंट्रोल पंजाब सरकार के पास है। क्या इस सरकार को इस बात का इलम है कि पंजाब वाले हमारा पूरा पानी देते हैं या अपनी तरफ डाईवर्ट कर लेते हैं? हमारे हिस्से का पानी भाखड़ा में पूरा आता ही नहीं है। आज केन्द्र में, हरियाणा में और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और इन्हें चाहिए कि ये पानी के फैसले को इम्पलीमैंट करवाएं। पंजाब वाले जब भी पानी की कमी होती है हमेशा पानी का ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ ले जाते हैं

और हरियाणा को उसका पूरा पानी का हिस्सा नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात भी कही गयी है कि एस0वाई0एल0 नहर को पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आज से साढ़े तीन या चार साल पहले जब यह सरकार बनी थी तब उस दिन मुख्य मन्त्री जी यह कहते लगे कि एक साल के अन्दर अन्दर एस0वाई0एल0 बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्य मन्त्री जी बार-बार यह भी कहते रहे हैं कि अगर अपोजीशन के मैम्बर्ज इस बात को न छेड़ें तो शायद हमें फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं ये इस बात को क्यों सीक्रेट रखना चाहते हैं। यह हम इनसे जानना चाहते हैं कि एस0 वाई0एल0 कब तक बनेगी। अगर एस0वाई0एल0 नहर तीनों जगहों पर यानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस की सरकारें होने के बावजूद भी नहीं बन सकती तो फिर कब बनेगी ? मुख्य मन्त्री जी ने तो हिसार में एक बार यह भी कहा था कि प्रधान मन्त्री की कुर्सी के बाद नम्बर दो की कुर्सी मेरी ही है। अगर नम्बर दो की कुर्सी मुख्य मन्त्री जी की है, तो अच्छी बात है और हमको इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप यह नहर तो बनवा लो और इसको पूरा करवा-कर पानी ले आओ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नहरों की डिसिल्टिंग के बारे में पिछले साल सिंचाई मन्त्री ने कहा था कि मानसून के या बारिश के खत्म होते ही डिसिल्टिंग करायी जाएगी परन्तु आज तक भी डिसिल्टिंग नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आज क्या हो रहा है ? कई जिलों में जैसे रोहतक, सोनीपत और अन्य दूसरी जिलों में नहरों में इतनी-इतनी लम्बी घास और इतने ऊंचे-ऊंचे पेड़ और पौधे खड़े हैं कि अगर उनमें छोटा हाथी चला जाए तो वह भी नजर नहीं आएगा। तो यह हालत आज नहरों की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार नहरों की यह डिसिल्टिंग कब तक करवा देगी क्योंकि डिसिल्टिंग के बगैर तो किसानों का गुजारा ही नहीं हो सकता ? अध्यक्ष महोदय, यह नहरों की डिसिल्टिंग की तारीख मुकर्रर कर दें।

इसके अलावा जब यमुना जल समझौता हुआ तो मुख्य मन्त्री जी ने बहुत बड़ा क्लेम किया कि यह समझौता हरियाणा के लिए ऐतिहासिक समझौता है। अध्यक्ष महोदय, पहले इस समझौते में रबी की फसल के वक्त यमुना नदी में हरियाणा के पानी का शेयर 77 प्रतिशत था और यू0पी0 का 23 प्रतिशत था और खरीफ की फसल में हरियाणा का इसके पानी में शेयर 73 प्रतिशत तथा यू0पी0 का 27 प्रतिशत था तथा जब 10900 क्यूसिक से ज्यादा पानी यमुना नदी में हो जाता था तो दो तिहाई पानी का शेयर हरियाणा का और एक तिहाई यू0पी0 का हिस्सा था। लेकिन जब मुख्य मन्त्री जी ने यह ऐग्रीमैंट किया जिसको यह ऐतिहासिक समझौता बताते हैं, उसके बाद और उसके अनुसार हरियाणा के पानी का हिस्सा 47.8 परसैंट हो गया यानी हमारा पानी पूरा ही घट गया। अध्यक्ष महोदय, यमुना के पानी में से दिल्ली को पानी देने का मैं विरोध नहीं करता हूं। क्योंकि दिल्ली तो हिन्दुस्तान की

[चौधरी बंसी लाल]

राजधानी है, इसलिए दिल्ली को तो राजस्थान और पंजाब के हिस्से का पानी भाखड़ा से भी दिया जा सकता है तथा यू0पी0 का पानी दिल्ली को यमुना एवं गंगा नदी से भी दिया जा सकता है। केवल हरियाणा ही अकेला क्यों मारा जाए ? हरियाणा को तो पूरा पानी मिलना चाहिए और दिल्ली को राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जिनके पास पूरा पानी है, दिया जाना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह का यमुना जल समझौता मुख्य मन्त्री जी ने किया। पिछले सैशन में भी यह बात आयी थी कि राजस्थान का यमुना नदी के पानी में कोई हिस्सा नहीं है लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने उनको भी पानी देने की बात मान ली। जब मुख्य मन्त्री जी ने उनकी यह बात मानी थी, तो उस वक्त इनको एक यह बात भी कहनी चाहिए थी कि राजस्थान से जो हरियाणा में तीन-चार नदियां यानी कृष्णावती, दोहन, साहबी एवं लडोहा नाला आता है, उन पर राजस्थान सरकार ने 30 या 35 बांध बना दिए हैं और उनका एक घूंट पानी भी हरियाणा में नहीं आता है। पिछले सैशन में मुख्य मन्त्री जी ने यह बात कही थी कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री से उन्होंने यह बात उठायी थी और उन्होंने कहा था कि हमने कोई भी बांध नहीं बनाए हैं। आप चाहें तो इनको देख लें। मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इंस्पैक्शन कर लेंगे। तो मुख्य मन्त्री जी यह भी बता दें कि इन्होंने वह इंस्पैक्शन किया या नहीं किया और किया तो कब किया और कहां किया और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

वह पानी हमारा कहां चला गया क्योंकि उसके ऊपर हमारा राईपेरियन राइट भी बनता है। सदियों से पानी हमारे यहां आ रहा था और एक जो हथिनीकुण्ड बैराज है, यह सैन्ट-परसैंट सैन्ट्रल गवर्नमैंट प्रोजैक्ट होना चाहिए क्योंकि यह सैन्ट्रल गवर्नमैंट की वजह से डिले हुआ है, वरना बहुत कम कीमत में बनता। जब भारत सरकार ने डिले किया है तो भारत सरकार ही इसका खर्च भी बर्दाश्त करे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी जगह बाढ़ आई। सोनीपत जिले में राठधना, गोहाना तहसील में धनाणा वगैरह गांव हैं वहां भी बड़ी बाढ़ आई। राठधना गांव में तो आज तक पानी खड़ा है, उसका प्रबन्ध भी कुछ करना चाहिए। इसी तरह झज्जर तहसील में कलोई हसनगढ़ के इलाके में बहुत सी जगह जे0एल0एन0 का सीपेज का पानी खड़ा है। खास तौर से पहाड़ीपुर और अलेजा गांव में है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में तो गांव की दहलीज तक पानी खड़ा है। लोगों ने बीच में ईंट-पत्थर रखकर निकलने का रास्ता बनाया है। यह पानी जिन इलाकों में खड़ा है, उसे निकालने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा-7 में स्प्रिंकलर्ज का जिक्र किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किस जिले को कितने स्प्रिंकलर दिए गए कितने टोटल दिए और उनकी टोटल कीमत क्या आई। जहां-कहीं ओलावृष्टि हुई है, बहुत सी जगह यह हुई है लेकिन मैं खास तौर से तोशाम, लोहारू और दादरी सब-डिवीजन की चर्चा करना चाहूंगा। इनमें

लेवा, जीतवान, बास, सिमली, कैरू, ओबरा, चैहरकलां, चैहरखुर्द, सिरसी, मिट्ठी, बढ़ेढ़ा, बड़धू मुगल, बड़धू खूजा, लाढावास, रावलधी, खातीवास, समसपुर, कमोद, सिक्कर, बास, चीड़ां, भागेश्वरी वगैरह में किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई । उसके लिए किसानों को अभी तक राहत नहीं मिली । उसका भी सरकार को फौरी तौर से प्रबन्ध करना चाहिए क्योंकि ऐसी विपदा से किसान तो मर जाता है । किसानों को करनाल में जो नकली बीज दिया गया, उस नकली बीज का पिछली बार भी बताया था सरकार ने कि केस रजिस्टर हुआ, सारी बात हुई लेकिन न तो किसान को मुआवजा मिला न उस केस में कोई गिरफ्तारी हुई। जरा मुख्यमंत्री जी इस बारे में भी बताएं कि जो यह नकली बीज सप्लाई किया गया, जिस किसी आदमी ने बेचा, उस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ? अध्यक्ष महोदय, किसान को न डी0ए0पी0 खाद मिलती है, न यूरिया मिलती है । किसान को वक्त पर खाद न मिले, तो आप भी किसान हैं, आप जानते हैं कि उस पर क्या बीतती होगी ?

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार फैसला कर रही है या कर चुकी है कि पानीपत की शूगर मिल किसी दूसरी जगह पानीपत और गोहाना के बीच में ले जाई जाए । अध्यक्ष महोदय, पानीपत का शूगर मिल पानीपत में रहना चाहिए और गोहाना में शगर मिल अलग से लगनी चाहिए क्योंकि दोनों ही जगह मिलें होनी जरूरी हैं । पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पानीपत का शूगर मिल हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि यह शहर के बीच में आ गया है । शहर के बीच में यमुना नगर शूगर मिल है । यमुनानगर के रैस्ट हाउस में आप रात को ठहर जाएं तो सुबह जब बाहर निकलेंगे तो सब कुछ सफेद हुआ मिलेगा । रैस्ट हाउस के बाहर की घास भी सफेद दिखेगी । यह जो बातें हैं इनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । मोलैसिज की बात कही गयी है । (व्यवधान व शोर)

अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ अपोजीशन ने मोलैसिज की बात कही कि इस पर पूरी तरह से डि-कंट्रोल होना चाहिये । मुख्यमन्त्री महोदय ने कहा कि पिछली बार ठेके नीलाम कर दिये थे, जिसकी वजह से डि-कंट्रोल नहीं किया गया । इस बार अभी ठेके नीलाम नहीं हुए हैं । इस बार कंपलीटली डि-कंट्रोल कर दो । जो 50 परसैन्ट डि-कंट्रोल किया हुआ है, और जो 50 परसैन्ट खुला रखा जाता है उसमें से भी हरियाणा सरकार ने शूगर मिलों को मजबूर किया हुआ है कि 75 परसैन्ट 180 रुपये क्विंटल के हिसाब से डिसटिलरीज को देना पड़ेगा जबकि उसका मार्किट के भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल है ।

इसी तरह से पोल्यूशन की बात है । पोल्यूशन की तो यह हालत है कि जहां जहां पर डिसटिलरीज हैं वहां पर पूरा पोल्यूशन है । उसको ठीक करना चाहिये । हिसार के अन्दर बाई पास पर एक डिसटिलरी बनी हुई है और उस बाईपास पर चढ़ने पर ही बदबू आने लगती है और दूर-दूर तक अगर पूर्व की हवा चल जाए

[चौधरी बंसी लाल]

तो सारा शहर सो नहीं सकता और अगर पश्चिम की हवा चल जाए तो कैन्ट और आस पास के गांव वाले सो नहीं सकते । इसलिये उस डिसटिलरी को वहां से शिफ्ट करना चाहिये । वहां पर बहुत बड़ा कैन्ट बनना था और इसीलिये आर्मी वाले उस कैन्ट को बनाने के लिये आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उस डिस्टिलरी से वे परेशान हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से डिवैल्पमैंट की बात है । डिवैल्पमैंट का कोई काम नहीं हो रहा है । सड़कों की कोई मुरम्मत नहीं हो रही है । सरकार कहती है कि हमने सड़कों की बड़ी मुरम्मत की है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में खुद माना है । पैरा 23 में सरकार ने बताया है कि 7538 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत की गयी है और 831 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया गया है और सुधारा गया है । हरियाणा में सड़कें तो 22, 23 हजार किलोमीटर हैं तो क्या इतनी 7538 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत और 831 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने से सब कुछ ठीक हो गया है ? यह सारी परफारमैन्स सरकार साढ़े तीन साल की स्वयं मानती है । तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि सड़कों की मुरम्मत सारी स्टेट में कब तक करवा देंगे । स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि मुख्यमन्त्री ने पहले ही जुलाई सैशन में कहा था कि 31 मार्च 1992 तक सभी सड़कों की मुरम्मत हो जाएगी तो मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि उनके उस वायदे का क्या हुआ ? क्या सारी सड़कों की मुरम्मत हो गयी है ?

स्पीकर साहब, आज तक जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं चाहे नहरों का हो, चाहे प्राईमरी ऐजुकेशन का हो, चाहे किसी और बात का हो, हर चीज में वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है । मैं मुख्यमन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर अब तक हरियाणा सरकार ने चाहे कोई कारपोरेशन है, इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड हो, कितना कर्जा आज तक वर्ल्ड बैंक से लिया गया है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रदेश को ऐसा कर्जदार बना दें कि आगे उनके पास चुकाने के लिये उस पैसे का ब्याज तक भी न हो ।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, रोडवेज की हालत है । पीपे उड़े पड़े हैं । और रोडवेज ऐक्सप्रैस के नाम से 20 या 25 परसैन्ट ज्यादा किराया लोगों से ले रही है । बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां आर्डीनरी बसें जाती ही नहीं, सिर्फ ऐक्सप्रैस बसें ही जाती हैं । सरकारी मुलाजिम अगर टूर पर जाता है, तो वह ऐक्सप्रैस बस में ही जाता है आर्डीनरी बसें अवेलेबल नहीं हैं और उसको सरकार आर्डीनरी का किराया देती है । बाकी का वे अपने घर से भुगतता है । इसलिये सरकार इस बात का ध्यान रखे कि आर्डीनरी बसें भी ऐक्सप्रैस के साथ साथ चलाई जाएं ताकि आम

आदमी को सुविधा हो सके क्योंकि साधारण आदमी तो आर्डीनरी बस में ही जाना पसन्द करेगा । इसका कारण यह भी है कि आजकल किराये भी बहुत बढ़ गये हैं । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज के ड्राईवर्ज ऐक्सीडैंट बहुत करते हैं । उनको हर तीन या छः महीने के बाद, जितना भी सरकार मुनासिब समझे, रिफ्रैशर कोर्स करवाया जाए । उनको ट्रेनिंग दी जाए । वे हर रोज पांच-दस बसों को तोड़ देते हैं । इसलिए उनको कोर्स करवा कर सिखाने और बताने के लिए सरकार को कोई सिस्टैमैटिक प्रोग्राम बनाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, हस्पतालों के अन्दर डॉक्टर नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं । इक्विपमैंट अगर हैं, तो वे खराब पड़े हैं । उनको कोई ठीक करवाने वाला नहीं है । हमारे मैडिकल कालेज में अच्छे डाक्टर नहीं हैं । जितने सीरियस केस मैडिकल कालेज में आते हैं, वे सारे केस दिल्ली को रैफर कर दिए जाते हैं । दिल्ली पहुंचते-पहुंचते मरीज की हालत खराब हो जाती है या वह मर जाता है । इसलिए रोहतक के मैडिकल कालेज के लिए स्पैशल रिक्रूटमैंट की जाए । बाई नैगोसिशन की जाए । अच्छे-अच्छे डाक्टर्ज मैडिकल कालेज के लिए लाने चाहिएं । उसमें चाहे आप ऐज की रिलैक्सेशन कर दें । डाक्टर जितनी तनखाह मांगे, उतनी आप उसे दे दें मगर मैडिकल कालेज का स्टैंडर्ड ऊंचा कर दें । वहां पर इक्विपमैंट बहुत है लेकिन डाक्टर इस्तेमाल नहीं होता । वहां से अच्छे-अच्छे डाक्टर चले गए । जैसे डाक्टर मढ़िया ऐसे सर्जन थे, जिनसे लोग दूर-दूर से आप्रेशन करवाने आते थे । उस समय कई केस दिल्ली और बम्बई वाले डा० मढ़िया को रैफर किया करते थे । सरकार को चाहिए था कि उनको पांच साल की एक्सटैन्शन दे देती और उनका डैजिगनेशन चेंज कर देती । इसी तरह से डा० श्रीवास्तव भी ऐसे ही रिटायर हो गए । मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी खुद इसको देखें और मैडिकल कालेज के लिए अच्छे-अच्छे डाक्टर लाएं । चाहे वे जितनी भी तनखाह मांगे, वह उनको दें । अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कालेज में जो दाखिला होता है वह स्कैंडलस है । इंटरव्यू के समय 'यैस' और 'नो' पर टिक मार्क करनी पड़ती है । जिसको सिलैक्ट करना हो, उसके आगे 'यैस' की टिक मार्क कर देते हैं और जिसकी छुट्टी करनी हो, उसने चाहे कितना बढ़िया पर्चा किया हो, उसके आगे 'नो' टिक मार्क करके उसकी छुट्टी कर देते हैं । जो फौजियों की सीट्स रिजर्व हैं, उनकी तो लिस्ट तीन-चार महीने के बाद लगाई गई । उनको इम्तिहान देना मुश्किल हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी बहुत से गांवों में नहीं है । कई गांव ऐसे हैं, जिनमें दो-दो साल से पानी नहीं गया । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि सभी जगहों पर रोजाना 40 लिटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी दिया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, 40 लिटर की बात तो बाद में रही, मैं मुख्य मन्त्री जी को आपके जरिए कहूंगा कि जो 10-15 लिटर मिलता था, वह तो दे दो । गांवों

[चौधरी बंसी लाल]

की बात दूर है, लेकिन जो शहर हैं, जैसे झज्जर, रिवाड़ी, होडल, कैथल, नारनौल और अम्बाला, इन बड़े-बड़े शहरों में पीने का पानी पोटेबल नहीं है । वहां पीने का पानी खारा है । इसलिए इस चीज को प्रायरिटी देनी चाहिए । जो कुछ पहले का कर रखा है, कम से कम उसको तो मेनटेन कर लो लेकिन उसको भी नहीं किया जा रहा है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यमुना नगर के शूगर मिल और पेपर मिल का सीवरेज का पानी वैस्टर्न यमुना कैनाल में पड़ता है । उस पानी को इस्तेमाल करने के बाद बहुत सी वाटर बौर्न बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता इसलिए वे बीमार हो जाते हैं । उस पानी को नदी में डालने से पहले सरकार उन मिलों के मालिकों को ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के लिए कहे । सरकार इस बारे में सख्ती से काम करे । जब तक सरकार सख्ती से काम नहीं करेगी तब तक काम नहीं चलेगा ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का टाईम 10 मिनट और बढ़ा 14.00 बजे | दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का टाईम 10 मिनट और बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हरिजन और बैकवर्ड भाईयों के वैल्फेयर की चर्चा की गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सरकार के आने के बाद नौकरियों में जितने आदमी लगाए गए हैं, उन सभी नौकरियों में चाहे वह ए0 एस0 आई0 की पोस्ट है, चाहे कांस्टेबल की पोस्ट है, चाहे एच0 सी0 एस0 की पोस्ट है और चाहे एक्साईज इंस्पैक्टर की पोस्ट है या चाहे दूसरी पोस्टें हैं, उनके अन्दर क्या हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों का रिजर्व कोटा पूरा किया गया है क्योंकि मुख्य मंत्री जी हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों की बड़ी वकालत करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक बात यह कही है कि एक अप्रैल से लाटरी

की टिकटें बिकना बंद कर देंगे । बाहर की लाटरीज की जो टिकटें बिकेंगी, उन पर 20 परसट सेल्ज टैक्स लगेगा । अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि लाटरी फौरन बंद होनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि बाहर की लाटरी हमारे यहां पर क्यों बिके ? अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपको भी मालूम होगा और शायद मुख्य मंत्री जी को भी मालूम होगा कि हरियाणा में इस लाटरी की तकलीफ के कारण तीन-चार आदमियों ने खुदकशी कर ली इसलिए इसको बिल्कुल ही बंद किया जाना चाहिए । इन्होंने एक बात यह कही कि हरियाणा में बार बंद कर दिए गए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि इस शराब को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए । हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन के डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज में आर्टीकल 47 में शराब को बिल्कुल बंद करने को कहा गया है । इसलिए इसको बिल्कुल ही बंद कर दें ।

हरियाणा प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनके बारे में भारत सरकार का 26-27 साल पुराना फैसला है कि जहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी उनमें टैक्नीकल हैड को छोड़ कर बाकी सब के सब मजदूर लोकल लिए जाएंगे । उस फैसले का इंडस्ट्रीयलिस्ट्स पालन नहीं कर रहे हैं । उस फैसले का पालन सरकार को सख्ती से करवाना चाहिए ताकि लोकल आदमियों को इंडस्ट्रीज में काम मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय, मजदूरों को बहुत तकलीफ है क्योंकि उनके राशन कार्ड नहीं बनते हैं । न उनको मजदूरी पूरी मिलती है और न उनके रहने के लिए मकान बनाए गए हैं । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्लांट लौड फैक्टर कितना है। फरीदाबाद और पानीपत में टोटल कितने थर्मल प्लांट लगे हुए हैं । जितने थर्मल प्लांट लगे हुए हैं, उनमें से कितने चल रहे हैं और कितने बंद पड़े हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में यह चर्चा हुई थी कि थर्मल प्लांट्स में कोयला घटिया आया है। कोयला जरूर घटिया आता होगा, मैं इस बात को चैलेंज नहीं करता कि कोयला घटिया नहीं आता लेकिन आपके पास इंजीनियर्ज बहुत सरप्लस हैं । उनको आप कोल हैड पर बैठा दें । अगर इस बारे में जरूरत पड़े तो वहां की सरकार से इस चीज की इजाजत ले लें और जरूरत पड़े तो उनकी प्रोटैक्शन के लिए हरियाणा की पुलिस उनको दे दें क्योंकि वहां पर लोग गुण्डागर्दी बहुत करते हैं । अगर कोयला अच्छा आएगा तो बिजली पूरी पैदा होगी ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि बिजली पैदा करने में बड़ी इम्प्रूवमैंट की है । इम्प्रूवमैंट कहां हुई है ? गांवों में दो-दो तीन-तीन दिन बिजली नहीं जाती है । कई-कई गांवों में तो बिजली हफ्ता-हफ्ता तक नहीं जाती

[चौधरी बंसी लाल]

है। शहरों में आप देखते हैं कई बार बिजली चली जाती है। पता नहीं, बिजली की इम्प्रूवमैंट कहां पर हुई है ? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात की चर्चा है कि इजराइल के साथ आपका कोई एग्रीमैंट हुआ है। इस बारे में पिछले सैशन में भी चर्चा हुई थी। मैंने उस समय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि आप उस एग्रीमैंट की कापी दिखा दें। उस वक्त मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब फाईनल हो जाएगा तो आपको वह दिखा देंगे। अब तो उस एग्रीमैंट के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी चर्चा है, इसलिए अब तो आप हमें उस एग्रीमैंट की कापी दिखा दें। बिजली के रेट एक साल में दो बार बढ़ाए गए। यह किसान, एक साधारण व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के साथ ज्यादती है। यह रेट सोच-समझ कर बढ़ाने चाहिएं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि रेट बढ़ाने से पहले सदन की एक कमेटी बैठा दें जो इन चीजों को देखे कि बिजली बोर्ड को कितना घाटा है और कितना रेट बढ़ाना ठीक है। साथ ही रेट बढ़ाते समय इस बात का ध्यान भी रखा जाये कि कितनी लाईन लौसिज हैं। इस काम के लिए हाउस की एक कमेटी बना दें, तो अच्छा रहेगा। यदि ऐसा नहीं करना तो 4-5 फाइनैंशियल कमिशनर्ज की एक कमेटी चीफ सैक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप में बना दें जो इन सारी चीजों का पता लगा सके।

अध्यक्ष महोदय, आज के दिन डिवैल्पमैंट का काम हो ही नहीं रहा है। जो पुराने डिवैल्पमैंट के काम हो चुके हैं, उनकी मुरम्मत ही पूरी नहीं हो पा रही तो फिर नए डिवैल्पमैंट के वे क्या काम कर पाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय, आज के दिन चोरियां, डकैतियां, बरगलरी, रेप और मर्डर के केसिज हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इस तरफ कम ध्यान दे रही है। यह क्यों हो रहा है ? उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो पुलिस वाले हैं, उनमें बहुत सी जगह पर तो पुलिस वाले ही मिलकर यह काम करवाते हैं क्योंकि वे सिफारिश से या पैसा देकर भर्ती हुए हैं। उनको अपना दिया हुआ पैसा पूरा करना होता है, इसलिए वे ऐसा काम करवाते हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इस तरफ खुद मुख्य मंत्री महोदय तवुज्जह दें और पुलिस वालों की यूनियन बनाने की मांग को माना जाना चाहिए ताकि इन घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में जलियांवाला कांड की 75वीं वर्ष गांठ मनाने की बात कही गयी। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि आज तो सारे हरियाणा में जलियांवाला कांड हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन वाले चाहे निसिंग में, चाहे टोहाना में या नारनौंद में रैली करें, पुलिस फायरिंग होती है और आदमी मरते हैं। इन घटनाओं में जो लोग मरे हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी जुडिशियल इन्क्वायरी

करवाये ताकि असलियत का पता चल सके । अभी पिछले दिनों नारनौद में जो कुछ हुआ, वह कोई अच्छी बात नहीं है । वहां पर एक लड़का पुलिस की गोली से मारा गया और गोली ने उसके सिर को उड़ा दिया लेकिन मुख्य मंत्री कहते हैं कि वह पुलिस की गोली से नहीं पत्थर लगने से मरा है । पुलिस की कस्टडी में जितनी मौतें होती हैं, इसके लिए जुडिशियल इन्क्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाये ।

पंचायतों के इलैक्शन के बारे में ये कहते हैं कि हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इलैक्शन करवा दिये । कहीं तो इलैक्शन डिक्लेयर करा दिए, कहीं सिक्रेट बैलट से इलैक्शन करा दिए । कहीं हाथ खड़े करा कर करा दिए । कहने का मतलब यह है कि सरकार को जैसा सूट किया, उसी हिसाब से इलैक्शन करवा दिए । फरीदाबाद जिले के बारे में लीडर आफ दी अपोजीशन ने बताया कि वहां पर जिला परिषद के लिए जो उम्मीदवार चुना गया था, उसको मार दिया । ये जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कोई अच्छी बात नहीं है । यह कौन से सिद्धांत की बात है कि सिवानी में 3-4-5 आदमियों ने दस्तखत कर दिए कि फलां आदमी चेयरमैन और वाईस चेयरमैन है । जब वहां पर प्रिजाइडिंग आफिसर गया, तो उसने कहा कि यह चेयरमैन है और यह वाइस चेयरमैन है । लोग कहने लगे कि इलैक्शन करवाओ तो कहा गया कि इलैक्शन तो हो चुका । बहुत सी जगहों पर पंचायतों और म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव में एक्स्ट्रा कांस्टीच्यूशनल पावर मिसयूज किया जा रहा है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 5 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब आप 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल :- अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि स्टेट में कम्युनल हारमनी बनी रही है, लेकिन कम्युनल हारमनी स्टेट में कहां है ? यहां जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जातिवाद का जहर फैला हुआ है । रणबीर सिंह सुहाग की हत्या रोहतक में हुई । मुख्य मन्त्री जी जवाब देते हुए कह देंगे कि इसकी इन्क्वायरी सी0 बी0 आई0 के पास है । इस इन्कवायरी से पहले उसने रोहतक की पुलिस के पुलिस कप्तान को लिख कर दिया था कि उसको जान का खतरा है । लिख कर देने के बाद भी उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली । राजस्थान के गंगानगर जिले तक हरियाणा पुलिस सिक्योरिटी देती रही है लेकिन रणबीर सिंह सुहाग को पुलिस सिक्योरिटी नहीं दी गई । कल परसों के अखबार में छपा था कि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के बहुत से प्रोफैसर्ज अपनी प्रोटैक्शन के लिए हथियार मांग रहे हैं और उन्होंने इसके लिए दरख्वास्तें दी हैं । स्पीकर साहब, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है ? कल प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने हाउस में कहा मोडस अपरेंडी हर जगह एक जैसी नहरों में मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, आखल थाने में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसको यातना दी गई । करनाल में दो छोटे बच्चों का अपहरण करके उनको मार दिया गया और उसी दुख में बच्चों के बाप ने भी खुदकशी कर ली । अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य में कहीं कोई कानून-व्यवस्था है ? पाई हल्के में प्योदा गांव की 12 वर्षीय हरिजन बालिका के साथ 28 फरवरी को बलात्कार किया गया था, उस बारे कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई । अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में 28 फरवरी को 2 सिपाहियों ने शौच के लिए जाती हुई महिला के साथ कुकर्म करने की कोशिश की थी । रोहतक जिले में मकरौली गांव में ईंटों के भट्टे पर महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ । यह वारदात 2 फरवरी की है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । महिलाओं के पतियों को पुलिस थाने में बुला कर धमकाया गया और यह कहा गया कि अगर तुमने गुण्डों का मुकाबला किया तो बुरा हश्र होगा । 16 फरवरी को बहादुरगढ़ में 8 वर्षीय लड़की पूजा का अपहरण किया गया और जब मुलजिम उससे बलात्कार करने लगा तो लड़की ने शोर मचाया और उस लड़की को वहां पर मार दिया गया । एक मार्च को गांव भालकी जिला रिवाड़ी में 2 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जिस की रिपोर्ट तीन दिन बाद दर्ज की गई लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं । गांव मानपुर जिला फरीदाबाद में 15 वर्षीय लड़की संतोष का अपहरण हुआ । 3-4 मार्च को फरीदाबाद में पुराने फरीदाबाद चौक पर एक डाक्टर दम्पति को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के गनमैन ने वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में जमकर पीटा । 2 मार्च की रात को एक डी0 एस0 पी0 ने एक कांस्टेबल की पिटाई की । डिगावे की फटिलाईजर का केस यहां पर आया । अध्यक्ष महोदय, वह केस इस तरह से है कि उसमें मुलजिमों को सजा देनी चाहिए मगर अब दिल्ली की पुलिस आई और उन्होंने आ कर सौदा किया ।

दिगावा के बेगुनाह व्यापारियों ने डी0 सी0 और पुलिस कप्तान से इस बारे में कहा। डी0 सी0 ने कहा कि उन्हें रंगे हाथों पकड़वा दो, उसने नोटों के नम्बर लिखवा दिए। जब दिल्ली की पुलिस के आदमियों को रिश्वत दी गई तो उन्हें पहले ही पता लग गया कि उन्हें पकड़ने का प्रयत्न हो रहा है, इसलिए उनको भगा दिया। भागते हुए एक आदमी को मण्डी के दुकानदारों ने पकड़ लिया। डी0 एस0 पी0 लोहारु ने उनको पहले ही बता दिया था। अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह से पुलिस वाले ही रिश्वत को प्रोटैक्शन देते हैं, तो कौन क्या करेगा? पिंजोर में ब्लॉक समिति के चेयरमैन व सरपंच की हत्या हो गई और पुलिस के अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय 'सहारा' अखबार की एक छोटी सी कटिंग पढ़ कर मुख्य मंत्री जी को सुना देता हूं। फरीदाबाद, प्रवर पुलिस अधीक्षक * * * के निवास स्थान के बाहर कल शाम से खड़ी नई-नवेली कण्टैसा कार लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सफेद रंग की कार पर अस्थाई नम्बर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कण्टैसा कार फरीदाबाद पुलिस ने अपने पुलिस महा निदेशक * * * (विघ्न) "अरोड़ा" तो वह गलती से लिख गया। लक्ष्मन दास के बेटे की शादी में देने के लिए खरीदी है। इसके लिए बाकायदा हर पुलिस थाने में प्रभारी एवं चौकी इन्चार्ज को अपना हिस्सा देने के लिए कहा गया। (विघ्न) इस श्रृंखला में बल्लभगढ़ पुलिस की भी भूमिका है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो आदमी हाऊस में अपने आपको डिफैन्ड नहीं कर सकता है उसका नाम लेना ठीक बात नहीं है। उनको कार चाहे किसी ने दी है या उन्होंने अपने आप खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम कार्यवाही से एक्सपंज किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बंसी लाल जी ने जो नाम लिये हैं, उनको कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, नाम ही एक्सपंज करवाएं, बाकी सब रहने दें। इधर फरीदाबाद की दुधारी ट्रक यूनियन ने पुलिस के इशारे पर * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *

अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में 10 मार्च, 1993 को पुलिस की कस्टडी में मौत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो लाख मुआवजा देने के लिए हुक्म दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डी0 जी0 पी0 से कन्सर्ड जो भी बात है, वह कार्यवाही से निकाल दें।

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप नाम निकलवा दें लेकिन डैजिगनेशन तो नहीं निकलना चाहिए ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो सदन का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 5 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जमुना नगर में भी पुलिस कस्टडी में एक आदमी की मौत हुई, उसके लिए सरकार ने पिछले 2-3 महीने से कोई कार्यवाही नहीं की । परसों ही केस रजिस्टर किया है क्योंकि विधान सभा का सैशन चल रहा है । इस केस को 342 और 304-ए के तहत दर्ज किया है । अध्यक्ष महोदय, रोहतक में भी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई । यह जो चीजें हो रही हैं, इससे कोई ला-एंड-आर्डर की स्थिति सुधरेगी नहीं । अध्यक्ष महोदय, सुशीला कांड के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि यह केस सी0 बी0 आई0 के पास है । अध्यक्ष महोदय, यह केस सी0 बी0 आई0 के पास बाद में गया है, पहले यह केस हरियाणा पुलिस के पास था । इस बारे में पूरा हिसार शहर और जिला मुजरिमों के नाम ले रहा था लेकिन उस वक्त पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । अध्यक्ष महोदय, नारनौल में इन्होंने एक लड़के को ही नहीं मारा, बल्कि वहां पर बहुत से लोगों को पीटा है और उसके बाद उनके ट्रैक्टरों को भी तोड़ डाला है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ला-एंड-आर्डर नाम की कोई भी चीज कहीं पर नहीं है । मुख्य मंत्री जी ला-एंड-आर्डर खुद सुपरवाईज करें । अगर ऐसा ही चलता रहा, तो काम नहीं चलेगा । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहता हूं । अगर आप थोड़ा सा और समय बढ़ा दें तो मैं वह भी बोल दूं । मेरा एक हरियाणा सरकार को सुझाव है कि ये अपना एक्सपैंडीचर घटाएं । आप हर डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियों का सरकारी पूल बनवा दें । जिसको भी गाड़ी की जरूरत हो, वह लॉग-बुक में भर दे कि किस काम से जाना है और वह गाड़ी ले जाए । आज क्या होता है कि

सरकारी गाड़ियां सब्जी मण्डी के आगे खड़ी होती हैं, तो कभी किसी स्कूल के आगे खड़ी होती हैं। यह जो गाड़ियों और टैलीफोनों का मिस-यूज होता है, अगर आप इसको घटाएंगे तो सरकार का फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डिस्ट्रिक्टस में गाड़ियों के पूल बना दिए हैं। जिसको भी सरकारी काम-काज के लिए गाड़ियां चाहिएं, वह ले लें। अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजों पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर आपका धन्यवाद करता हूं।

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Hon'ble Speaker, I seek the permission to move a motion. Prof. Chattar Pal Singh was deliberately obstructing the proceedings of the House and persistently dis-obeying the orders of the Chair. Therefore, I seek your permission to move a motion regarding suspension of Prof. Chhattar Pal Singh from the House and suspension of Rule 104 also.

I beg to move—

> That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding suspension of Prof. Chhattar Pal Singh.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding suspension of Prof. Chhattar Pal Singh.

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां) : स्पीकर सर, नेहरा साहब जो प्रस्ताव लेकर आए हैं मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की मैजोरिटी है, इसलिए वह आज जो चाहे वह काम कर सकती है लेकिन यह कोई हैल्दी ट्रैडीशन नहीं होगी। आज ही गवर्नर ऐड्रैस पर बहस शुरु हुई है और जब सदस्य अपना कोई इशू उठाना चाहते हैं, तो कम समय के कारण उनको अपनी बात कहने का समय ही नहीं मिलता। छः महीने के बाद अधिवेशन शुरु होता है। आनरेबल मैम्बर, पहले भी इसी सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए उनको ज्ञान भी है, वे पढ़े लिखे भी हैं और कालेज में प्रोफैसर भी रहे हैं। वे अपनी बात को ही उठा रहे थे। जब आदमी को अपनी बात रेज़ करने का मौका नहीं मिलता, तो वह उतावला हो जाता है इसलिए इस तरह का वातावरण बना है। इस सदन का सदस्य होने के नाते और पब्लिक रिप्रैजेंटेटिव होने के नाते उस मैम्बर का यह कांस्टीच्यूशनल राईट है कि वह अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को एवं सरकार की बुराईयों को विधान सभा में उठाए। लेकिन सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिलता क्योंकि शोर्ट अधिवेशन होता है। सर, आप देखिए कि इस सैशन में भी केवल 13 ही सीटिंग्ज़ हैं। कल भी नोन-औफिशियल-डे आ गया है और परसों मुख्य मंत्री जी ने अपना रिप्लाई देना है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस तरह से गवर्नर ऐड्रैस पर भी सही मायने में एक ही दिन डिस्कशन के लिए मिला । परसों मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई होने के कारण किसी को भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा । स्पीकर सर, इस तरह के हालात तो खुद सरकार ही क्रिएट करती है इसलिए उस मैम्बर को मजबूर होकर आपके सिंहासन तक आना पड़ा था लेकिन ऐसी परिस्थितियां खुद रूलिंग पार्टी ने क्रिएट की थीं । मैं यह ऐडमिट करता हूं कि वैसे यह सब अनफोर्चुनेट था । इसलिए सर, सरकार को ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए थे । पार्लियामैंट के अंदर भी यह परम्परा रही है कि अधिवेशन को बुलाने से पहले इसके बारे में विपक्षी पार्टियों के लीडर्ज से डिस्कशन किया जाता है । मुख्य मंत्री जी तो वहां पर रहे हैं, इसलिए उनको यहां पर भी हैल्दी ट्रैडीशन डालनी चाहिए । लेकिन यहां पर तो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने से पहले ही सब कुछ डिसाईड हो जाता है । स्पीकर सर, अगर यहां पर भी पार्लियामैंट की तरह हो, तो इस तरह के हालातों से बचा जा सकता है । यह जो नेम या सस्पैंशन की बात आती है, यह टाईम की शोर्टेज के कारण आती है । आप भी बी० ए० सी० में सब कुछ सैटल होने के कारण बंधे हुए हैं, इसलिए आप उससे आगे सरक नहीं सकते । इसलिए ऐसे मौके आना तो स्वाभाविक ही है । स्पीकर सर, मैं यह कहूंगा कि अगर सदस्य इस तरह की उत्तेजना की बात करते हैं तो यह नहीं होना चाहिए कि उनको ससपैन्ड कर दिया जाए । आप उनको वार्निंग भी दे सकते हैं कि इस तरह से आगे से नहीं होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब यह गलत प्रथा डाल रहे हैं । इसकी बैकग्राउंड है । कल चौटाला साहब ने प्वायंट आउट किया था कि खुद मुख्य मंत्री ने कहा कि उसको (छत्तरपाल) नेम कर दें । इसका मतलब क्या है ? यह किसी विधायक की आवाज को बंद कर रहे हैं । यह अनडैमोक्रेटिक है । डैमोक्रेसी का कत्ल है । हम यह चाहते हैं कि आप इस कदम को रोकें । यह तो षड़यन्त्र है ।

वैल प्लान्ड कदम है। पहले से तय किया हुआ कदम है। स्पीकर सर, इस तरह की बात आप रोकें। आप गवर्नमैंट को डायरैक्शन दें कि इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाए वरना ....

श्री मोहम्मद अस्लम खान : अध्यक्ष महोदय, 1987 में इनकी सत्ता में पार्टी आई थी उसमें हम पांच मैम्बर चुनकर आए थे। एक तो छोड़कर चले गए थे। दो आते नहीं थे। मैं और महेन्द्र प्रताप दो ही मैम्बर आया करते थे। महेन्द्र प्रताप को बोलने की बिनाह पर ही ससपैंड कर दिया गया और मैं वाक आउट कर गया था। यह तो इनके हालात थे। और आज ये कह रहे हैं कि इनको ससपैंड न किया जाए। यह बहुत गलत बात है।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफैयर्ज मिनिस्टर जो प्रस्ताव लाए हैं। मैं यह समझता हूं कि इस प्रस्ताव के लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में जो पार्टी सरकार में बैठी हो, उसको कुछ अन-कन्वीनियंट बातें तो सुननी पड़ेंगी। उसके बगैर काम नहीं चलता। हो सकता है, इनको सब बातें इनकन्वीनियैंट लगती हों। किसी भी बिजनैस के लिए दिन मुकर्रर नहीं होते, जैसे अपने यहां होते हैं। किसी भी बिजनैस के लिए पार्लियामैंट में घण्टे मुकर्रर होते हैं, जैसे फलां चीज की डिसकशन पर इतने घंटे लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह है कि वह प्रथा यहां फौलो नहीं कर रहे हो। उसका नतीजा यह होता है कि बिजनैस रुक थ्रू करते हैं। हर मैंबर को अपनी कांस्टीच्यूएंसी के बारे में बात कहनी होती है।

श्री अध्यक्ष : टाईम तो हम अपोजीशन को ज्यादा देते हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, 90 मैंबर हैं। हर मैंबर को अपनी बात कहने का अधिकार है। परन्तु छत्तर पाल सिंह को आपने बोलने की इजाजत नहीं दी। वह बार-बार खड़ा हुआ। आदमी पेशेन्स खो बैठता है। उन्होंने गलती की, तो आप उनको चैंबर में बुलाकर समझा दें कि आइन्दा ऐसी गलती न करें। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमैंट को यह प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय 5 मिनट तक के लिये बढ़ाया जाता है।

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, सदन में चेयर की गरिमा रहनी चाहिये । आपके प्रति हमारा सब का आदर व श्रद्धा होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आप पांच मिनट में ही समाप्त करें ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, आज जो नेहरा साहब प्रस्ताव लेकर के आए हैं, यह बात ठीक है परन्तु प्रजातन्त्र में सरकार के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि वह कटुता को कम करे । विपक्ष की एक अनप्लेजैन्ट सी भूमिका होती है । नेहरा साहब बड़े विद्वान हैं । पार्लियामैंट्री अफेयर्ज के मिनिस्टर हैं । वे ऐसे मैम्बर को सस्पैंड करने का प्रस्ताव लेकर के आए हैं जो कल इन्हीं के मन्त्रिमण्डल के नवरत्नों में से एक थे । कल के इनके मंत्रिमण्डल में बराबर के मन्त्री महोदय होते थे लेकिन आज पता नहीं किस कारण से, कोई बात हो गई है, जो इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं । दूसरा मुद्दा जो उन्होंने यहां सदन में उठाया था, उस मुद्दे पर बोलने की उसे इजाजत भी दी गई थी । अध्यक्ष महोदय, छतर पाल सिंह जी एक नौजवान और अनमैरिड हैं । कोई तो रियायत उन्हें मिलनी ही चाहिये । कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिये । मैंने शुरु में ही निवेदन किया था कि यह जो दाढ़ी वाले लोग कुछ बचे हैं, कुछ ने तो डर के मारे दाढ़ी कटवा दी है जैसे कैप्टन अजय सिंह जी हैं, भाई शकरुल्ला खां ने भी दाढ़ी छंगवा दी है कुछ मेरी बिरादरी के लोग बचते हैं, उन पर यह कुल्हाड़ी क्यों चलाई जा रही है (हंसी) यह जो सस्पैन्शन वाली बात है, यह होनी नहीं चाहिये । उन्होंने आपके आर्डर्ज की कोई अवहेलना नहीं की है । आज भी वे एक बात को उठा रहे थे और मुख्य मन्त्री महोदय ने उसका उत्तर भी दे दिया था । वह अपनी बात को नहीं कह पाए । फिर भी सदन में इस तरह की ऐसी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई मन्शा नहीं थी । उनकी तरफ से सौरी फील किया जा सकता है । यह मसला बड़ा ही अनफारचुनेट होगा यदि यह सस्पैंशन का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा । यह बड़ा ओड सा लगता है । स्पीकर साहब, जिस सदन के आप स्वयं कस्टोडियन हों । आप किसान हैं और शिक्षा से जुड़े हुए आदमी हैं । आप टू इन वन हैं, सर । यह बात आपके खाते में जुड़ती है । इसलिये मेरी हम्बल रिकवैस्ट है कि आप सरकार से कहें कि इस रैजोल्यूशन को वापिस ले लें ताकि हाउस का वातावरण ठीक तरह से चलता रहे । नेहरा साहब अपने इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कल भी इस बात का अन्देशा था इसीलिये मैंने आपकी रूलिंग चाही थी । मुख्य मंत्री महोदय ने

कल इस सम्मानित सदस्य के बारे कहा था कि इसको नेम किया जाए और मैंने इस पर आपकी राय जाननी चाही थी । अध्यक्ष महोदय, अभी तो सैशन की केवल तीन ही सिटिंग्ज हुई हैं, अभी तो 10 बाकी हैं । यह बड़ा ही अन-डैमोक्रेटिक तरीका होगा, यदि यह मैजोरिटी के बल बूते पर यहां पर अपनाया गया और यह मैम्बर के अधिकारों पर एक तरह से कुठाराघात होगा । ये इस रैजोल्यूशन को मूव करते हुए कहते हैं कि यह तो आपके हुक्म की उल्लंघना करते हैं । अगर आप समझते हैं कि किसी सदस्य ने आपके हुक्म की अवहेलना की है, आपके ऊपर कोई आक्षेप किया है तो यह आपको ही केवल अधिकार है कि आप उसको सजा दे सकते हैं । नेम कर सकते हैं । अपने चैम्बर में बुलाकर उसे समझा सकते हैं । आप उससे माफी मंगवा सकते हैं लेकिन मैजोरिटी के बलबूते पर यह रैजोल्यूशन लाने का कोई औचित्य नहीं है । आप जो चाहें, इनसे करवा सकते हैं । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि कहीं यह गल्त परम्परा कायम न हो जाए । अगर ऐसा हो गया तो प्रजातन्त्र का खुल्लम-खुल्ला हनन होगा और इस प्रजातन्त्र में इस बात को कोई भी बरदाश्त नहीं करेगा । इस तरह से प्रजातन्त्र का हनन हो, शायद आप भी यह बात नहीं चाहेंगे । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं इस मामले को अपने हाथ में लें और यह जो रैजोल्यूशन यहां पर लाया गया है, यह विद-ड्रा होना चाहिये । आप जो निर्णय लेंगे, वह सब को मान्य होगा । इस हाउस को भी मान्य होगा । धन्यवाद ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति यहां हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुई । अगर माननीय सदस्य यहां किसी बात के लिए डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है । वे लिख कर देते हैं और अगर आप उस नोटिस को एडमिट कर लेते हैं तो उस पर डिस्कशन भी हो सकती है और गवर्नमैंट

[चौधरी जगदीश नेहरा]

अपनी स्पष्टीकरण भी दे सकती है । लेकिन आज की स्थिति और है । पहले तो प्रो० साहब वहां अपनी सीट पर अखबार लहरा रहे थे फिर यहां वैल आफ दी हाउस में आ गए । आप द्वारा कितनी बार कहने के बावजूद भी वे यहां से नहीं हटे । हमें यह सारी स्थिति देखकर हैरानगी हुई । ये प्रोफैसर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं । ये हमारे पहले भी साथी थे और अब भी हैं । लेकिन इन द्वारा इस तरह का भद्दा प्रदर्शन करने की बात ठीक नहीं है । कल भी प्रोफैसर साहब ने इसी तरह से डैरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे । मैं उस समय उठना चाहता था लेकिन बीच में बात चली गई । तो इस हिसाब से तो कल को भी ऐसी स्थिति आएगी और परसों भी आएगी । तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । जो आदमी मिनिस्टर रहा हो, और प्रोफैसर रहा हो, वह आपके आर्डर्ज के खिलाफ लगातार खड़ा रहे, तो यह ठीक बात नहीं है । जब आप किसी को बोलने की इजाजत देते हैं, वह तभी बोलता है । किसी समय जब आप खड़े हो जाते हैं, तो हम सब बैठ जाते हैं । लेकिन इनको आपने कई बार कहा कि आप बैठिए, ये फिर भी नहीं बैठे । तो हम जो करने जा रहे हैं यह कोई प्रजातन्त्र का हनन नहीं है । यह तो डैकोरम कायम रखने का एक सिस्टम है । इस तरह से तो हमारी आपस में लड़ाई हो जाएगी । इन्होंने अपनी बात कहनी है और हमने उसका जवाब देना है । अभी यहां कहा गया कि यदि कोई गवर्नमैंट के खिलाफ बात कहता है तो हमें इनकनवीनिएंस होती है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम इनकी बात सुनते हैं । ये नुकताचीनी कर सकते हैं, लेकिन हाउस अच्छे ढंग से चलना चाहिए । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विपक्ष के लीडरों ने जो बात कही, उनकी बात ठीक हो सकती है लेकिन इस मामले में बात ठीक नहीं है । इसमें किसी किस्म की साजिश की बात नहीं है । हम तो चाहते हैं कि हाउस का डैकोरम कायम रहे । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मोशन को पढ़ा जाए और उसके बाद मैं इसको आगे पेश करूंगा ।

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding suspension of Prof. Chattar Pal Singh

The motion was carried.

वाक-आउट

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, हम एक प्रोटैस्ट फिर वाक आउट करते हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, हम भी इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

प्रो० राम विलास शर्मा : मैं भी वाक आउट करता हूं।

(इस समय उपस्थित विपक्ष (जनता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी) के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन (पुनरारम्भ)

Irrigation Minister (Chaudhari Jagdish Nehra) : I also beg to move—

That Prof. Chhattar Pal Singh be suspended from the service of the House for the remainder of the present Session for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this August House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Prof. Chhattar Pal Singh be suspended from the service of the House for the remainder of the present Session for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this August House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That Prof. Chhattar Pal Singh be suspended from the service of the House for the remainder of the present Session for his misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this August House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M., tomorrow,

*2.39 P.M. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday the 9th March, 1995)

26637—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh